

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



फरवरी 2020

खंड 74 अंक 2

संपादन समिति
राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

छठा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 1

भाषण

भारत की मौद्रिक नीति के सात युग
शक्तिकांत दास 11

लेख

वर्ष 2019-20 में निजी कॉर्पोरेट निवेश :
सुधार के आसार 17

2018-19 में भारतीय विनिर्माताओं के मनोभाव 31

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और केंद्रीय बैंक 41

वर्तमान सांख्यिकी 55

हाल के प्रकाशन 101

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

छठा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

छठा द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज (6 फरवरी 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगे।

- एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर है, जब तक वृद्धि को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, निभावकारी रुख बरकरार रखा जाए।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. दिसंबर 2019 में एमपीसी की पिछली बैठक के बाद, वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीमी, लेकिन भौगोलिक रूप से अलग बनी हुई है। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के बीच, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्चों की भरपाई में उपभोक्ता खर्च में कमी के साथ तीसरी तिमाही की गति के समान 2019 की चौथी तिमाही में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूरो क्षेत्र में, उपभोक्ता विश्वास में कमी

से फ्रांस और इटली के अप्रत्याशित रूप से संकुचित हो जाने के कारण चौथी तिमाही में आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई। यूके में विकास की गति चौथी तिमाही में कमजोर हो गई है, जैसे कि औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में गिरावट से परिलक्षित होता है। कमजोर खुदरा बिक्री के कारण जापान की अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही में कमजोर हो गयी है जैसा कि अक्टूबर में बिक्री कर बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ता व्यय में कमी के रूप में परिलक्षित होता है। जापान में औद्योगिक उत्पादन में मंद वैश्विक मांग के कारण कमी आ गयी है।

3. उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच, चीन की अर्थव्यवस्था 2019 में पिछले 29 साल की तुलना में 6.1 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण घरेलू मांग में गिरावट और लंबे समय तक व्यापार तनाव है। रूस में, उपलब्ध संकेतक औद्योगिक उत्पादन सहजता के साथ 2019 की चौथी तिमाही में गतिविधि की गति में धीमेपन की ओर इशारा करते हैं, यद्यपि निजी खपत ने कुछ सहायता प्रदान की है। ब्राजील में, औद्योगिक उत्पादन में संकुचन और खुदरा बिक्री में गिरावट के कारण गतिविधि धीमी होती दिख रही है। दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था ने तीसरी तिमाही में -0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और चौथी तिमाही में संकुचित होने की भी संभावना है क्योंकि उपभोक्ता निराशावाद के बीच औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और घरेलू खर्च कम ही बना हुआ है।

4. यूएस-ईरान टकराव के कारण जनवरी की शुरुआत में कच्चे तेल और सोने की कीमतों में उछाल आया, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण जनवरी के मध्य से दोनों नरम हो गए। जनवरी के अंत तक, कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। दूसरी ओर, सोने की कीमतें सुरक्षित मांग के कारण जनवरी के अंत तक बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतें प्रमुख निर्यातक देशों से उच्च मांग और आपूर्ति व्यवधानों के कारण बढ़ रही हैं। इन गतिविधियों को दर्शाते हुए, कुछ प्रमुख ईई और ईएमई में मुद्रास्फीति बढ़ गई है।

5. दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में अधिकांश वैश्विक वित्तीय बाजारों में लचीलापन बना रहा क्योंकि अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों में सुधार और सुव्यवस्थित ब्रेक्सिट परिप्रेक्ष्य की संभावना से निवेशकों के मनोभाव बेहतर बने रहे। कोरोनावायरस के फैलाव के कारण बाजारों, खासकर चीन में, विकास की संभावनाओं पर

* 06 फरवरी 2020 को जारी किया गया।

प्रतिकूल प्रभाव के अनुमान ले सभी आई और ईएमई के इक्विटी बाजारों में जनवरी के अंत में मंदी देखी गई। हालांकि, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी बाजारों ने फरवरी की शुरुआत में घाटे की कुछ वसूली की। बॉण्ड प्रतिफल, जो कि निवेशकों के जोखिम की ओर मूड जाने के कारण 2019 के अंत तक अमेरिका में सख्त हो गए थे विशेषरूप से यूएस फेड द्वारा पॉलिसी रेट को अपरिवर्तित रखने और रेपो परिचालन के विस्तार का आश्वासन देने के बाद जनवरी 2020 में सौम्य हो गए। यूरो क्षेत्र में, बांड प्रतिफल जनवरी में नकारात्मक हो गया। कई ईएमई में भी प्रतिफल सौम्य हुआ। मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी बॉण्ड बाजारों को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ सहानुभूति में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के एवज में जनवरी में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। ईएमई मुद्राओं, जो आम तौर पर एक प्रतिपक्षी मूल्यवृद्धि के साथ कारोबार कर रही थीं, उनमें जनवरी के अंतिम सप्ताह से मूल्यहास हुआ है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

6. घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 7 जनवरी, 2020 को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान (एफएई) ने भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2019-20 के लिए 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। अपनी 31 जनवरी की रिलीज़ में, एनएसओ ने मई 2019 के अनंतिम अनुमानों में दिए गए 6.8 प्रतिशत से 2018-19 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि को संशोधित कर 6.1 प्रतिशत कर दिया। आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2018-19 में 6.0 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

7. हाल के संकेतकों की ओर ध्यान देते हुए, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात - निवेश गतिविधि के दो प्रमुख संकेतक - दोनों में नवंबर / दिसंबर में संकुचन जारी रहा, हालांकि पिछले महीने की तुलना में इसकी गति मध्यम थी। केंद्र का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) तीसरी तिमाही में मजबूत बना रहा, जो सरकार की अंतिम खपत द्वारा प्रदान की जा रही घरेलू मांग के प्रति-चक्रीय बफर का संकेतक है। केंद्रीय बजट में दिए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार, तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में केंद्र के राजस्व व्यय की संवृद्धि (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) कम होने का अनुमान है।

8. आपूर्ति पक्ष पर, एक वर्ष पहले की तुलना में 31 जनवरी 2020 तक रबी की बुआई 9.5 प्रतिशत तक अधिक रही है। उत्तर पूर्व मानसून की बारिश सामान्य से अधिक थी। प्रमुख जलाशयों में भंडारण - रबी मौसम के दौरान सिंचाई का मुख्य स्रोत - पूर्ण जलाशय स्तर (30 जनवरी, 2020 तक) का 70 प्रतिशत था, जबकि यह एक वर्ष पहले 45 प्रतिशत था। पहले अग्रिम अनुमानों के आधार पर, बागवानी उत्पादन 2019-20 में 0.8 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। प्याज, आलू और टमाटर के अधिक उत्पादन के कारण 2019-20 में सब्जियों का उत्पादन 2.6 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।

9. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापी गई औद्योगिक गतिविधि में पिछले तीन महीनों में संकुचन में रहने के बाद नवंबर में सुधार हुआ। मुख्य उद्योगों का उत्पादन चार महीने के संकुचन के बाद दिसंबर में सकारात्मक क्षेत्र में लौट आया, जो इसके आठ में से पांच घटक- कोयला; रिफाइनरी उत्पाद; उर्वरक; इस्पात; और सीमेंट से प्रभावित हुए। रिज़र्व बैंक की आदेश बही, माल सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) द्वारा मापी गयी विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) पहली तिमाही में 73.6 प्रतिशत की तुलना में दूसरी तिमाही में 69.1 प्रतिशत तक गिर गया; मौसमी रूप से समायोजित सीयू भी 73.3 प्रतिशत से 70.3 प्रतिशत पर आ गया। रिज़र्व बैंक का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण 2019-20 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली कमजोर मांग स्थितियों की ओर इशारा करता है। रिज़र्व बैंक की व्यावसायिक अपेक्षाओं का सूचकांक चौथी तिमाही में सुधार का सुझाव देता है। यह जनवरी 2020 के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक के सूचकांक (पीएमआई) द्वारा पोषित है, जो उत्पादन में बढ़ोतरी और नए आदेशों के कारण नवंबर 2019 में 51.2 से बढ़कर 55.3 हो गया है।

10. हाल की अवधि में सेवाओं के कई उच्च आवृत्ति संकेतक ऊपर की ओर मुड़ गए हैं, जो कि गति में मामूली पुनरुद्धार की ओर इशारा करते हैं, हालांकि संभावनाएं अभी भी मंद हैं। ग्रामीण मांग के संकेतकों के बीच, जबकि दस महीने की गिरावट के बाद दिसंबर में ट्रैक्टर की बिक्री में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मोटरसाइकिल की बिक्री अभी भी संकुचित रही। घरेलू हवाई यात्री यातायात - शहरी मांग का एक संकेतक - में नवंबर में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद दिसंबर में मामूली वृद्धि हुई। तिपहिया वाहनों की

बिक्री और रेलवे माल ढुलाई में तेजी आई है, जबकि बंदरगाह यातायात दिसंबर में बदलाव आया। दूसरी ओर, यात्री वाहन की बिक्री में संकुचन जारी रहा। नए व्यापार और उत्पादन में वृद्धि के कारण पीएमआई सेवा सूचकांक में नवंबर 2019 में 52.7 की तुलना में जनवरी 2020 में 55.5 तक सुधार आया।

11. सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष बदलावों द्वारा मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति, अक्टूबर में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर में 5.5 प्रतिशत और दिसंबर 2019 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई 2014 के बाद सबसे अधिक रीडिंग है। जबकि खाद्य समूह मुद्रास्फीति दो अंकों में बढ़ गई, ईंधन समूह अपस्फीति से बाहर चला गया। भोजन और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में मुद्रास्फीति अपने अक्टूबर के गर्त से लगातार बढ़ती रही।

12. अक्टूबर-नवंबर में बेमौसम बारिश के कारण प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अक्टूबर में सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति 6.9 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर में 12.2 प्रतिशत हो गई। दिसंबर में प्याज को छोड़कर, खाद्य मुद्रास्फीति 4.7 प्रतिशत और हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत अंक कम बनी रही। इसके अलावा, कई अन्य खाद्य उप-समूहों जैसे दूध, दाल, अनाज, खाद्य तेल, अंडे, मांस और मछली की मुद्रास्फीति में भी तेजी आई।

13. सीपीआई ईंधन समूह ने दिसंबर में 0.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की, जो बिजली और जलावन की लकड़ी और चिप्स की कीमतों में वृद्धि; और मिट्टी के तेल की प्रशासित कीमतों को दर्शाती है। साथ में वे सीपीआई ईंधन बास्केट का 68 प्रतिशत हिस्सा हैं। नवंबर-दिसंबर में कीमतों में तेज सुधार के बावजूद एलपीजी मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में बनी रही।

14. सीपीआई मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन को छोड़कर अक्टूबर में 3.4 प्रतिशत से दिसंबर 2019 तक 3.8 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो मोबाइल फोन शुल्क, पेट्रोल, डीजल, परिवहन किराए और वस्त्रों के मुद्रास्फीति में वृद्धि से संचालित है। दिसंबर में आवास मुद्रास्फीति मंद हुई जो मांग में कमी को दर्शाती है।

15. रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के जनवरी 2020 के दौर में परिवारों की मुद्रास्फीति अनुमान 3 महीने आगे और 1 साल आगे मुद्रास्फीति की उम्मीदों में क्रमशः 60 आधार अंकों (बीपीएस) और 70 बीपीएस की गिरावट के साथ पिछले दौर में तेज उछाल के बाद कम हो गए। रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के

आधार पर, उपभोग की गैर-आवश्यक वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय एक वर्ष पहले की तुलना में संकुचित हुए; हालांकि, कुल व्यय में बढ़ोतरी की संभावना है जो कीमतों में वृद्धि को दर्शाते है। रिजर्व बैंक के औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के दिसंबर 2019 के दौर से पता चलता है कि विनिर्माण फर्मों के इनपुट और आउटपुट मूल्य 2019-20 की तीसरी तिमाही में मंद रहे और चौथी तिमाही में भी वैसे ही बने रहने की संभावना है।

16. सिस्टम में कुल चलनिधि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में अधिशेष में बनी रही। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण दिसंबर 2019 में ₹2.61 लाख करोड़ रहा। जनवरी 2020 में, अधिशेष चलनिधि का औसत दैनिक शुद्ध अवशोषण बढ़कर ₹3.18 लाख करोड़ हो गया। रिजर्व बैंक ने दिसंबर और जनवरी (23 और 30 दिसंबर 2019 तथा 6 और 23 जनवरी) के दौरान प्रत्येक ₹10,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के तहत दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री को शामिल करते हुए चार नीलामियों का आयोजन किया। इन परिचालनों को दर्शाते हुए 10-वर्ष का जी-सेक प्रतिफल 19 दिसंबर 2019 और 31 जनवरी 2020 के बीच संचयी रूप से 15 बीपीएस तक सौम्य हो गया। तथापि, मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रतिफल में 25 बीपीएस तक की गिरावट आई। भारत औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) ने आसान चलनिधि शर्तों पर दिसंबर में 10 बीपीएस तक और जनवरी में 19 बीपीएस तक पॉलिसी रेपो रेट (औसतन) से नीचे कारोबार किया।

17. विभिन्न मुद्रा बाजार क्षेत्रों और निजी कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट में मौद्रिक परिचालन काफी अधिक रहा। फरवरी 2019 के बाद से नीतिगत रेपो दर में 135 बीपीएस की संचयी कमी के विपरीत, 31 जनवरी 2020 तक विभिन्न धन और कॉर्पोरेट ऋण बाजार क्षेत्रों में प्रसारण 146 बीपीएस (ओवरनाइट मांग बाजार) से लेकर 190 बीपीएस (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के 3 महीने के सीपी) तक सीमित रहा। सरकारी प्रतिभूति बाजार की लंबी अवधि के माध्यम से परिचालन 73 बीपीएस (5-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों) और 76 बीपीएस (10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों) रहा। ऋण बाजार में परिचालन धीरे-धीरे सुधर रहा है। फरवरी 2019 और जनवरी 2020 के दौरान 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत की निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 55 बीपीएस की गिरावट

आई। फरवरी-दिसंबर 2019 के दौरान बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नए रुपये ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) पर 69 बीपीएस और बकाया रुपये ऋण पर डब्ल्यूएलआर में 13बीपीएस की गिरावट आई।

18. बाह्य बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, अधिकांश बैंकों ने आवास, व्यक्तिगत और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए अपनी ऋण दरों को रिजर्व बैंक की पॉलिसी रेपो दर से जोड़ा है। अक्टूबर-दिसंबर 2019 के दौरान, घरेलू (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र) बैंकों के नए रुपये के ऋणों पर डब्ल्यूएलआर आवास ऋण के लिए 18 बीपीएस, वाहन ऋण के लिए 87 बीपीएस और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण के लिए 23 बीपीएस की गिरावट दर्ज की गई है।

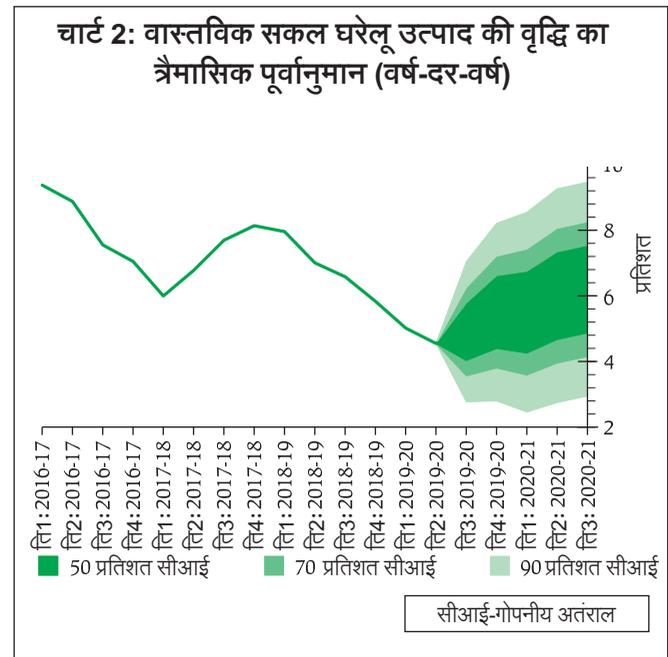
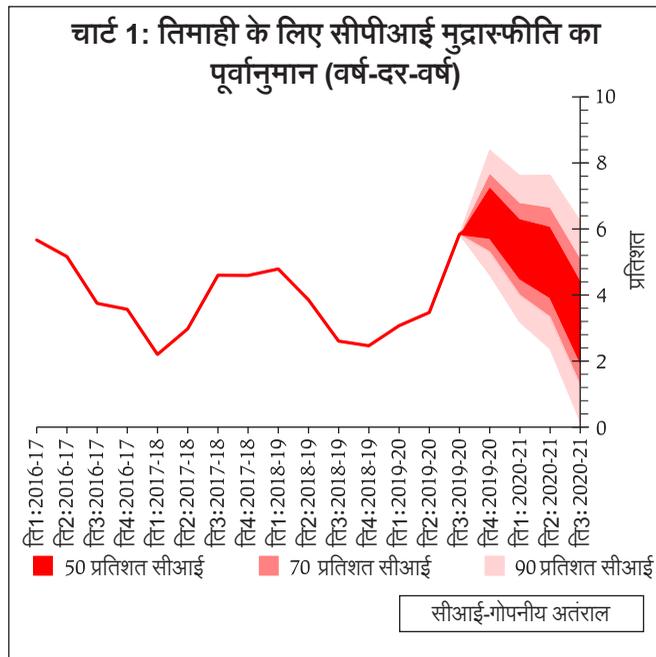
19. वैश्विक व्यापार में मंदी को दर्शाते हुए नवंबर-दिसंबर 2019 में निर्यात वृद्धि में संकुचन जारी रहा। तेल और गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात दोनों में संकुचन के साथ नवंबर-दिसंबर 2019 में आयात वृद्धि कम हो गई। जबकि गैर-तेल गैर-स्वर्ण आयात में घरेलू मांग में अंतर्निहित कमजोरी परिवहन उपकरण, कोयला, लोहा और इस्पात और रसायनों जैसी श्रेणियों में फैल गई, तेल आयात मात्रा में कटौती के कारण तेल आयात में कमी आई। दिसंबर 2019 में भी सोने के आयात में गिरावट आई। वित्त पोषण की तरफ, अप्रैल-नवंबर 2019 में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़कर 24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 2019-20 में (4 फरवरी तक) 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले साल की समान अवधि में अमेरिकी डॉलर 14.2 बिलियन का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया। इसके अलावा, स्वैच्छिक अवधारण मार्ग के तहत एफपीआई द्वारा निवल निवेश 11 मार्च 2019 के बाद से समेकित रूप से 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बने रहे। अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारी 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 4 फरवरी 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 471.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि मार्च 2019 के अंत तक 58.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

संभावनाएं

20. दिसंबर 2019 के पांचवें द्विमासिक संकल्प में, व्यापक रूप से संतुलित जोखिम के साथ 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए

5.1-4.7 प्रतिशत और 2020-21 की पहली छमाही के लिए 4.0-3.8 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया गया था। अक्टूबर-नवंबर में बेमौसम बारिश के कारण मुख्य रूप से दिसंबर 2019 में प्याज की कीमतों में उछाल के कारण दूसरी तिमाही में वास्तविक मुद्रास्फीति परिणाम 70 बीपीएस की वृद्धि के साथ 5.8 प्रतिशत रहे।

21. आगे बढ़ते हुए, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण कई कारकों से प्रभावित होने की संभावना है। पहले, खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर के उच्च स्तर से नरम होने की संभावना है और 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान गिरावट और अधिक स्पष्ट होने की उम्मीद है क्योंकि प्याज की कीमतें देर से खरीफ और रबी की फसल की आवक के जवाब में तेजी से गिर रही हैं। बेमौसम बारिश से शुरुआती नुकसान के बावजूद सब्जियों के उच्च उत्पादन का खाद्य मुद्रास्फीति पर एक लाभदायक प्रभाव होने की संभावना है। दूसरी ओर, गैर-सब्जी खाद्य पदार्थों की कीमतों में हाल ही के उछाल, विशेष रूप से इनपुट लागत में वृद्धि के कारण दूध में और खरीफ उत्पादन में कमी के कारण दालों में सभी के बने रहने की संभावना है। ये कारक समग्र खाद्य कीमतों के लिए कुछ ऊपरी पूर्वाग्रह प्रदान कर सकते हैं। दूसरी ओर, मध्य पूर्व में एक ओर भू-राजनीतिक तनाव और दूसरी ओर अनिश्चित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के कारण कूड की कीमतें अस्थिर रहने की संभावना है। तीसरा, हाल के महीनों में सेवाओं के लिए इनपुट लागत में वृद्धि हुई है। हालांकि, जनवरी के आखिरी सप्ताह से कमजोर मांग स्थिति और कंपनियों की मूल्य निर्धारण शक्ति, ऊर्जा की कीमतों में सुधार के मद्देनजर, पास-थ्रू प्रभाव से बिक्री की कीमतें सीमित हो सकती हैं। चौथा, घरेलू वित्तीय बाजार वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों को दर्शाते हुए अस्थिर बने हुए हैं, जिसका मुद्रास्फीति संभावनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। पांचवां, आधार प्रभाव 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान अनुकूल होगा। छठे, बजट में खुदरा खपत की वस्तुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि से महंगाई में केवल एक बार की बढ़ोतरी हो सकती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए और 2020-21 में एक सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून की धारणा के तहत सीपीआई मुद्रास्फीति प्रक्षेपण ऊपरी ओर संशोधित करके मोटे तौर पर संतुलित जोखिम के साथ 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए 6.5 प्रतिशत; 2020-21 की पहली छमाही के लिए 5.4-5.0 प्रतिशत; और 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए 3.2 प्रतिशत कर दिया गया है (चार्ट 1)।



22. विकास के दृष्टिकोण की ओर रुख करें, तो 2019-20 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दिसंबर 2019 की नीति में 5.0 प्रतिशत – दूसरी छमाही में 4.9-5.5 प्रतिशत थी। 2020-21 की पहली छमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 5.9-6.3 प्रतिशत था। 2020-21 के लिए, विकास का दृष्टिकोण कई कारकों से प्रभावित होगा। सबसे पहले, निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बेहतर रबी संभावनाओं के आधार पर ठीक होने की उम्मीद है। खाद्य कीमतों में हालिया वृद्धि ने कृषि के पक्ष में व्यापार की शर्तों को अंतरित कर दिया है, जो ग्रामीण आय को समर्थन मिलेगा। दूसरा, वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं को कम करने से निर्यात और निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। कोरोनावायरस का फैलाव, हालांकि, पर्यटकों के आगमन और वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, वाणिज्यिक क्षेत्र में उधार दरों और वित्तीय प्रवाह में कमी के मामले में मौद्रिक संचरण ने अंतिम नीति की दृष्टि से प्रगति की है और यह उपभोग और निवेश दोनों की मांग को बढ़ा सकता है। चौथा, केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यक्तिगत आयकर दरों के युक्तिकरण द्वारा घरेलू और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ाने के उपायों के साथ घरेलू मांग का समर्थन अपेक्षित है। उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.0 प्रतिशत – पहली छमाही में 5.5-6.0 प्रतिशत और तीसरी तिमाही (चार्ट 2) में 6.2 प्रतिशत की सीमा में अनुमानित है।

23. एमपीसी ने नोट किया कि मुद्रास्फीति दिसंबर 2019 में लक्ष्य के आसपास ऊपरी सहिष्णुता बैंड के ऊपर बढ़ी है, मुख्य रूप से प्याज की कीमतों में असामान्य उछाल के कारण। आने वाले हफ्तों और महीनों में प्याज की कीमतों में गिरावट की संभावना है क्योंकि आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि, हेडलाइन मुद्रास्फीति पर मौजूदा लाभदायक प्रभावों के विघटित होने की संभावना है, अन्य खाद्य पदार्थों विशेष रूप से दालों और प्रोटीनों के कीमतों के कड़े रुख से। इस बीच दूरसंचार शुल्क का समायोजन खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति को लागत-दबाव प्रदान कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि मोबाइल फोन शुल्क में शेष संशोधनों के पास-थ्रू, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स की कीमतों में वृद्धि और नए उत्सर्जन मानदंड मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रहे हैं। एमपीसी का अनुमान है कि कम से कम 2020-21 की पहली छमाही में इन कारकों के संयोजन से अल्पावधि में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है। तदनुसार, एमपीसी मुद्रास्फीति संबंधी दबावों के संभावित सामान्यीकरण के बारे में सतर्क रहेगा क्योंकि पहले उद्धृत किए गए कई अंतर्निहित कारक एक साथ परिचालित होते हैं।

24. इसी समय, एमपीसी का मानना है कि अर्थव्यवस्था कमजोर बनी हुई है और उत्पादन अंतर नकारात्मक बना हुआ है। हालांकि कुछ उच्च-आवृत्ति संकेतक बदल गए हैं और आर्थिक गतिविधि की गति में वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं और उनकी स्थिरता का अनुमान लगाने के लिए जरूरी है कि आने वाले आकड़ों की प्रतीक्षा की जाए। वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह में हाल के महीनों में सुधार हुआ है। केंद्रीय बजट 2020-21 ने विकास को गति प्रदान करने के लिए कई उपाय प्रस्तुत किए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे निकट अवधि में विकास की गति बढ़ सकती है। सितंबर 2019 के कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती से मध्यम अवधि में विकास की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत की तुलना में 3.8 प्रतिशत रखा गया है। बजट अनुमानों में 2019-20 में उच्च राजकोषीय घाटे के कारण बाजार उधार में वृद्धि नहीं हुई है। 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक घटने का अनुमान है। बजट की संभावना है कि ताजा सकल बाजार उधार ₹70,000 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹7.1 लाख करोड़ से 2020-21 में ₹7.8 लाख करोड़ हो जायेगा। एमपीसी नोट करता है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में समायोजन की आवश्यकता है, वहीं 1 अक्टूबर, 2019 से शुरू की गई बाहरी बेंचमार्क प्रणाली ने मौद्रिक परिचालन को मजबूत किया है। इन विकासों को फरवरी 2019 से

रिजर्व बैंक द्वारा किए गए संचयी नीति दर में कमी के प्रभावों को बढ़ाना चाहिए और घरेलू मांग को आगे बढ़ाना चाहिए।

25. एमपीसी मानता है कि भविष्य की कार्रवाई के लिए नीति अवसर उपलब्ध है। हालांकि, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र 2019-20 की चौथी तिमाही के माध्यम से बढ़ते हुए स्तर पर है। इस मोड़ पर मुद्रास्फीति के लिए दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है। दूसरी ओर, आर्थिक गतिविधि कमजोर हो रही है और हाल ही में बढ़े कुछ संकेतकों द्वारा अभी और अधिक व्यापक-आधारित तरीके से गति प्राप्त करना बाकी है। बढ़ती विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता को देखते हुए, एमपीसी ने यथास्थिति बनाए रखना उचित समझा है। तदनुसार, एमपीसी ने यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, विकास को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक रूप में लंबे समय के लिए नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित रखने और दृढ़ता के साथ उसे बनाए रखने का निर्णय लिया है।

26. डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. जनक राज, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने निर्णय के पक्ष में मतदान किया।

27. एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 20 फरवरी, 2020 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

28. एमपीसी की अगली बैठक 31 मार्च, 1 और 3 अप्रैल 2020 के दौरान निर्धारित की गई है।

विकासात्मक एवं विनियामक नीति वक्तव्य

यह वक्तव्य कुछ क्षेत्रों में क्रेडिट प्रवाह में सुधार; मौद्रिक संचरण को सुदृढ़ करना; विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करना; वित्तीय बाजारों को व्यापक और गहरा करना; और भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. तरलता प्रबंधन, मौद्रिक संचरण, एवं ऋण प्रवाह

1. संशोधित तरलता प्रबंधन

जैसा कि 6 जून, 2019 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, चलनिधि प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करने के उपायों के बारे में और चलनिधि प्रबंधन हेतु टूलकिट की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह की स्थापना की गई। समूह की रिपोर्ट 26 सितंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियों के लिए रखी गई थी। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे को ठीक करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित रूपरेखा के प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं:

- (i) चलनिधि प्रबंधन मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया है; भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) इसका परिचालन लक्ष्य बनी रहेगी।
- (ii) चलनिधि प्रबंधन कॉरिडर को बनाए रखा गया है, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को इसकी ऊपरी सीमा(सीलिंग) के रूप में और स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो दर न्यूनतम सीमा (तल) के रूप में और बीच में पॉलिसी रेपो दर रहेगा।
- (iii) कॉरिडर की चौड़ाई 50 आधार बिंदुओं पर अपरिवर्तित बनी हुई है – प्रतिवर्ती रेपो दर रेपो दर से 25 आधार अंक से और रेपो दर से 25 बेसिस अंक ऊपर आधार अंक है।
- (iv) डब्ल्यूएसीआर एकल परिचालन लक्ष्य होने के साथ, निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत के चलनिधि प्रावधान के लिए एकतरफा लक्ष्य को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान में किए जा रहे हर पखवाड़े में दैनिक नियत दर रेपो और चार 14-दिवसीय

मियादी रेपो वापस लिए जा रहे हैं। हालांकि, रिजर्व बैंक नीतिगत दर पर या उसके आस-पास अंतर्निहित और विकसित बाजार की स्थितियों से अप्रतिबंधित तरलता की पर्याप्त व्यवस्था / अवशोषण सुनिश्चित करेगा।

- (v) तरलता प्रबंधन के साधनों में निश्चित और परिवर्तनीय दर रेपो / रिवर्स रेपो नीलामियां, एकमुश्त खुले बाजार संचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और अन्य लिखतों शामिल होंगे, जो समय-समय पर तैनात किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिस्टम में पर्याप्त तरलता है।
- (vi) एक परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय रेपो / रिवर्स रेपो परिचालन किया जाएगा जो नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव साइकल के साथ मेल खाता हो और जो घर्षणात्मक तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए मुख्य तरलता प्रबंधन उपकरण होगा।
- (vii) आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित तरलता में बदलाव करने के लिए, रात भर और / या अधिक समय तक, मुख्य तरलता परिचालन सही संचालन द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- (viii) इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक 14 दिनों से अधिक समय की लंबी अवधि की परिवर्तनीय दर रेपो / रिवर्स रेपो परिचालनों का संचालन करेगा।
- (ix) दैनिक आधार पर निर्धारित सीआरआर का न्यूनतम 90 प्रतिशत बनाए रखने की वर्तमान आवश्यकता जारी रहेगी।
- (x) एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडीएस) को रात भर चलनिधि प्रबंधन कार्यों में सीधे भाग लेने की अनुमति होगी।
- (xi) तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी; हालांकि, रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए मार्जिन आवश्यकता 'निरंक' रहना जारी रहेगा।
- (xii) रिजर्व बैंक की तरलता प्रबंधन रूपरेखा और प्रक्रियाओं पर संचार को बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित उपाय प्रस्तुत किए जा रहे हैं (ए) मुद्रा बाजार परिचालन (एमएमओ) को विस्तार से बताते हुए प्रेस रिलीज को दैनिक प्रवाह प्रभाव के साथ-साथ रिजर्व बैंक की तरलता संचालन से स्टॉक प्रभाव

दोनों को दिखाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा; (बी) बैंकिंग प्रणाली की टिकाऊ तरलता की स्थितियों का मात्रात्मक मूल्यांकन एक पखवाड़े के अंतराल पर प्रकाशित किया जाएगा; (सी) आवधिक परामर्श बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित किया जाएगा।

2. मौद्रिक संचरण सुधारने हेतु दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओएस)

जून 2019 से, रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित किया है कि मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को परिचालित करने और अर्थव्यवस्था को ऋण प्रवाह मुहैया कराने के लिए सिस्टम में पर्याप्त तरलता उपलब्ध है। मौजूदा बाजार स्थितियों में उचित लागत पर टिकाऊ तरलता की उपलब्धता के बारे में बैंकों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से इन प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे बैंकों को परिपक्वता परिवर्तन को सुचारू और निर्बाध रूप से करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा ताकि उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि हो सके। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 15 फरवरी 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े से, रिजर्व बैंक ₹1,00,000 करोड़ की कुल राशि के लिए पॉलिसी रेपो दर पर उपयुक्त आकार के एक वर्ष और तीन-वर्ष के कार्यकाल की अवधि के मीयादी रेपो का संचालन करेगा। एलटीआरओ सुविधा के बारे में अलग से विवरण जारी किया जा रहा है।

3. विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बैंक क्रेडिट को प्रोत्साहन देना

मौद्रिक संचरण में सुधार के निरंतर प्रयासों के साथ, रिजर्व बैंक सक्रिय रूप से विकास के आवेगों का समर्थन करने के लिए गुणक प्रभाव वाले उत्पादक क्षेत्रों को बैंक ऋण प्रवाह को पुनर्जीवित करने में लगा हुआ है। इसके एक हिस्से के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऑटोमोबाइल, आवास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 31 जनवरी 2020 को समाप्त पखवाड़े के अंत में ऋण के बकाया स्तर के अलावा खुदरा ऋण के रूप में उनके द्वारा वितरित वृद्धिशील ऋण के बराबर कटौती करने की अनुमति दी जाएगी और यह कटौती आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने के लिए निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से की जाएगी। यह छूट 31 जुलाई 2020 को समाप्त पखवाड़े तक बढ़ाए गए वृद्धिशील ऋण के लिए उपलब्ध होगी।

II. विनियम एवं पर्यवेक्षण

4. बैंकों द्वारा माध्यम उद्यमों को प्रदान नए अस्थायी दर ऋण की बाहरी बेंचमार्किंग

एक आंतरिक अध्ययन समूह (अध्यक्ष: डॉ. जनक राज) की सिफारिशों के अनुसरण में, बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रदान सभी नए अस्थायी दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और अस्थायी दर ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़े गए थे, यथा, (i) नीतिगत रेपो दर; या (ii) 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी खज़ाना बिल दरों सहित वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा निर्धारित किसी भी बेंचमार्क बाजार ब्याज दर। बाहरी बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, मौद्रिक संचरण उन क्षेत्रों में सुधार हुआ है जहां नए अस्थायी दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है। मौद्रिक संचरण को और मजबूत करने के उद्देश्य से, मध्यम उद्यमों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋणों के मूल्य निर्धारण को 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इस आशय के विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

5. एमएसएमई अग्रिमों के लिए एकबारगी पुनर्गठन योजना का विस्तार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत है¹ 40 प्रतिशत से अधिक निर्यात² तथा लगभग 11 करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करता है।³ भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को ध्यान में रखते हुए और औपचारिकता की दिशा में अपने प्रयासों में इस क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए, उन एमएसएमई को जो चूककर्ता थे लेकिन 1 जनवरी 2019 को 'मानक' थे को बिना निम्न आरिस्त वर्गीकरण के एकबारगी पुनर्निर्माण ऋण की अनुमति दी गई। 31 मार्च 2020 तक उधारकर्ता खाते का पुनर्गठन लागू किया जाना था। इस योजना से बड़ी संख्या में एमएसएमई को राहत मिली है। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया का वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह प्रक्रिया अभी

¹ एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

² एमएसएमई निर्यात की संभावित क्षमता - एमएसएमई मंत्रालय की कार्यनीति कार्य योजना, 01 नवंबर, 2018

³ एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19

भी चल रही है, इसलिए यह तय किया गया है कि जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई जो 1 जनवरी 2020 को चूककर्ता थे, के मानक खातों में आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड के बिना एक बारगी का लाभ बढ़ाया जाए। इस योजना के तहत पुनर्गठन को 31 दिसंबर 2020 तक लागू किया जाना है। इससे पात्र एमएसएमई संस्थाओं को लाभ होगा जो 1 जनवरी 2019 के परिपत्र के प्रावधानों के तहत पुनर्गठित नहीं की जा सकी हैं, और वे एमएसएमई इकाइयां भी जो आगे तनावग्रस्त हो गई हैं। इस पर फिर से जोर दिया गया है कि यह एक बार की विनियामक संवितरण है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

6. वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र में कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं पर दिशानिर्देश

यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्यिक अचल संपत्ति के लिए परियोजना ऋण के वाणिज्यिक परिचालनों को आरंभ (डीसीसीओ) करने की तारीख को गैर-मूलभूत सुविधा क्षेत्र के लिए अन्य परियोजना ऋणों के प्रकृति के अनुरूप आस्ति वर्गीकरण में गिरावट लाए बिना एक और वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी जाए, जिसमें विलंब होने का कारण प्रमोटर के नियंत्रण से परे है। यह भारत सरकार द्वारा अचल संपत्ति क्षेत्र में की गई पहल का पूरक होगा। शीघ्र ही विस्तृत अनुदेश जारी किए जाएंगे।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय के लिए अनुमति

अपने ग्राहकों को लागत प्रभावी और यूसर फ्रेंडली के अनुकूल समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सक्षम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आरआरबी को अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह, आधार पे – भीम ऐप और पीओएस टर्मिनलों का उपयोग करके व्यापारी अधिग्रहण बैंकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आज जारी किए जाएंगे।

8. सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए लागू विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन

09 अगस्त 2019 से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से रिजर्व बैंक में एचएफसी के नियमन का अंतरण, 13 अगस्त 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें यह सूचित किया गया

कि रिजर्व बैंक, एचएफसी पर लागू मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा करेगा और नियत समय में संशोधित विनियम जारी करेगा, और तब तक एचएफसी एनएचबी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना जारी रखेगा। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए, इस महीने के अंत तक बैंक की वेबसाइट पर संशोधित नियमों को रखना प्रस्तावित है।

III. वित्तीय बाजार

9. रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न बाजार को बढ़ावा देना

वर्तमान में, 'बैंक-टू-बैंक' व्यवस्था के माध्यम से गैर-निवासियों के साथ रुपये के ब्याज दर व्युत्पन्न (आईआरडी) लेनदेन करने वाले बाजार निर्माताओं को भारत में अपनी लेखों में वैश्विक स्तर पर संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए सभी रुपये के आईआरडी लेनदेन को पहचानने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था को सभी बाजार निर्माताओं को कवर करने के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव है, चाहे वे बैंक-टू-बैंक लेनदेन का कार्य करें या नहीं। यह तदनुसार प्रस्तावित है कि बाजार निर्माताओं और वैश्विक स्तर पर संबंधित संस्थाओं के रुपये के सभी आईआरडी लेनदेन का भारत में हिसाब किया जाएगा। यह उपाय उच्च अनिवासी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा, जिससे अपतटीय बाजार में घरेलू बाजार निर्माताओं की भूमिका बढ़ेगी, पारदर्शिता में सुधार होगा, और बेहतर सुरक्षा प्राप्त होगी। संशोधित दिशा-निर्देश का मसौदा मार्च 2020 तक जारी किया जाएगा।

10. गैर-केंद्रीकृत क्लियरिंग डेरिवेटिव के लिए मार्जिन आवश्यकताएं

वित्तीय अनुबंधों के लिए सुस्थापित सीमांकन व्यवस्था बाजार तंत्र की विश्वसनीयता को बढ़ाने और अत्यधिक जोखिम लेने को हतोत्साहित करके वित्तीय स्थिरता में योगदान करती है। ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव के निपटान की सुरक्षा में सुधार करने के लिए जिसे केंद्रीय स्तर पर मंजूरी नहीं दी गई है, जी -20 की सिफारिशों के बाद, रिजर्व बैंक ने इस तरह के डेरिवेटिव के लिए मार्जिन आवश्यकताओं से संबंधित वैश्विक प्रथाओं को लागू करने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया था। केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित वित्तीय लेन-देन के लिए कानून की शुरुआत कुशल मार्जिनिंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक होगी। इसलिए, मार्च 2020

के अंत तक गैर-केंद्रीय रूप से मंजूर डेरिवेटिव (एनसीसीडीएस) के लिए भिन्नता मार्जिन (वीएम) के आदान-प्रदान के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है। एनसीसीडी के लिए प्रारंभिक मार्जिन (आईएम) के आदान-प्रदान पर मसौदा निर्देश जून 2020 तक जारी किए जाएंगे।

11. निक्षेपागार की अंतर-संचालनशीलता

केंद्रीय बजट 2019-20 में घोषित सरकारी प्रतिभूतियों के निक्षेपागार की सुविधा के लिए प्रयासों के क्रम में, रिज़र्व बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की रजिस्ट्री (पीडीओ-एनडीएस प्रणाली) को संशोधित करेगा, ताकि जिसमें ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों ग्राहक के विवरण शामिल किया जा सके। यह अनुमानित है कि इससे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए खुदरा निवेशकों के हित को बढ़ावा मिलेगा। जुलाई 2020 के अंत तक अपग्रेड को परिचालित करने की उम्मीद है।

IV. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

12. डिजिटल भुगतान सूचकांक

भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। रिज़र्व बैंक समय-समय पर भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को प्रभावी ढंग से केपचर करने के लिए एक समग्र “डिजिटल भुगतान सूचकांक” (डीपीआई) का निर्माण और प्रकाशन करेगा। डीपीआई कई मापदंडों

पर आधारित होगा और विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों के पैठ और गहनता को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करेगा। डीपीआई को जुलाई 2020 से उपलब्ध कराया जाएगा।

13. डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना की रूपरेखा

भुगतान इको तंत्र में डिजिटल भुगतान में पर्याप्त संवृद्धि और संस्थाओं द्वारा प्राप्त परिपक्वता सहित भुगतान प्रणाली में संस्थाओं के व्यवस्थित परिचालन के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) होना वांछनीय है। रिज़र्व बैंक अन्य के साथ सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और मूल्य निर्धारण की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 तक डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए एक एसआरओ की स्थापना के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। एसआरओ प्लेयर्स और विनियामक / पर्यवेक्षक के बीच दो-तरफ़ा संचार चैनल के रूप में काम करेगा।

14. अखिल भारतीय चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस)

चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सीटीएस), जो वर्तमान में देश के प्रमुख समाशोधन गृहों में परिचालित है, अच्छी तरह से स्थिर हो गया है और इसने बड़ी दक्षता हासिल की है। इसे देखते हुए, एक अखिल भारतीय सीटीएस को सितंबर 2020 तक परिचालित कर दिया जाएगा।

भाषण

भारत की मौद्रिक नीति के सात युग
शक्तिकांत दास

भारत की मौद्रिक नीति के सात युग* शक्तिकांत दास

मेरी शैक्षणिक संस्था में लौटकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यहां, मेरी कई यादें ताजा हो गई हैं। आज, मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंकिंग के कुछ पहलुओं एवं वर्तमान स्थिति में आरबीआई की भूमिका पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं, खास तौर पर भारत में मौद्रिक नीति की व्यवस्था के क्रमिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और यदि मैं शेक्सपियर की काव्यात्मक प्रस्तुति का उपयोग कर रहा हूँ तो क्या मैं इसे भारत की मौद्रिक नीति के सात युग कह सकता हूँ?

केंद्रीय बैंकिंग का इतिहास सत्रहवीं शताब्दी में पाया जाता है जब 1668 में स्वीडन में पहला संस्थान 'रिकबैंक', केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। एक संयुक्त स्टॉक बैंक के रूप में स्थापना से, यह सरकार को धन उधार देने और व्यापार के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत था। बाद में, रिक्सबैंक ने वाणिज्यिक उधार त्याग दिया और 1897 में उसे बैंक नोट जारी करने के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके बाद, कई देशों ने केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य करने वाले संस्थानों की स्थापना की। शुरुआती केंद्रीय बैंक जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंके डी फ्रांस हालांकि निजी पूंजी के साथ स्थापित किए गए, उन्होंने सरकार को कर्ज के वित्तपोषण में मदद की और बैंकिंग विकास में शामिल रहे। तब से, देश भर के केंद्रीय बैंकों की भूमिका लगातार उनकी अर्थव्यवस्थाओं की बदलती जरूरतों और वित्तीय ढांचे के विकास के अनुरूप विकसित होती रही है। आज, आधुनिक केंद्रीय बैंकों के कार्य उनके शुरुआती समकक्षों से काफी भिन्न हैं।

मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद रिज़र्व बैंक की रूपरेखा हमारे देश के आर्थिक और वित्तीय विकास के साथ आंतरिक रूप से किस तरह से परस्पर जुड़ी हुई है।

रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी जिसमें मूल प्रस्तावना में रिज़र्व बैंक के व्यापक अधिदेश का वर्णन करता है:

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 24 जनवरी 2020 को सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में दिया गया सम्बोधन।

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन करना समीचीन है।”

बाद में, 1949 में भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंधन, बैंकों का बैंक और सरकार का बैंकर, जैसे अपने पारंपरिक कार्य करना जारी रखा है, लेकिन मौद्रिक नीति संचालन का कार्य विभिन्न पहलुओं में समय समय पर आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन से गुजरा है।

जैसा कि हम जानते हैं, नीतिगत बदलाव आमतौर पर दो प्रमुख कारणों से प्रेरित होते हैं: पहला, जो उद्देश्य पहले उचित लगते हैं, वह समय के साथ बदलते व्यवहारों के कारण प्रासंगिकता खो देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमने पाया कि अतीत की तरह मुद्रा का सांकेतिक आय के साथ संबंध बहुत प्रत्याशित नहीं है, तो हमने 1998 में एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण अपनाए। दूसरा, बेहतर नीतिगत परिणामों के लिए, नए सिद्धांतों और प्रमाणों के साथ अद्यतन ज्ञान लागू करने की आवश्यकता है। समय के साथ भारत में निश्चित रूप में इसी ने मौद्रिक नीति के संचालन को आकार दिया।

अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप के अनुरूप मौद्रिक नीति का विकास

1935 से 1949: प्रारंभिक चरण

यह रोचक बात है कि रिज़र्व बैंक की स्थापना महामंदी से जूझती वैश्विक अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालियों की अव्यवस्था के बीच आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना ने मौद्रिक नीति ढांचे के विकास की आधारशिला प्रदान की। आजादी तक, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से बाजार दर और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) जैसे अतिरिक्त मौद्रिक साधनों से चलनिधि विनियमित करके वास्तविक अनुरूपता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरे शब्दों में, मौद्रिक नीति के लिए विनिमय दर सांकेतिक साधन था। अर्थव्यवस्था की कृषि स्वरूप

के मद्देनजर, अक्सर आपूर्ति पक्ष के झटकों के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति एक चिंता का विषय बन गई। जबकि सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण के उपायों और आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग की गई थी, रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को सट्टा उद्देश्यों के लिए ऋण देने से रोकने हेतु चयनात्मक ऋण नियंत्रण और नैतिक दबाव का प्रयोग किया।

1949 से 1969: पंचवर्षीय योजनाओं के साथ मौद्रिक नीति का समन्वयन

1947 में भारत की स्वतंत्रता देश के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद नियोजित आर्थिक विकास की नीति को अपनाया गया था। इन दो दशकों में न केवल राज्य की प्रमुख भूमिका यह विशेषता थी, बल्कि मौद्रिक नीति के संचालन में भी एक उल्लेखनीय बदलाव आया था। इसका व्यापक उद्देश्य आत्म-निर्भरता पर ध्यान देने के साथ आर्थिक विकास के माध्यम से समाज के समाजवादी पैटर्न को सुनिश्चित करना था। यह उद्देश्य, स्वदेशी क्षमता का निर्माण, छोटे और साथ ही बड़े पैमाने पर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, आय असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के माध्यम से हासिल करना था। तदनुसार, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करके औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए उद्यमशीलता की भूमिका भी निभाई।

विकास की प्रक्रिया में नियोजित व्यय को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाने के कारण, उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आबंटन पर जोर दिया गया था। इसलिए नियोजित आर्थिक विकास के इस चरण के दौरान, मौद्रिक नीति की भूमिका, पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकताओं के इर्द-गिर्द घूमती है। यदि कोई औपचारिक ढांचा नहीं भी होता, तब भी अर्थव्यवस्था में ऋण की आपूर्ति और मांग के प्रबंधन के लिए मौद्रिक नीति पर भरोसा किया गया था। ऋण उपलब्धता को विनियमित करने के लिए बैंक दर, आरक्षित अपेक्षाएं और खुले बाजार संचालन (ओएमओ) जैसे नीतिगत उपायों का प्रयोग किया गया था। 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के लागू होने के साथ, बैंकों के लिए निर्धारित संवैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाएं सरकारी उधार के लिए एक सुरक्षित स्रोत के रूप में उभरी तथा मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन के लिए अतिरिक्त साधन के रूप में भी कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में मुद्रास्फीति मध्यम रही लेकिन 1964-68 के दौरान एक चिंता का विषय बन गयी।

1969 से 1985: ऋण योजना

1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण मौद्रिक नीति के विकास में और एक उल्लेखनीय चरण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य जनता के हर तबके और विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करना था। बैंकों को क्रेडिट विस्तार करने का अधिकार मिलने के कारण, क्रेडिट विस्तार से धन आपूर्ति में तेज वृद्धि के मद्देनजर रिजर्व बैंक को आर्थिक वृद्धि का वित्तपोषण और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, 1971 में भारत-पाक युद्ध, 1973 में सूखा, 1973 और 1979 में वैश्विक तेल की कीमतों में आघात और 1973 में ब्रेटन-वुड्स प्रणाली के पतन के भी स्फीतिकारी परिणाम थे। इसलिए, 1960 के दशक के दौरान घाटे के वित्तपोषण के कारण उच्च मुद्रास्फीति की चिंताओं ने 1970 के दशक के दौरान जोर पकड़ा। प्रसंगवश घरेलू अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन- मुद्रास्फीति और धीमी गति से वृद्धि के साथ-साथ हुई। इस तरह की परिस्थिति में, पारंपरिक मौद्रिक नीति साधन, अर्थात्, बैंक दर और ओएमओ मूल्य स्थिरता के लिए धन आपूर्ति के प्रभाव को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त पाए गए। चूंकि बैंक घाटे के वित्तपोषण के प्रभाव कारण उपलब्ध जमाराशि से उत्तेजित थे, इसलिए उन्हें धन के लिए आरबीआई से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे मौद्रिक नीति साधन के रूप में बैंक दर की प्रभावकारिता को कम कर दिया। इसी तरह, अविकसित सरकारी प्रतिभूति बाजार के कारण, मौद्रिक नीति साधन के रूप में ओएमओ का उपयोग करने के लिए सीमित गुंजाइश थी। इस चरण में औसत विकास दर लगभग 4.0 प्रतिशत के आस-पास रहा, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति लगभग 8.8 प्रतिशत थी।

1985 से 1998: मौद्रिक लक्ष्य

1980 के दशक में, राजकोषीय प्रभुत्व तदर्थ ट्रेजरी बिल और 1985 तक एसएलआर में प्रगतिशील वृद्धि के माध्यम से बजट घाटे के स्वतः मुद्रीकरण के रूप में परिलक्षित हुआ। इसके परिणामस्वरूप, घाटे के वित्तपोषण के मुद्रास्फीति प्रभाव ने समन्वित रूप से मौद्रिक नीति को सख्त बनाने का प्रयास किया - सीआरआर और बैंक दर दोनों में काफी वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति और वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से निपटने में मौद्रिक नीति के

अनुभव ने अंततः चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों पर 1985 में एक औपचारिक मौद्रिक नीति ढांचे के रूप में मौद्रिक लक्ष्य को अपनाया। इस ढांचे में, मौद्रिक विस्तार को सीमित करने के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, आरक्षित निधि का उपयोग परिचालन लक्ष्य और व्यापक मुद्रा का उपयोग मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में किया गया था। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का लक्ष्य अपेक्षित वास्तविक जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के सहनीय स्तर पर आधारित था। यह दृष्टिकोण आघात सहनीय था क्योंकि इसने प्रतिक्रिया मांगी थी। सीआरआर का उपयोग मौद्रिक नियंत्रण के लिए प्राथमिक साधन के रूप में किया गया था। बहरहाल, निरंतर राजकोषीय प्रभुत्व के कारण, एसएलआर और सीआरआर दोनों 1990 तक अपने चरम स्तर पर पहुंच गए।

प्रतिकूल वैश्विक आघातों - खाड़ी युद्ध और सोवियत संघ के विघटन की पृष्ठभूमि में 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राजकोषीय स्थिति के बिगड़ने से बाहरी संतुलन की स्थिति में गिरावट और 1991-92 में घरेलू वृद्धि में गिरावट हुई। नतीजन भुगतान संकट के संतुलन ने बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण और मूल्य स्थिरता के साथ स्थायी वृद्धि प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने की शुरुआत की। साथ-साथ 1993 में निर्धारित विनिमय दर प्रणाली के स्थान पर बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली शुरू हुई। व्यापार और वित्तीय क्षेत्र में सुधार और परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी प्रवाह और वित्तीय नवाचारों में वृद्धि के मद्देनजर, पैसे की मांग में स्थिरता की धारणा, साथ ही मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में व्यापक मुद्रा की प्रभावकारिता सवालों के घेरे में आ गई। इसी समय, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के लिए बाजार आधारित वित्तपोषण की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव हुआ। वास्तव में, तदर्थ ट्रेजरी बिलों के माध्यम से स्वचालित विमुद्रीकरण को 1997 में समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) को लाया गया था। इस अवधि के दौरान, औसत घरेलू वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत और औसत डब्ल्यूपीआई-आधारित मुद्रास्फीति 8.1 प्रतिशत थी।

1998 से 2015: एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण

1990 के दशक की शुरुआत से ही अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वित्तीय नवाचारों ने प्रचलित मौद्रिक लक्ष्य ढांचे की प्रभावकारिता कमजोर होना शुरू हुआ, मौद्रिक नीति ढांचे की समीक्षा करने और इसकी संचालन प्रक्रियाओं को पुनः

सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की गई। नतीजतन, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1998 में एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए संकलित मौद्रिक राशि के अलावा, क्रेडिट, आउटपुट, मुद्रास्फीति, व्यापार, पूंजी प्रवाह, विनिमय दर, अलग-अलग बाजारों के रिटर्न और राजकोषीय निष्पादन में सूचना के आधार जैसे प्रगतिशील संकेतकों के समूह का उपयोग किया। 2003 में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम (एफआरबीएम) लागू होने से अधिनियम ने राजकोषीय अनुशासन की शुरुआत करते हुए, मौद्रिक नीति को लचीलापन प्रदान किया। 1990 के दशक की शुरुआत से घरेलू अर्थव्यवस्था के बाजार उन्मुखीकरण में वृद्धि और ब्याज दरों में गिरावट ने भी मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष साधनों को प्रत्यक्ष साधनों में परिवर्तित किया। इसलिए, मौद्रिक नीति निर्माण के लिए मात्रा साधनों के सापेक्ष दर चैनलों पर अधिक जोर दिया गया था। तदनुसार, अल्पकालिक ब्याज दरें आरबीआई के मौद्रिक नीति रुख दर्शाने का साधन बन गईं।

अल्पकालिक ब्याज दरों को स्थिर करने के लिए, रिजर्व बैंक ने अन्य बाजार खंडों के साथ मुद्रा बाजार के एकीकरण पर अधिक जोर दिया। इसने बाजार चलनिधि को नीतिगत साधनों के मिश्रण का उपयोग करके मौद्रिक स्थितियों को वांछित वृद्धि में परिवर्तित किया। आरक्षित आवश्यकताओं, स्थायी सुविधाओं और ओएमओ में परिवर्तन सहित इनमें से कुछ साधन सीमांत चलनिधि मात्रा को प्रभावित करने के लिए थे, जबकि नीतिगत दरों में परिवर्तन, जैसे बैंक दर और रिवर्स रेपो / रेपो दर चलनिधि की कीमत बदलने के साधन थे।

समष्टि आर्थिक परिणामों के आकलन से पता चलता है कि एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण 1998-99 से 2008-09 तक काफी अच्छी तरह से काम करता है। इस अवधि के दौरान, घरेलू वृद्धि दर औसतन 6.4 प्रतिशत और डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत तक मध्यम रही।

2013-2016: मुद्रास्फीति लक्ष्य की पूर्वशर्तें

वैश्विक वित्तीय संकट की अवधि (यानी, 2008 के बाद) के बाद, हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति और कमजोर वृद्धि के कारण इस ढांचे की विश्वसनीयता निरंतर सवालों के घेरे में आ गई। 2012-13 में दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति के सामने, मई / जून 2013 में यूएस फेड की टेंपर टॉक ने घरेलू मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया, जिसमें वृद्धि को बनाए रखने,

मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और वित्तीय स्थिरता हासिल करने के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना था। मौजूदा एकाधिक संकेतकों के दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की गई थी कि संकेतकों का एक बड़ा समूह मौद्रिक नीति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित सांकेतिक साधन नहीं देता है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने और इसे और अधिक पारदर्शी और प्रत्याशित बनाने हेतु सुझाव के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने 2014 की अपनी रिपोर्ट में, एकाधिक संकेतकों के दृष्टिकोण की समीक्षा की और सिफारिश की कि भारत में मौद्रिक नीति ढांचे के लिए मुद्रास्फीति सांकेतिक साधन होनी चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने क्रमबद्ध तरीके से - नवंबर 2013 में अपने 11.5 प्रतिशत के स्तर से जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत; जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत और 2016-17 के ति4 में 5 प्रतिशत के स्तर तक मुद्रास्फीति को नीचे लाने का मार्ग अपनाया।

2016 के आगे: आघात सहनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य

इसके अलावा, एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते (MPFA) पर 20 फरवरी, 2015 को भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तदनंतर, मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के साथ आघात सहनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) को औपचारिक रूप में अपनाया गया। मौद्रिक नीति के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की भूमिका को संशोधित अधिनियम में निम्नलिखित रूप में बहाल की गई है:

“मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है”।

इस अधिदेश से अधिकार प्राप्त, आरबीआई ने एक आघात सहनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) ढांचा अपनाया जिसके अंतर्गत मूल्य स्थिरता को प्रधानता दी गयी, जिसे उपभोक्ता मूल्य हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ +/- 2 प्रतिशत के टोलरेंस बैंड के साथ और साथ-साथ जब मुद्रास्फीति नियंत्रण में है वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना के रूप में संख्यात्मक रूप से परिभाषित किया गया है। मुद्रास्फीति और वृद्धि पर सापेक्ष जोर समष्टि आर्थिक परिदृश्य, मुद्रास्फीति और वृद्धि के दृष्टिकोण और आने वाले डेटा से उभरने वाले संकेतों पर निर्भर करता है। तब से आरबीआई एक दूरदर्शी तरीके से मौद्रिक नीति का संचालन कर रहा है और अपने लक्ष्य के आसपास मुद्रास्फीति को बनाए रखने के लिए अपने निर्णयों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर रहा है

और जिससे वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। साथ ही, आरबीआई वित्तीय बाजारों में और इस तरह वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नीति संचरण के लिए मौद्रिक नीति की अपनी संचालन प्रक्रियाओं को भी ठीक कर रहा है। नतीजतन, मुद्रास्फीति लगातार गिरती गई और 2017-18 के बाद से औसतन 4 प्रतिशत से नीचे आ गई है, भले ही खाद्य कीमतों से प्रेरित मुद्रास्फीति में हाल ही में कोई फर्क नहीं पड़ा है, खासकर सब्जी की कीमतों में तेज वृद्धि बेमौसम बारिश और चक्रवात के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती है।

बदलता सैद्धांतिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मौद्रिक नीति का विकास

भारत में मौद्रिक नीति ढांचा सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की विकास द्वारा निर्देशित है। उदाहरण के लिए, 1970 के दशक के दौरान कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निर्धारित विनिमय दरों और उच्च मुद्रास्फीति की ब्रेटन-वुड्स प्रणाली के पतन की पृष्ठभूमि में मुद्रा आपूर्ति को सांकेतिक साधन के रूप में पसंद किया गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, हालांकि, मौद्रिक लक्ष्य और मुद्रास्फीति जैसे लक्ष्य चरों के बीच बढ़ते डिस्कनेक्ट के कारण मौद्रिक लक्ष्य ढांचे वाले कई उन्नत देशों का अनुभव संतोषजनक नहीं था। 1990 के दशक में भारतीय संदर्भ में भी मनी डिमांड फंक्शन में इसी तरह की अस्थिरता सामने आई थी, जिसके कारण 1998 में मौद्रिक लक्ष्य से कई संकेतकों के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ था।

1990 के दशक की शुरुआत में, न्यूजीलैंड से शुरू करते करते हुए 1990 में, कई उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने मुद्रास्फीति लक्ष्य को पसंदीदा नीति ढांचे के रूप में अपनाया। हालांकि, भारत ने 2016 में औपचारिक रूप से रूपरेखा को अपनाया जिससे हमें विभिन्न देशों के लंबे समय से विविध अनुभवों से सीखने में मदद मिली। वास्तव में, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के अनुभव ने मौद्रिक नीति का एकमात्र उद्देश्य मूल्य स्थिरता पर कम ध्यान देने की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया, जिसने मैक्रो-वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। इस उपलब्धि में, मौद्रिक नीति के लिए वित्तीय स्थिरता एक और महत्वपूर्ण विचार के रूप में उभरा है, हालांकि अभी भी निर्णायकों को यह स्पष्ट नहीं है कि इसे उद्देश्य के रूप में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। यह दिलचस्प है कि

अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) के रूप में केंद्रीय बैंकिंग कार्य भारत सहित पूरे देशों में नीतिगत ढाँचों के विकास और परिशोधन के बावजूद बरकरार है।

वित्तीय बाजार विकास के अनुरूप मौद्रिक नीति का विकास

वित्तीय बाजार शेष अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौद्रिक नीति संचरण के दो चरण हैं। पहले चरण में, मौद्रिक नीति परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से अन्य बाजारों, अर्थात्, बांड बाजार और बैंक ऋण बाजार में प्रसारित किए जाते हैं। दूसरे चरण में व्यक्तियों और फर्मों के निर्णय खर्च को प्रभावित करके वित्तीय बाजार से लेकर वास्तविक अर्थव्यवस्था तक मौद्रिक नीति का प्रचार किया जाता है। वित्तीय प्रणाली में, मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित मौद्रिक परिचालन के केंद्र में है।

भारत के मामले में, 1980 के दशक से पहले मुद्रा बाजार की विशेषता थी साधनों का अभाव और गंभीरता की कमी। सीमित सहभागिता के कारण मुद्रा बाजार में चलनिधि की कमी थी, जिसकी विशेषता थी कुछ प्रमुख उधारदाता और बड़ी संख्या में पुराने आदतन उधारकर्ता। निर्धारित ब्याज दर वाले तदर्थ ट्रेजरी बिलों के साथ स्वचालित विमुद्रीकरण की उपस्थिति प्रणाली में, ट्रेजरी बिल अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन के रूप में उभर नहीं सकते थे। सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में निर्धारित ब्याज दरों और सीमित निवेशक आधार ने मौद्रिक नियंत्रण के प्रभावी साधन के रूप में खुले बाजार के संचालन को बाधित किया। सहभागिता पर प्रतिबंधों के साथ ब्याज दर विनियमों की व्यापकता ने विभिन्न बाजार क्षेत्रों के एकीकरण पर रोक लगा दी जो प्रभावी मौद्रिक नीति प्रसारण के लिए आवश्यक है। इस माहौल में, मौद्रिक नीति शुरू में मुख्य रूप से क्रेडिट योजना और चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण और अंततः मात्रात्मक साधनों के माध्यम से मौद्रिक लक्ष्य पर निर्भर थी।

1990 के दशक की शुरुआत से वित्तीय बाजारों में सुधार हुआ, इसलिए, वित्तीय बाजारों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय प्रणाली में विभिन्न मूल्य और गैर-मूल्य नियंत्रण को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सुधार के उपायों में संरचनात्मक अड़चनों को दूर करने, नए प्रतिभागियों / साधनों को पेश करने, वित्तीय आस्तियों के मुक्त मूल्य निर्धारण, मात्रात्मक प्रतिबंधों को छुट देने, संस्थानों को मजबूत करने,

व्यापार में सुधार, क्लीयरिंग और निपटान प्रथाओं को बेहतर बनाने, अच्छे बाजार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उपायों को शामिल किया गया है। इन सुधारों के कारण धीरे-धीरे वित्तीय बाजारों में कीमत अनवेषण सरल बना और ब्याज दर एक सिग्नलिंग तंत्र के रूप में उभरा। 2000-01 में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की शुरुआत के प्रयोजन से जो चलनिधि प्रबंधन के साधन के रूप में और ओवरनाईट मुद्रा बाजार में ब्याज दरों के लिए सिग्नलिंग तंत्र दोनों के लिए यह मार्ग प्रशस्त किया गया। वैश्विक बाजारों के साथ घरेलू वित्तीय बाजारों के अधिक एकीकरण के बाद, आरबीआई ने भी घरेलू मौद्रिक नीति पर वैश्विक विकास के प्रभाव को पहचाना शुरू हुआ। वित्तीय बाजारों के विकास ने रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के बाजार आधारित साधनों का उपयोग करने और एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत मौद्रिक नीति के संचालन में वित्तीय बाजारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना का उपयोग करने में सक्षम बनाया।

हालांकि वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों ने समय के साथ गहराई और परिपक्वता हासिल कर ली थी, लेकिन केवल मुद्रा बाजार क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि व्यापक क्रेडिट बाजारों में नीतिगत दरों में बदलाव का तेजी से प्रसारण एक प्रमुख चुनौती रही। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, रिजर्व बैंक विभिन्न मॉडलों की कोशिश कर रहा है। उसी समय, नीतिगत लक्ष्य के करीब परिचालन लक्ष्य को बनाए रखने के उद्देश्य से चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अप्रैल 2016 से ठीक किया गया था। इस ढांचे के अंतर्गत, रिजर्व बैंक ने बाजार को अल्पकालिक चलनिधि स्थितियों को नीतिगत रुख के अनुरूप बनाने के लिए अपने कार्यों को ठीक करते हुए अपनी टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। यह विभिन्न परिपक्वताओं के निश्चित और परिवर्तनीय दर रेपो / रिवर्स रेपो, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और एकमुश्त खुले बाजार परिचालन - नकदी प्रबंधन बिल और विदेशी मुद्रा स्वैप द्वारा कई बार पूरक सहित कई साधनों के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

वर्तमान चुनौतियां

केंद्रीय बैंकों के लिए मौजूदा आर्थिक स्थिति का आकलन, प्रमुख चुनौतियों में से एक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वास्तविक समय में संभावित आउटपुट और आउटपुट अंतराल

जैसे प्रमुख मापदंडों का सटीक अनुमान एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, हालांकि वे मौद्रिक नीति के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल के दिनों में, कई अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव की प्रवृत्ति, वैश्विक स्पिलओवर प्रभाव तथा आपूर्ति झटकों के कारण वित्तीय चक्रों और व्यापार चक्रों के बीच अलगाव मोटे तौर पर समझाते हैं कि दुनिया भर में मौद्रिक नीति अस्थिर स्थिति में क्यों है। बहरहाल, मुद्रास्फीति में मांग में गिरावट और आपूर्ति पक्ष के आघात की वास्तविक प्रकृति पर विचार करना होगा ताकि प्रतिचक्रिय नीतियों का समय पर उपयोग किया जा सके।

इसलिए, रिज़र्व बैंक में, हम नीति निर्धारण के लिए मॉडल आधारित अनुमानों के साथ आने वाली सूचनाओं को देखते हुए आने वाले आंकड़ों और सर्वेक्षणों के आधार पर अर्थव्यवस्था के हमारे आकलन को लगातार अद्यतन करते हैं। इस दृष्टिकोण से रिज़र्व बैंक को मुद्रास्फीति में अपेक्षित मॉडरेशन द्वारा खोले गए नीति स्थान का उपयोग करने में मदद मिली और बाद में डेटा द्वारा इसकी पुष्टि होने से पहले अपेक्षित मंदी को पहचानने और उसपर शीघ्र कार्रवाई करने में मदद मिली। तथापि मौद्रिक नीति की अपनी सीमाएँ हैं। संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय उपायों को जारी रखा जा सकता है और मांग प्रोत्साहना तथा वृद्धि को बढ़ावा देकर सक्रिय किया जा सकता है। मेरे पिछले भाषणों में, मैंने कुछ संभावित वृद्धि उत्प्रेरक को उजागर किया है, जो पिछे और आगे की ओर लिंकेज के माध्यम से, वृद्धि को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दे सकते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पर्यटन, ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के प्रयास शामिल हैं। सरकार बुनियादी ढांचे के खर्च पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जो

अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्षमता को बढ़ाएगा। राज्यों को भी पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिसका उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है।

समापन टिप्पणी

भारत में मौद्रिक नीति ढांचा इस प्रकार सिद्धांत और देश प्रथाओं, अर्थव्यवस्था की बदलती प्रकृति और वित्तीय बाजारों के विकास के अनुरूप विकसित हुई है। व्यापक उद्देश्यों के भीतर, हालांकि, मुद्रास्फीति नीति, विकास और वित्तीय स्थिरता के सापेक्ष जोर मौद्रिक नीति व्यवस्थाओं में भिन्न है। यद्यपि एक अतिरिक्त नीतिगत उद्देश्य के रूप में वित्तीय स्थिरता के साथ वैश्विक अनुभव अभी भी अनसुलझा है, रिज़र्व बैंक हमेशा से ही आरबीआई अधिनियम की प्रस्तावना लागू होने के बाद से वित्तीय स्थिरता को उचित महत्व दे रहा है। बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य रिज़र्व बैंक के पास है और समय के साथ निर्धारित वैश्विक मानदंडों के अनुरूप है। हाल ही में, वित्तीय स्थिरता का ध्यान केवल विनियमन और पर्यवेक्षण तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि बैंक रहित और सेवारहित आबादी के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली की पहुंच बढ़ा रहा है।

वित्तीय समावेशन के अलावा, सुरक्षित, निर्बाध और वास्तविक समय में भुगतान और निपटान को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित है। नए सिरे से वित्तीय समावेशन और सुरक्षित भुगतान और निपटान पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य न केवल घरेलू वित्तीय प्रणाली में आम जनता के विश्वास को बढ़ावा देना है, बल्कि मूल्य स्थिरता, समावेशी विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता में सुधार करना है।

लेख

वर्ष 2019-20 में निजी कॉर्पोरेट निवेश :
सुधार के आसार

2018-19 में भारतीय विनिर्माताओं के मनोभाव
डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और केंद्रीय बैंक

वर्ष 2019-20 में निजी कॉर्पोरेट निवेश : सुधार के आसार*

इस आलेख में 2018-19 और 2019-20 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा भारत में निवेश की संभावनाओं से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और वित्तपोषण के अलग-अलग माध्यमों में पहले से स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए परिकल्पित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के आधार पर सुधार के संकेत लक्षित किए गए हैं। वित्तपोषण के प्रमुख चैनलों के माध्यम से स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं की कुल लागत (मूल्य के आधार पर) से निवेश गतिविधि की निकट भविष्य में रहने वाली दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और वर्तमान में अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की कमजोर मांग के वातावरण में, यह लेख निवेश चक्र में आमूलचूल बदलाव की शुरुआत की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

भूमिका

आर्थिक विकास निजी निवेश पर टिका होता है। विकास से जुड़े साहित्य में, निवेश को विकास के प्राथमिक वाहकों में से एक माना गया है। निवेश जीडीपी का प्रमुख घटक होता है और इस रूप में वह निवेश, श्रम उत्पादकता, क्षमता निर्माण, नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, रोजगार सृजन आदि को भी प्रभावित कर सकता है और इसीलिए इससे भावी विकास परिदृश्य के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। इस प्रकार, लघु-से मध्यम अवधि तक के आर्थिक विश्लेषण और पूर्वानुमान के उद्देश्यों से, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की समय पर जानकारी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, कंपनियों के प्रकाशित वार्षिक लेखा से निजी निवेश संबंधी वास्तविक (हार्ड) आंकड़े काफी देर से मिलते हैं, इसलिए वे अल्पकालिक विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकते। यही कारण है कि कंपनियाँ परिकल्पित कॉर्पोरेट निवेश संबंधी जानकारी जुटाने के लिए सर्वे आधारित तरीकों को उपयोग में लाती हैं (एबर्गर, 2005; औरिज़ियो और स्टेफानो, 2011; बार्न्स एंड एलिस, 2005; फेरारी, 2005; ओस्टरहोम, 2013)।

* यह आलेख सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग की प्रोगिता पी. साइकिया और आर. के. सिन्हा ने तैयार किया है। इसमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस विषय पर इससे पहले का अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन के मार्च 2019 अंक में 'वर्ष 2018-19 में निजी कॉर्पोरेट निवेश : धीमी वसूली जारी' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।

सर्वेक्षण-आधारित परिणाम वर्तमान निवेश के स्वरूप और निवेश के इरादों, जिनके निकट भविष्य में मूर्त रूप लेने की संभावना है, दोनों के आकलन के लिए बहुमूल्य साधन उपलब्ध कराते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही निवेश के इरादों के आकलन और पूर्वानुमान के लिए भारत में सर्वेक्षण कराने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। 1970 के दशक से, भारतीय रिज़र्व बैंक निजी कंपनियों के क्षेत्र की कैपेक्स योजनाओं (जो पहले से ही वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित हैं) पर नज़र रख रहा है, ताकि रंगराजन (1970) द्वारा अपनाई गई कैपेक्स के समयबद्ध चरणों वाली प्रणाली के आधार पर निवेश के इरादों से जुड़े परिदृश्य को समझा जा सके। इस तरह के लेख शुरु में इकोनॉमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली और इसके बाद (1989 से) आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किए गए थे।

निवेश के इरादों संबंधी डेटा का प्राथमिक स्रोत कैपेक्स प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषण प्रदान करने वाले जैसे, बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थान (एफआई)¹ के साथ-साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)², विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसी), रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्ड (आरडीबी) और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), फॉलो-ऑन पब्लिक पेशकश (एफपीओ) और एक वर्ष के लिए अधिकार निर्गम थे।

इस लेख में 2018-19 और 2019-20 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी योजनाओं के आधार पर निवेश के उनके इरादों पर चर्चा की गयी है। लेख को छह भागों में बांटाकर तैयार किया गया है। भाग II इसकी कार्यपद्धति और उसकी सीमाओं पर चर्चा करता है। भाग III समीक्षाधीन अवधि में स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताओं, उनके वित्तपोषण, क्षेत्र और उद्योग-वार उनके वितरण जैसे पहलुओं को रेखांकित करता है। भाग IV स्वीकृत / अनुबंधित ऋण / वित्तपोषण के चरणबद्ध प्रोफाइल से संबंधित है और कॉर्पोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है। भाग V वर्ष के दौरान किए गए निजी स्थानन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का

¹ इसमें सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी और विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल किए गए हैं जो कि परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्रियता से लगे हुए हैं यथा, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनांस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम)।

² ईसीबी में रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड (आरडीबी) शामिल हैं।

विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भाग VI में अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. क्रियाविधि

वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट परियोजनाओं का समय के अलग-अलग चरणों के आधार पर अल्पकालिक पूर्वानुमान (एक वर्ष आगे का) लगाने की पद्धति का श्रीगणेश 1970 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा किया गया था। इस पद्धति के तहत कैपेक्स के आकलन के लिए, स्वीकृत परियोजनाओं के डेटा बैंकों / एफआई से प्राप्त किए जाते हैं जिसमें ईसीबी/ एफसीसीबी/ आईपीओ/ एफपीओ/ अधिकार निर्गमों जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त वित्तपोषण के आंकड़े पूरक का कार्य करते हैं। मूल्यांकन के समय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशित फ्रेजिंग प्लान के आधार पर, वर्ष के दौरान संभावित कैपेक्स के स्तर का एक अनुमान प्राप्त होता है।

इस विश्लेषण में, भारतीय रिज़र्व बैंक में आंतरिक रूप से उपलब्ध जानकारी और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने का समुचित प्रयास किया गया है कि प्रत्येक परियोजना के केवल एक सेट की प्रविष्टि की जाए भले ही वह कई माध्यमों से वित्तपोषित हो। उन परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है जो इनमें से किसी भी माध्यम से वित्तपोषित नहीं हैं या जो ₹10 करोड़ से कम लागत वाली हैं। 51 प्रतिशत से कम निजी स्वामित्व वाली परियोजनाएं जो न्यासों, केंद्र और राज्य सरकारों की उपक्रम हैं और शैक्षणिक संस्थानों को भी इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

ये अनुमान इस धारणा के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनियां अपने प्रत्याशित खर्च की योजनाओं के अनुसार चलती हैं। हालाँकि, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के मामले में ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन ए एस) में उपलब्ध कॉर्पोरेट निश्चित निवेश के प्रत्याशित अनुमानों से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं क्योंकि कुछ प्रत्याशित पूर्वानुमान राशि एवं निवेश के समय की दृष्टि से वास्तविक निवेश में नहीं परिणत हो पाते।

III. स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंकों और एफआई ने ₹1,76,581 करोड़ की कुल लागत वाले निजी कंपनियों के 414 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। 535 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से किसी भी वित्तपोषण का लाभ नहीं उठाया,

लेकिन ईसीबी / एफसीसीबी के साथ उन्होंने ₹76,515 करोड़ की ऋण राशि का अनुबंध किया। इसी तरह, 39 कंपनियों ने किसी भी बैंक वित्त या ईसीबी / एफसीसीबी का लाभ नहीं उठाया, लेकिन घरेलू इक्विटी निर्गमों के ज़रिए अपनी कैपेक्स जरूरतों के लिए ₹609 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 988 परियोजनाओं की निवेश योजनाएं 2018-19 के दौरान तैयार की गयीं जिनकी कुल राशि ₹2,53,705 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2017-18 में 955 परियोजनाओं के तहत कुल निवेश ₹2,07,673 करोड़ था (अनुबंध: सारणी ए1-ए4)।

परियोजनाओं के आकार-वार वितरण से यह पता चलता है कि किसी विशिष्ट समयावधि में स्वीकृत अलग-अलग परियोजनाओं की लागत का वितरण किस प्रकार होता है। अनुभवजन्य परिणामों से पता चलता है कि परियोजना लागत के सांख्यिकीय वितरण एक भारी राइट टेल होता है। किसी अवधि में मंजूर परियोजनाओं की औसत लागत इस टेल की प्रकृति और प्रोफाइल से प्रेरित होती है जो आउटलाइयर्स (बड़े मूल्यों) की सापेक्ष उपस्थिति को दर्शाती है। परियोजनाओं के आकार-वार वितरण ने 2017-18 की 3 मेगा परियोजनाओं (₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की) की संख्या की तुलना में 2018-19 में कुल 5 मेगा परियोजनाओं तथा कुल परियोजना लागत में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि भी दर्शाया। वर्ष 2018-19 में कुल परियोजना लागत में हुई वृद्धि में भी इसका आंशिक योगदान रहा, अन्यथा 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कुल परियोजनाओं की संख्या में गिरावट देखी गयी। मेगा परियोजनाएं आम तौर पर लंबे समय तक चलती हैं, जैसा कि उनकी चरणबद्ध योजना में परिलक्षित होता है, और ऐसी परियोजनाओं की उपस्थिति से वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत बढ़ती है। बड़े आकार वाली -₹1,000 करोड़ से ₹5,000 करोड़ तक की - लगभग 41 परियोजनाएं थीं जिनकी हिस्सेदारी कुल परियोजना लागत की लगभग 41 प्रतिशत थी (बॉक्स 1 और अनुबंध: सारणी ए5)।

परियोजनाओं के उद्देश्य-वार पैटर्न पर दृष्टिपात करने पर यह पता चलता है कि 2018-19 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (76.9 प्रतिशत) हरित क्षेत्र (नई) परियोजनाओं में निवेश की थी, और इसके बाद मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का रहा जिसकी हिस्सेदारी कुल परियोजना लागत का 19.7 प्रतिशत थी, जो कि 2017-18 की इसकी हिस्सेदारी में अधिक है (अनुबंध: सारणी ए6)।

बॉक्स 1: परियोजना लागत का सांख्यिकीय वितरण

किसी विशेष समय अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत संयुक्त रूप से परियोजनाओं की संख्या और प्रत्येक परियोजना की राशि से प्रभावित होती है। जैसाकि पहले खंड में इंगित किया गया है, 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाएं ही केवल संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं, और इसलिए बहुत छोटी परियोजनाओं (10 करोड़ से कम वाली) की जानकारी डेटासेट में कैप्चर नहीं की जाती है।

प्रोफाइल (आकार के संदर्भ में) का अध्ययन करने के लिए, 5 साल की अवधि (2014-15 से 2018-19) के दौरान बैंकों / एफआई द्वारा अनुमोदित सभी 2,112 परियोजनाओं के सेट पर विचार किया गया। परिणामों से पता चलता है कि परियोजना लागत का सांख्यिकीय वितरण अत्यधिक असमान (विषम) है जिसमें एक भारी (मोटी) राइट टेल है और जिनका समांतर माध्य ₹332.91 करोड़ है, जो इसके 75वें प्रतिशत से बड़ा है। वितरण से पता चलता है कि लगभग 30 प्रतिशत परियोजनाओं की लागत ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ की बीच थी। अंतिम 5 प्रतिशत का अवलोकन करने से पता चलता है कि ये ₹1,480 करोड़ से ₹15,000 करोड़ की व्यापक रेंज में हैं, जो परियोजनाओं के कम बारंबारता और उनके विभिन्न आकार को दर्शाते हैं (सारणी बी1 और चार्ट बी 1)।

परियोजना लागत के डेटासेट के वितरण की फिटिंग से यह बात सामने आयी है कि 3-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उचित तरीके से डेटासेट का वर्णन करता है। 3-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की संभाव्यता घनत्व फलन को इस रूप में परिभाषित किया गया है:

$$f(x) = \exp [-1/2 \{ \ln(x-\gamma) - \mu \}^2 / \sigma] / (x-\gamma) \sigma \sqrt{2\pi}$$

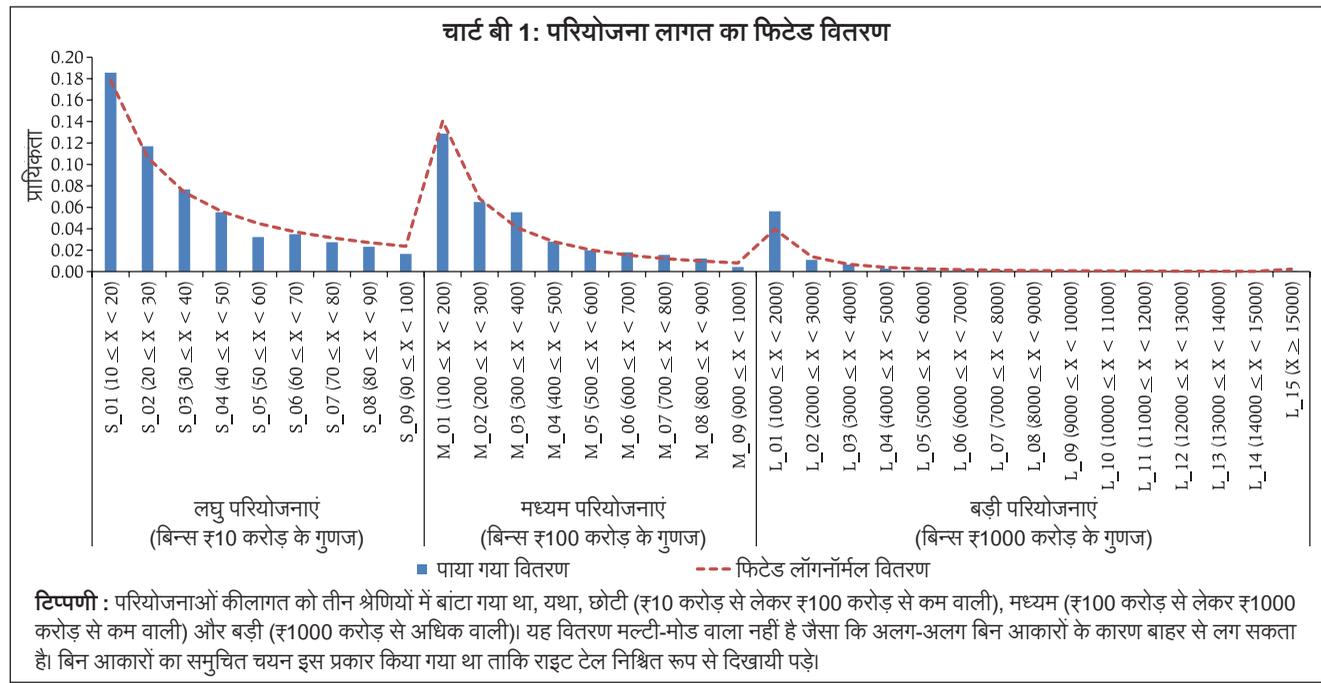
सारणी बी1 : परियोजना लागत आकार की विवरणात्मक सांख्यिकी

परियोजनाओं की संख्या	2112	25वीं प्रतिशतता (ति ₁)	24.43
माध्य	332.91	माध्यिका (ति ₂)	69.04
मानक विचलन	880.64	75वीं प्रतिशतता (ति ₃)	278.72
न्यूनतम	10.00	95वीं प्रतिशतता	1480.00
अधिकतम	15000.00	स्क्यूनेस	7.93
रेंज	14990.00	कर्टोसिस	94.66

जहां, γ , μ और σ वितरण के तीन मानदंड हैं। वितरण पारंपरिक 2-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ $\gamma=0$ में परिवर्तित हो जाता है।

अनुमानित मानदंड के साथ लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुमानित मानदंड परियोजना लागत की रूपरेखा का आकलन करने और विभिन्न प्रासंगिक संभावनाओं (उदाहरण : इसकी संभावना कि एक किसी विशेष परियोजना की लागत एक विशेष बैंड के अंतर्गत आएगी) की गणना करने में उपयोगी हो सकते हैं। तीन परीक्षण आँकड़े अर्थात, कोलमोगोरोव-स्मिरनोव, एंडरसन-डार्लिंग और ची-स्क्वायर परियोजनाओं की लागत के वितरण की प्रकृति का वर्णन करने में लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की उपयुक्तता की पुष्टि करते हैं (सारणी बी2)। इसके अलावा, संभाव्यता -संभाव्यता (पीपी) प्लॉट, 45° के कोण पर एक सीधी रेखा को दर्शाती है जो परियोजना लागत (चार्ट बी 2) के वितरण की लॉग- नॉर्मलिटी की पुनः पुष्टि करता है।

इसके अलावा, उक्त वितरण की उपयुक्तता को पहचानने और स्थापित करने के लिए, इस डेटासेट के सबसेट का वर्णन करने के लिए मापदंडों



(क्रमशः...)

सारणी बी2 : मानकों के आकलन और फिट की अच्छाई के लिए परीक्षण सांख्यिकी

मानकों के आकलन		परीक्षण सांख्यिकी	
γ	9.9083	कॉल्मोगोरोव-स्मरनोव (के एस)	0.029
μ	4.1071	एन्डडर्सन-डार्लिंग (एडी)	2.799
σ	1.9516	ची-स्क्वायर	39.665

टिप्पणी : कॉल्मोगोरोव-स्मरनोव (के एस), एन्डडर्सन-डार्लिंग (एडी) और ची-स्क्वायर परीक्षण फिट की अच्छाई की जाँच के लिए किए जाते हैं अर्थात् चयनित सैद्धांतिक वितरण कितनी अच्छी तरह इसके मूलभूत डेटासेट में फिट होता है।

का आकलन वांछनीय है, जिसके समरूप होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, 3-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दो डेटा सबसेट में रखा गया था – स्थान के अनुसार विभाजन (अर्थात्, एकल-राज्य और बहु-राज्य)। फिटिंग और अनुमानित मानदंड स्थान के आधार पर परियोजनाओं की विशेषताओं में अंतर को दर्शाते हैं। बहु-राज्य परियोजनाओं में परियोजना लागत का औसत आकार एकल-राज्य परियोजनाओं की तुलना में अधिक था। हालांकि, पहले वाले कम असमान और कम लेप्टोक्यूरेटिक (बड़े हुए) पाए जाते हैं।

गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के सापेक्ष बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रोफाइल का विश्लेषण बताता है कि बिजली, सड़कों और हवाई अड्डों के नेतृत्व में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं का हिस्सा मोटे तौर पर लगभग 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (सीमा के भीतर) रहा है राशि), हालाँकि परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में इनकी हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। अनुमानित

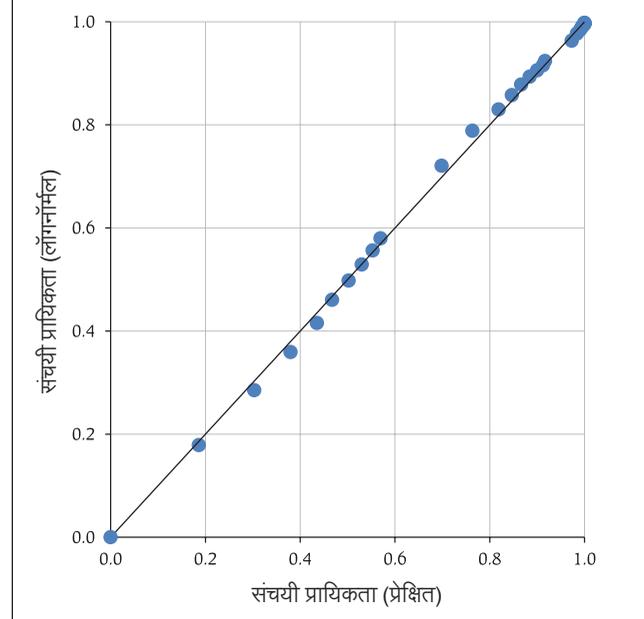
सारणी बी3 : भौगोलिक स्थिति आधारित परियोजना लागत-आकार की विवरणात्मक सांख्यिकी

सांख्यिकी	बहु-राज्यीय	एकल राज्यीय
परियोजनाओं की संख्या	72	2040
माध्य	1001.80	309.30
मानक विचलन	1284.20	853.89
माध्यिका	396.22	65.44
स्क्युनेस	2.43	8.61
कर्टोसिस	10.99	108.82

3-मानक लॉगनॉर्मल की फिटिंग

γ	12.2740	9.9044
μ	5.9003	4.0432
σ	1.7007	1.9293

चार्ट बी 2 : पीपी प्लॉट



लॉगनॉर्मल वितरण का उपयोग करके बुनियादी और गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के मध्यमान आकार क्रमशः ₹283.87 करोड़ और ₹40.30 करोड़ पाया गया, जो अनुभवजन्य आंकड़ों के ही समान है।

सारणी बी4 : इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन- इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित परियोजना लागत-आकार की विवरणात्मक सांख्यिकी

सांख्यिकी	बहु-राज्यीय	एकल राज्यीय
परियोजनाओं की संख्या	661	1451
माध्य	622.14	201.15
मानक विचलन	1084.00	733.93
माध्यिका	283.87	40.30
स्क्युनेस	5.66	11.02
कर्टोसिस	52.25	167.65

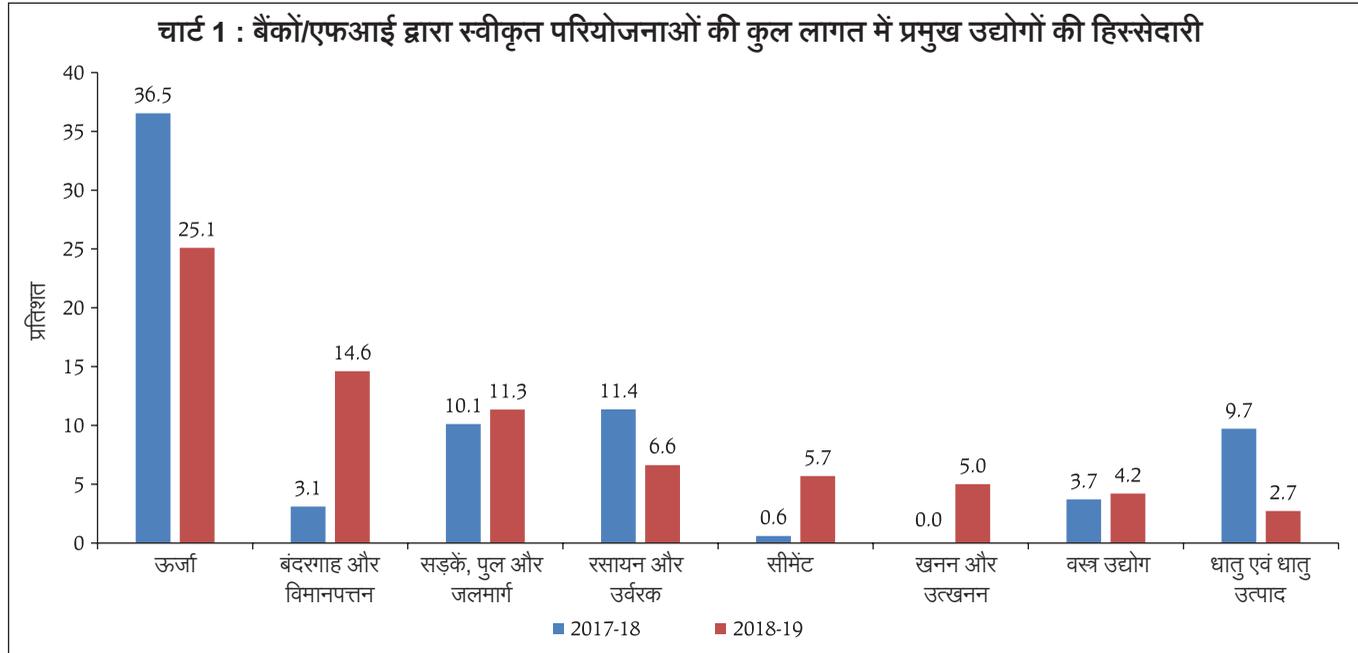
3-मानक लॉगनॉर्मल की फिटिंग

γ	5.3906	9.8992
μ	5.4444	3.5443
σ	1.5423	1.7773

उद्योग-वार देखें तो, बुनियादी ढांचा क्षेत्र जिसमें (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (iv) भंडारण और जल प्रबंधन, (v) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क, (vi) सड़क और पुल शामिल हैं, जिसकी हिस्सेदारी 2017-18 में 51.8 प्रतिशत थी, वह 2018-19 में बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गयी यद्यपि इसके

सबसे बड़े घटक, अर्थात्, 'ऊर्जा क्षेत्र' की हिस्सेदारी में भारी गिरावट हुई थी।

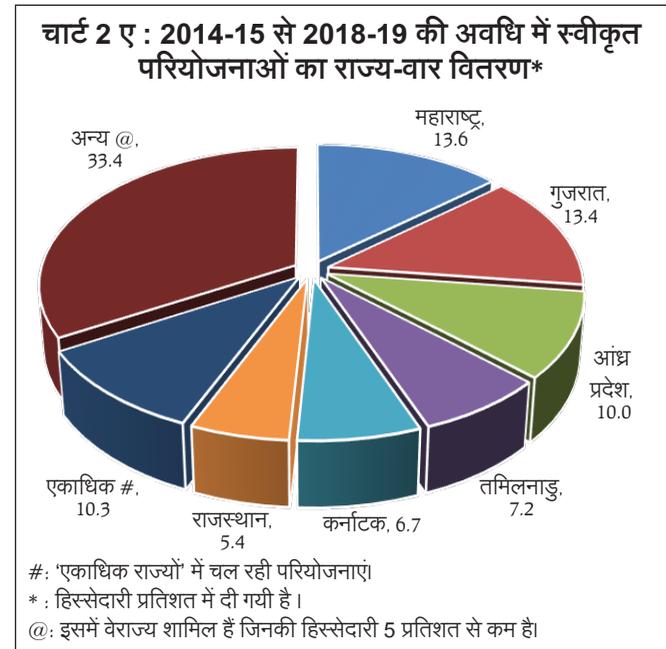
बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत के मामले में 'पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स' क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 5 परियोजनाओं में से चार 'नई' थीं और एक 'विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए थी।



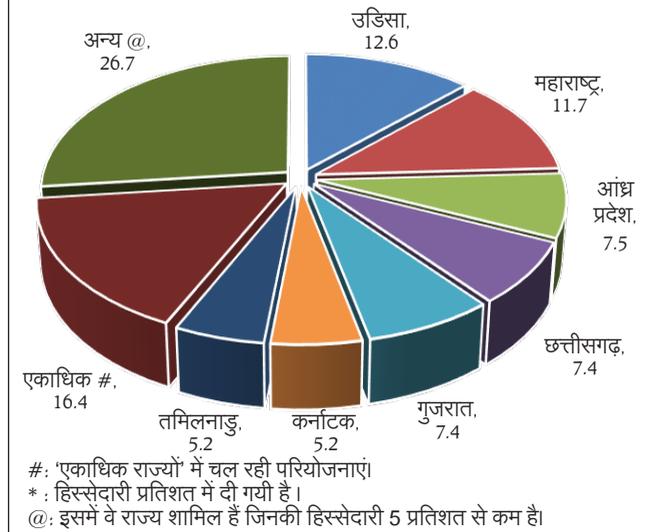
कुल परियोजना लागत में सीमेंट 'परियोजनाओं की हिस्सेदारी में 2017-18 की मामूली 0.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2018-19 में 5.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई और इससे आगामी वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विस्तार को बल मिल सकता है। "सीमेंट" उद्योग में कुल परियोजना लागत (और परियोजनाओं की संख्या) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 2017-18 के ₹1,068 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹10,138 करोड़ हो गई (संख्या क्रमशः तीन से बढ़कर ग्यारह परियोजनाएं)। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत इन ग्यारह परियोजनाओं में से आठ 'नई' थीं और तीन 'विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए थीं। हालांकि, उद्योग समूह जैसे धातु और धातु उत्पाद और विनिर्माण क्षेत्र में 2018-19 के दौरान मंदी रही जैसा कि कुल परियोजना लागत के साथ-साथ परियोजनाओं की संख्या में भी आयी भारी गिरावट से प्रकट हुआ और इसका विपरीत प्रभाव कुछ समय तक पड़ने की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में, जहाँ 'खनन और उत्खनन' की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 'रासायनिक और रासायनिक उत्पादों की हिस्सेदारी में कमी आयी। 'खनन और उत्खनन' क्षेत्र की सकल परियोजना लागत और साथ ही परियोजनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई और चार 'नई' परियोजनाओं के साथ दो अन्य परियोजनाओं का 'विस्तार और 'आधुनिकीकरण' किया गया। (चार्ट 1 और अनुबंध: सारणी ए7)

किसी परियोजना के लिए निर्णायक कारक होते हैं- परियोजना का स्थान, कच्चे माल की सुलभता, कुशल श्रम की

उपलब्धता, पर्याप्त आधारभूत संरचना, बाजार का आकार और विकास की संभावनाएं। पिछले पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के आंकड़ों से पता चला है कि 56 प्रतिशत परियोजनाएं इन छह राज्यों में थीं- आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में थीं, जिससे अन्य राज्यों की तुलना में उनकी अधिक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का संकेत मिलता है (चार्ट 2 ए)।



चार्ट 2 बी : 2009-10 से 2013-14 की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*



2009-14 की पंचवर्षीय अवधि की तुलना में 2014-19 की पंचवर्षीय अवधि में एक से अधिक राज्यों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के प्रसार में काफी गिरावट आई है। यह आंशिक रूप से इस कारण है कि कुल मेगा परियोजनाओं में बहु-राज्य मेगा परियोजनाओं (कुल ₹5,000 करोड़ और अधिक की परियोजना लागत वाली) की हिस्सेदारी कम है। 2014-19 के दौरान स्वीकृत कुल 15 मेगा परियोजनाओं में से केवल एक (6.67 प्रतिशत)

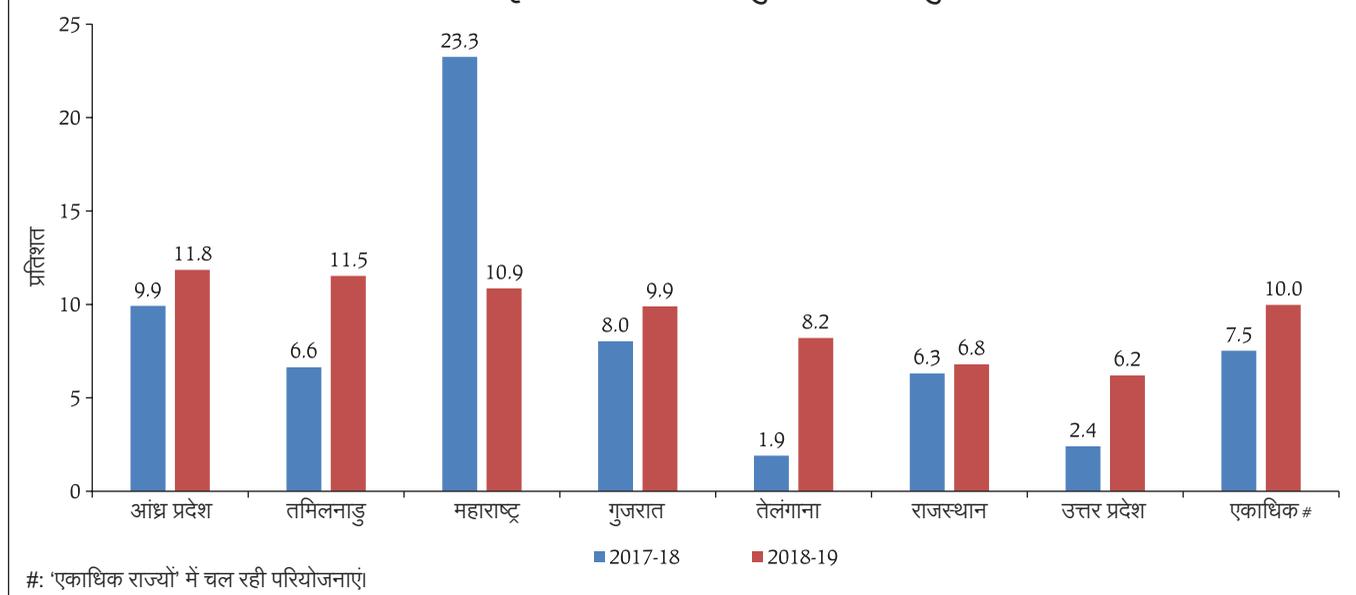
बहुराज्यीय थी जबकि 2009-14 की अवधि में कुल 63 मेगा परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं जिनमें से 09 (14.29 प्रतिशत) ऐसी थीं जो एक से अधिक राज्यों में फैली थीं (चार्ट 2 ए और चार्ट 2 बी)।

2018-19 के दौरान बैंकों / एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में सबसे अधिक हिस्सेदारी (11.8 प्रतिशत) आंध्र प्रदेश की थी जिसके बाद क्रमशः तमिलनाडु (11.5 प्रतिशत), महाराष्ट्र (10.9 प्रतिशत), गुजरात (9.9 प्रतिशत), तेलंगाना (8.2 प्रतिशत), राजस्थान (6.8 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (6.2 प्रतिशत) का स्थान है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हुई। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसके बाद तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा (चार्ट 3 और अनुबंध: सारणी ए 8)।

IV. निवेश इरादों का चरणबद्ध विन्यास

विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत अनेक परियोजनाओं में परिकल्पित कैपेक्स के चरणबद्ध प्रोफाइल की जानकारी से कैपेक्स के अल्पकालिक (एक वर्ष) पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। 2018-19 में बैंकों / एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समूह में चरणबद्धता संकेत करती है कि कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 35 प्रतिशत (₹62,561 करोड़) वर्ष 2018-19 में, 30 प्रतिशत (₹53,351 करोड़) 2019-20 में और 24 प्रतिशत (₹42,281 करोड़) बाद के वर्षों में खर्च किया जाएगा।

चार्ट 3 : बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी



वर्ष 2018-19 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 11 प्रतिशत 2015-16 से 2017-18 के दौरान पहले ही खर्च किया जा चुका है (अनुबंध: सारणी ए1)।

नियोजित व्यय में से, 2018-19 में परिकल्पित कुल कैपेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई हालांकि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूरीयों में कमी आयी थी। वर्ष 2018-19 में, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों के माध्यम से उठाए गए संसाधनों से होने वाले कैपेक्स में तीव्र वृद्धि हुई और यह एक साल पहले के अपने स्तर से लगभग 133 प्रतिशत हो गया। 2018-19 में पूंजी बाजार (इक्विटी रूट) ने ₹1,179 करोड़ के परिकल्पित कैपेक्स का वित्तपोषण किया जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था (अनुबंध: सारणी ए1, ए2, ए3)।

संक्षेप में, यह आकलन किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सभी माध्यमों से कुल मिलाकर ₹1,96,312 करोड़ (जिसमें से ₹1,11,710 करोड़ वर्ष के दौरान प्रदान की गयी नई मंजूरीयों थीं) कैपेक्स व्यय होगा जिसका मतलब होगा लगभग 24 प्रतिशत का भारी सुधार। इस सुधार का प्रमुख श्रेय कैपेक्स वित्तपोषण के ईसीबी माध्यम को दिया जा सकता है। चैनल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2019-20 में पाइपलाइन में पड़ी परियोजनाओं पर आधारित नियोजित कैपेक्स भी ₹1,20,157 करोड़ के उच्च स्तर पर रहने के पूरे आसार हैं जो पिछले वर्ष (₹84,602 करोड़) की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है (अनुलग्नक: सारणी ए2, ए4)।

आगे बढ़ते हुए, 2019-20 में संयुक्त रूप से परिकल्पित कैपेक्स 2019-20 में स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं के नए समूह द्वारा 2019-20 में किए जाने वाले कॉर्पोरेट निवेश के स्तर पर भी निर्भर करेगा। वित्तपोषण के प्रमुख चैनलों से परिकल्पित कैपेक्स और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि स्वीकृत / अनुबंधित राशि 2018-19 की पहली छमाही की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में अधिक रहेगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह ₹86,607 करोड़ से बढ़कर ₹1,25,305 करोड़ हो गई। ईसीबी के माध्यम से कैपेक्स उद्देश्य के लिए अनुबंधित कुल ऋण राशि ₹39,833 करोड़ से बढ़कर ₹61,833 करोड़ हो गई (सारणी 1)।

³ पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका है। किसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट से कैपेक्स किसी वर्ष के लिए वे परिकल्पित राशियाँ हैं जो उस वर्ष के पहले वाले वर्ष में मंजूर हो चुकी हैं।

सारणी 1 : बैंकों/एफ आई/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी/आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाएं*

	छमा.1 : 2019-20		छमा.1 : 2018-19	
	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत / अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत / अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में)
बैंकों/एफ आई	142	1,25,305	193	86,607
ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी	272	61,833	262	39,833
आईपीओ	9	78	30	481
कुल	423	1,87,216	485	1,26,921

*अंतिम आंकड़े

V. निजी स्थानन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट निवेश

हाल के वर्षों में, बॉन्ड और डिबेंचर जैसे कर्ज के लिखत तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कैपेक्स वित्तपोषण के प्रमुख वैकल्पिक स्रोत बनकर उभरे हैं। वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कर्ज के निजी स्थानन (बॉन्ड और डिबेंचर) के माध्यम से निधि संग्रह में बड़ी वृद्धि देखने को मिली परंतु 2017-18 और 2018-19 के दौरान इसमें कमी आयी। कैपेक्स वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में एफडीआई के लिए वरीयता भी देखने को मिली जिसमें 2012-13 से 2016-17 तक एफडीआई राशि में वृद्धि हुई। इसके बाद, यह 2017-18 में इसमें गिरावट आयी परंतु 2018-19 में फिर से यह बढ़ गया। 2019-20 की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जारी रही (सारणी 2)।

सारणी 2 : निजी स्थानन और एफडीआई (₹ करोड़ में)

अवधि	कर्ज- निजी स्थानन*	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**
2011-12	27,040	1,65,146
2012-13	59,188	1,21,907
2013-14	56,042	1,47,518
2014-15	97,358	1,81,682
2015-16	1,17,394	2,62,322
2016-17 [#]	1,53,136	2,91,696
2017-18 [#]	1,35,988	2,88,889
2018-19 [#]	1,34,540	3,09,867
छमा.1 : 2019-20 [#]	51,068	1,82,000
(छमा.1:2018-19) [#]	(55,022)	(1,55,117)

*: केवल निजी क्षेत्र की विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए

** : आवक एफडीआई में केवल इक्विटी पूंजी शामिल है

#: अंतिम आंकड़े

स्रोत : प्राइम डेटाबेस और भारत सरकार।

VI. निष्कर्ष

यह लेख 2019-20 में निवेश गतिविधियों भावी परिदृश्य के आकलन के लिए फर्मों के निवेश इरादों से जुड़े डेटा का उपयोग करता है। स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के चरणबद्ध विन्यास से निकट भविष्य में किए जाने वाले संभावित निवेश के आकलन में सहायता मिलती है। यह लेख परियोजना लागत के वितरण में काफी बड़ी राइट टेल की मौजूदगी को दर्शाता है। इसमें यह पाया गया है कि परियोजना लागत डेटा में इस सकारात्मक विषमता को लॉगनार्मल वितरण से समुचित रूप से समझा जा सकता है और इसलिए यह इस विषय से संबंधित आगे के शोध-कार्य में उपयोगी हो सकता है।

किसी वर्ष विशेष के दौरान स्वीकृत / अनुबंधित उच्च मूल्य और मेगा परियोजनाएं सभी परियोजनाओं के समूह के चरणबद्ध विन्यास को प्रभावित करती हैं। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के चलते वर्ष 2011-12 के बाद से बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत नई मेगा परियोजनाओं की संख्या कम रही है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक वित्तीय संकट से पहले या उसके आसपास जिन परियोजनाओं की घोषणा और क्रियान्वयन किया जा चुका था, उन्हें अपनी स्वीकृत निवेश योजनाओं को निष्पादित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय पूंजी मिली।

वर्ष 2019-20 में पहले के सभी वर्षों में स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर सभी स्रोतों से नियोजित या परिकल्पित कैपेक्स में उल्लेखनीय सुधार के संकेत मिलते हैं। अल्प से मध्यम अवधि में निवेश-चक्र के गति पकड़ने के आसार

हैं लेकिन यह तेजी कब तक बनी रहेगी, इस पर बारीकी से नज़र रखने की जरूरत है।

संदर्भ

Abberger, K (2005), "The Use of Qualitative Business Tendency Surveys for Forecasting Business Investment in Germany", *ifo Working Paper No. 13*, June

Aurizio, L. D. and Stefano, I. (2011), "Investment Forecasting with Business Survey Data", *Working Paper Number 832*, November, Bank of Italy.

Barnes, S. and Ellis, C. (2005), "Indicators of short-term Movements in Business Investment", *Bank of England, Quarterly Bulletin, Spring*, 30-38.

Ferrari, N (2005), "Forecasting corporate investment- An indicator based on revisions in the French Investment survey", *DESE Working Paper, October*.

Osterholm, P. (2013), "Forecasting Business Investment in the Short Term Using Survey Data", *Working Paper, Number 131*, November, National Institute of Economic Research.

Rangarajan, C. (1970), "Forecasting Capital Expenditure in the Corporate Sector", *Economic and Political Weekly, December 19*.

Reserve Bank of India: Various data releases and other publications.

अनुबंध

सारणी ए1: बैंकों/एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

मंजूरी का वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरी के वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	संशोधन/निरसन [@] के कारण परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010-11 तक				3,13,583	2,23,698	1,23,259	58,668	11,938	118	869				
2011-12	636	2,12,002	1,91,592 (9.6)	23,005	66,915	55,384	28,190	9,470	2,926					
2012-13	414	1,96,345	1,89,483 (3.5)	82	36,664	56,725	48,976	27,325	11,219	6,447	2,045			
2013-14	472	1,34,019	1,27,328 (5.0)		1,332	15,139	34,769	44,925	19,909	7,105	2,677	1,472		
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)			98	14,822	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036	
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)				3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)				1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	6,087
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)					620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	12,786
2018-19	414	1,76,581							569	6,847	10,972	62,561	53,351	42,281
कुल#				3,36,670	3,28,609	2,50,605	1,90,564	1,40,253	1,38,595	1,43,062	1,29,095	1,32,238	86,872	61,374
प्रतिशत परिवर्तन					-2.4	-23.7	-24.0	-26.4	-1.2	3.2	-9.8	2.4	*	

#: कॉलमों के योग किसी वर्ष विशेष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं जिसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें अलग-अलग वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ये प्रत्याशित अनुमान हैं, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त / प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

*: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2019-20 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे उपलब्ध नहीं हैं।

@: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निरसन का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी द्वारा निधि प्राप्त परियोजनाओं* के कैपेक्स की चरणबद्धता**

ऋणों का अनुबंध वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	कुल अनुबंधित ऋण (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010-11 तक			31,829	13,130	2,873	500							
2011-12	438	40,012		25,212	12,800	1,900	100						
2012-13	519	65,692			37,792	20,267	6,300	1,333					
2013-14	563	80,736				56,197	20,976	3,563					
2014-15	478	57,327					36,791	16,806	3,151	575	2	2	
2015-16	314	38,885						28,998	7,311	2,572	4		
2016-17	346	22,154							14,953	6,005	1,192	2	2
2017-18	419	37,896								17,822	13,054	6,484	536
2018-19	535	76,515									48,643	25,706	2,166
कुल*			31,829	38,342	53,465	78,864	64,167	50,700	25,415	26,974	62,895	32,194	2,704
प्रतिशत परिवर्तन				20.5	39.4	47.5	-18.6	-21.0	-49.9	6.1	133.2	#	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों / वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

** : रुपये में अंकित बॉण्ड (आरडीबी) 2016-17 से शामिल किए गए।

#: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2018-19 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे उपलब्ध नहीं हैं।

&: अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल किए गए हैं। ये वास्तव में प्राप्त / प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों* द्वारा निधि प्राप्त परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

इक्विटी निर्गम की अवधि ↓	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित कैपेक्स (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010-11 तक			1,923	726	95								
2011-12	21	973	153	460	360								
2012-13	25	1,135			533	494	108						
2013-14	21	454					384	70					
2014-15	24	1,078					189	557	332				
2015-16	40	4,511					11	644	2,753	849	183	71	
2016-17	29	1,159						14	471	368	163	143	
2017-18	51	1,538								419	327	787	5
2018-19	39	609									506	90	13
कुल*			2,076	1,186	988	494	692	1,285	3,556	1,636	1,179	1,091	18
प्रतिशत परिवर्तन				-42.9	-16.7	-50.0	40.0	85.7	176.9	-54.0	-27.9	#	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

#: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2019-20 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है वे उपलब्ध नहीं हैं।

&: ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त/प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/एफआई/आईपीओ/ ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी* द्वारा निधि प्राप्त परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

मंजूरी का वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2010-11 तक			3,47,335	2,37,554	1,26,227	59,168	11,938	118	869	0	-	-	-
2011-12	1,095	2,32,577	23,158	92,587	68,544	30,090	9,570	2,926	-	-	-	-	-
2012-13	958	2,56,310	84	36,664	95,050	69,737	33,733	12,552	6,447	2,045	-	-	-
2013-14	1,056	2,08,518	-	1,332	15,139	90,966	66,285	23,542	7,105	2,677	1,472	-	-
2014-15	828	1,45,658	-	-	98	14,822	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038	-
2015-16	700	1,35,177	-	-	-	3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220
2016-17	916	2,02,562	-	-	-	1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8,711	6,089
2017-18	955	2,07,673	-	-	-	-	620	15,184	12,445	81,242	54,817	30,038	13,327
2018-19	988	2,53,705	-	-	-	-	-	569	6,847	10,972	1,11,710	79,147	44,460
कुल*			3,70,577	3,68,145	3,05,058	2,69,922	2,05,112	1,90,580	1,71,164	1,57,705	1,96,312	1,20,157	64,096
प्रतिशत परिवर्तन				-0.7	-17.1	-11.5	-24.0	-7.1	-10.2	-7.9	24.5	#	

*: 2016-17 से रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) शामिल किए गए हैं।

#: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2019-20 तक स्वीकृति की संभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

&: आकलन प्रत्याशित है, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश शामिल हैं। यह वास्तव में प्राप्त/प्रयुक्त आंकड़ों से भिन्न है।

सारणी ए5: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण : 2009-10 से 2018-19

अवधि		₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ तक	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़ तक	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़ तक	₹5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2009-10	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	439 3.8	189 11.0	40 6.8	39 20.8	22 57.5	729 100 (4,09,502)
2010-11	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	412 4.4	172 10.2	42 8.6	51 29.3	20 47.5	697 100 (3,75,176)
2011-12	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	420 8.3	145 17.0	36 13.7	26 27.6	9 33.4	636 100 (1,91,592)
2012-13	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	245 4.8	119 14.6	20 7.3	23 26.8	7 46.4	414 100 (1,89,483)
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	306 8.3	115 20.0	25 13.9	21 29.1	5 28.7	472 100 (1,27,328)
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	223 9.0	65 16.6	18 14.6	19 47.8	1 12.0	326 100 (87,253)
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	214 8.6	76 20.9	34 26.0	21 38.5	1 5.9	346 100 (91,781)
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	287 5.8	180 23.3	29 11.9	40 41.7	5 17.4	541 100 (1,79,249)
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	263 5.2	149 21.0	28 10.8	42 43.9	3 19.1	485 100 (1,68,239)
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	215 4.3	115 15.8	39 15.3	40 41.1	5 23.5	414 100 (1,76,581)

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत दर्शाते हैं।
2. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।

सारणी ए6: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण : 2010-11 से 2018-19

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	नई	विस्तार और आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल
2010-11	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	454 66.8	224 30.9	6 1.8	13 0.5	697 100 (3,75,176)
2011-12	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	449 70.6	172 23.1	5 0.1	10 6.3	636 100 (1,91,592)
2012-13	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	303 84.2	107 14.7	- -	4 1.1	414 100 (1,89,483)
2013-14	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	361 65.2	95 20.1	2 -	14 14.7	472 100 (1,27,328)
2014-15	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	203 39.4	92 14.7	2 0.2	29 45.7	326 100 (87,253)
2015-16	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	260 73.6	64 14.3	3 0.1	19 12.0	346 100 (91,781)
2016-17	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	429 78.6	97 9.9	4 0.1	11 11.3	541 100 (1,79,249)
2017-18	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	396 89.0	80 9.4	2 0.1	7 1.5	485 100 (1,68,239)
2018-19	परियोजनाओं की संख्या प्रतिशत हिस्सेदारी	320 76.9	78 19.7	- -	16 3.4	414 100 (1,76,581)

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत दर्शाते हैं।
2. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।
3. -: शून्य / नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण : 2009-10 से 2018-19

उद्योग	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी																		
इन्फ्रास्ट्रक्चर	100	48.9	121	53.7	107	47.4	82	47.9	87	39.8	74	48.8	108	72.0	204	62.6	150	51.8	125	58.5
i) बिजली	75	30.7	105	46.3	82	42.4	71	39.4	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	81	25.1
ii) दूरसंचार	6	16.4	2	5.7	1	0.0	2	5.6	1	0.0	1	4.9	1	0.3	1	0.0	-	-	-	-
iii) बदरंगाह एव एयरपोर्ट	2	0.3	1	0.7	1	1.3	1	1.9	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	5	14.6
iv) भंडारण एवं जल प्रबंधन	2	0.9	1	0.0	12	0.5	-	-	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	15	5.3
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक तथा आई टी पार	15	0.6	12	1.1	11	3.2	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	6	2.2
vi) सडकें एव पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	18	11.3
रसायन एवं कीटनाशक	28	0.8	27	1.3	17	3.5	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	20	6.6
सीमेंट	29	2.8	15	2.7	9	2.0	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	11	5.7
खनन और उत्खनन	9	3.4	1	0.2	4	0.2	2	0.1	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	0.0	7	5.0
वस्त्र	77	2.2	77	2.9	94	7.0	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	29	4.2
धातु एवं धातु के उत्पाद	134	18.1	113	21.1	73	16.3	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	15	2.7
रबड़ उत्पाद	15	0.4	19	0.5	18	0.9	7	0.5	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	6	2.5
निर्माण	20	11.5	18	3.3	23	1.8	20	2.8	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	28	2.5
अस्पताल	23	0.9	22	0.6	9	0.3	17	1.4	10	0.7	2	0.1	1	0.0	22	1.1	18	1.8	15	2.3
होटल एवं रेस्तरां	56	2.6	63	3.5	51	4.6	31	3.1	29	2.7	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.9	28	1.7
फार्मास्यूटिकल्स	31	0.5	18	0.3	20	0.8	10	0.4	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.5
खाद्य पदार्थ	41	0.5	39	0.7	41	1.5	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.3
अन्य सेवाएं	2	0.0	3	0.1	4	0.1	2	0.1	8	0.8	2	0.1	-	-	3	0.1	-	-	11	1.2
अन्य विनिर्माण	18	0.5	22	0.2	22	0.4	8	0.1	15	0.7	7	0.1	9	1.4	7	0.2	9	0.7	20	0.7
परिवहन उपकरण	25	1.3	27	0.8	26	2.6	17	0.9	16	1.2	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3	5	0.7
अन्य*	121	5.6	112	8.2	118	10.5	70	5.7	79	12.6	56	7.3	52	6.0	67	3.6	56	5.9	43	3.0
कुल	729	100	697	100	636	100	414	100	472	100	326	100	346	100	541	100	485	100	414	100
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़)	4,09,502		3,75,176		1,91,592		1,89,483		1,27,328		87,253		91,781		1,79,249		1,68,239		1,76,581	

* : इनमें औषधि एव ड्रग्स, कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, कागज एवं कागज के उत्पाद, छपाई एवं प्रकाशन, रबड़, आईटी सॉफ्टवेयर, संचार एवं व्यापार सवाएँ, मनोरंजन आदि जैसे उद्योग शामिल हैं
- : कुछ नहीं/नगण्य

टिप्पणी: प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।

सारणी ए8: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण : 2009-10 से 2018-19

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी																		
आंध्र प्रदेश	73	7.1	65	11.4	52	5.1	35	5.7	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.8
तमिलनाडु	66	5.5	93	6.1	58	5.7	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.3	22	4.4	28	6.6	33	11.5
महाराष्ट्र	117	10.0	71	7.4	86	19.1	67	10.7	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	37	10.9
गुजरात	69	3.2	65	9.6	75	9.0	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	55	9.9
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.8	52	6.8	17	1.9	25	8.2
राजस्थान	23	2.9	28	0.8	49	4.9	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	20	6.8
उत्तर प्रदेश	27	0.4	32	4.6	42	7.8	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.3	22	3.7	30	2.4	29	6.2
कर्नाटक	42	1.4	40	7.2	39	12.0	20	1.6	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	33	4.7
पंजाब	23	0.4	38	1.1	37	1.7	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	14	1.8
पश्चिम बंगाल	33	2.6	29	3.3	19	4.9	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	15	1.6
मध्य प्रदेश	23	4.2	21	5.2	16	5.6	13	3.9	30	6.1	14	3.9	21	6.9	18	7.5	10	0.7	11	1.4
ओडिशा	25	13.9	25	7.4	15	6.3	10	26.8	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	3.0	9	1.3
छत्तीसगढ़	23	6.0	31	12.1	11	2.4	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.7	15	4.0	7	4.8	5	0.8
जम्मू और कश्मीर	2	0.1	3	0.1	5	0.2	10	0.2	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	12	0.4
हिमाचल प्रदेश	19	0.6	13	0.8	7	0.5	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.3	7	0.3
एकाधिक#	45	29.0	48	16.2	34	4.5	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	16	10.0
अन्य*	119	12.7	95	6.7	91	10.3	58	10.0	46	2.6	33	4.3	44	6.1	57	5.4	56	7.7	64	12.4
कुल	729	100	697	100	636	100	414	100	472	100	326	100	346	100	541	100	485	100	414	100
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)	4,09,502		3,75,176		1,91,592		1,89,483		1,27,328		87,253		91,781		1,79,249		1,68,239		1,76,581	

#: इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो एकाधिक राज्यों में चल रही हैं।

*: इसमें शेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

': सूचना उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी : प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।

2018-19 में भारतीय विनिर्माताओं के मनोभाव*

औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण के शुरुआती संकेतक – आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने का एक अत्यावश्यक साधन – के अनुसार 2018-19 के दौरान मांग की स्थितियां स्थिर होने और 2019-20 की पहली तिमाही में आशावादी विचारों में कमी आने के संकेत मिलते हैं। मांग को बढ़ाने की दिशा में किए गए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप, सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं बताते हैं कि 2019-20 की पहली तिमाही में वित्त की स्थितियां बेहतर हुई हैं। कीमतों के लिहाज से देखें तो, इनपुट लागत, विशेष रूप से कच्चे माल, में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाया जा रहा है जिसकी वजह से विक्रय की कीमतें घटी हैं। हिड्डन मार्कोव मॉडल (एचएमएम) के सांख्यिकीय आकलन पर आधारित पूर्वानुमान, सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने के जरिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) वृद्धि एवं थोकमूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का पता लगाता है।

परिचय

नीति निर्माताओं द्वारा वर्तमान आर्थिक वातावरण का आकलन करने और अल्पकालिक पूर्वानुमानों में मदद करने के लिए उपयोग किए गए साधनों की श्रेणी में, व्यावसायिक संभावना/दृष्टिकोण सर्वेक्षण का स्थान प्रमुख हो जाता है। ये सर्वेक्षण महत्वपूर्ण, हालांकि गुणवत्तापूर्ण, जानकारी देता है और साथ ही इसमें फायदा यह है कि इसकी लागत कम है एवं व्यवसाय चक्र (ओईसीडी, 2003) में आने वाले नए मोड़ के पूर्वानुमान हेतु सहज रूप से उपलब्ध होने वाला साधन है। प्रमुख उद्योगों में आर्थिक रुझान के बारे में “सुविचारित राय” प्राप्त करने के लिए इन सर्वेक्षणों का प्रगतिशील तरीके से पूरी तरह से उपयोग किया जाता है (विनसेन्ट 2006)। वर्ष 1998 में अपने त्रैमासिक औद्योगिक संभावना/दृष्टिकोण सर्वेक्षण (आईओएस) की शुरुआत के साथ, रिजर्व बैंक इस तरह के सर्वेक्षण करने में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच एक अग्रदूत के रूप में उभरा।

* यह आलेख सयान्तिका भौमिक और एस मजूमदार, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त विचार केवल लेखकों के हैं। सर्वेक्षण के आंकड़ों का नवीनतम दौर 6 फरवरी 2020 को RBI की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19415> पर जारी किया गया था। पिछला आलेख आरबीआई बुलेटिन के जनवरी 2019 के अंक में प्रकाशित हुआ था और इसे https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=17996 पर देखा जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख का दोहरा लक्ष्य है, पहला, पश्चावलोकन के लाभ के साथ आलेख में सर्वेक्षण से निकलने वाले प्रमुख संदेशों को प्रस्तुत किया गया है और इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि सर्वेक्षण के संकेतक कितनी बारीकी से संबंधित समष्टिआर्थिक समुच्चयों, मुख्यतः 2018-19 के दौरान आईआईपी और डब्ल्यूपीआई का पता लगाते हैं। दूसरे, 2000-01 की पहली तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही तक की दीर्घ समयावधि के साथ, तथा हिड्डन मार्कोव मॉडल रियेशन (एचएमएमआर) के अनोखे अर्थमितीय तकनीक को प्रयोग में लाते हुए व्यवसाय चक्रों में आने वाले नए मोड़ का पता लगाने में आईओएस की उपयोगिता।

आलेख के बाकी हिस्सों को पांच खंडों में प्रस्तुत किया गया है। खंड 2 में व्यावसायिक प्रवृत्ति संबंधी सर्वेक्षणों के अंतर-देशीय अनुभव का सार प्रस्तुत किया गया है एवं सर्वेक्षण के इनपुट का विश्लेषण करने में एचएमएमआर संबंधी साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा की गई है। खंड 3 में 2018-19 के दौरान जिन विनिर्माण परिस्थितियों के सर्वेक्षण किए गए थे उनके चुनिंदा मापदंडों के संबंध में शैलीगत तथ्यों पर निगाह डाला गया है। खंड 4 यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि आईओएस के संकेतक व्यवसाय चक्र के नए मोड़ का सटीक पूर्वानुमान करते हैं। खंड 5 अंतिम खंड है जिसमें आलेख का निष्कर्ष दिया गया है।

2. साहित्य की समीक्षा

व्यवसाय की प्रवृत्ति या दृष्टिकोण को लेकर किए जा रहे सर्वेक्षणों का इतिहास 1920 के दशक की शुरुआत से देखने को मिलता है और कई देश वर्षों से इन्हें लागू करते आ रहे हैं। कुछ शुरुआती सर्वेक्षण व्यापार संघों, जैसे, ब्रिटिश उद्योग परिसंघ और जर्मनी में इफो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा किए गए थे। जापान और बेल्जियम जैसे देशों के केंद्रीय बैंक आधिकारिक आंकड़ों के जारी होने से पहले आर्थिक स्थिति की अग्रिम जानकारी हासिल करने के लिए इस तरह के सर्वेक्षण कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य देशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में ट्रान्सिशन वाले देश और मध्य एशिया द्वारा व्यवसाय की प्रवृत्ति को लेकर पर्याप्त सर्वेक्षण किए जाते हैं, और ये उनके राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों, चाहे वे निजी हों या सार्वजनिक, द्वारा किए जाते हैं। कुछ सबसे प्रमुख व्यावसायिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण संयुक्त राज्य में कॉन्फ्रेंस बोर्ड और थॉम्पसन रॉयटर्स जैसे निजी संस्थानों द्वारा आयोजित और जारी किए जाते हैं।

यूरोपीय आयोग के आर्थिक और वित्तीय मामला महानिदेशालय (डीजी ईसीएफआईएन), अपने संयुक्त सुसंगत

यूरोपीय संघ (ईयू) सर्वेक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, यूरोपीय संघ और उम्मीदवार देशों के औद्योगिक प्रतिनिधियों को नियमित सर्वेक्षणों के बारे में बताते हैं। इस लीग में, सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिसर्च ऑन इकोनॉमिक टेंडेंसी सर्वे (सीआईआरईटी) - प्रमुख अर्थशास्त्रियों और संस्थाओं के लिए एक मंच जो सर्वेक्षण का संचालन और विश्लेषण करते हैं, को व्यवसाय की प्रवृत्ति को लेकर किए गए सर्वेक्षणों में हुए शुरुआती विकास के साथ-साथ हालिया सुधार के लिए श्रेय दिया जा सकता है।

व्यवसाय की प्रवृत्ति या दृष्टिकोण को लेकर किए गए सर्वेक्षणों से भिन्न प्रकार के चरों, जिसमें उत्पादन, ऑर्डर बुक, तैयार माल के स्टॉक, रोजगार और कीमत शामिल हैं, की जानकारी मिलती है। साहित्य से पता चलता है कि चूंकि इस प्रकार की श्रृंखलाओं में कोई तीव्र संशोधन नहीं होते, इसलिए वे व्यवसाय चक्र (ओईसीडी, 2003) में आने वाले नए मोड़ का अनुमान लगाने में उपयोगी होते हैं। सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाएं व्यावसायिक चक्रों की निगरानी और पूर्वानुमान में मदद करती हैं, इसलिए कई आर्थिक एजेंटों द्वारा उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डेटा सीरीज़ को आमतौर पर मौसम के अनुकूल ढाला जाता है और इस तरह की प्रतिक्रियाओं में दीर्घावधि रुझान की अनुपस्थिति को देखते हुए चक्रीय प्रोफाइल का पता लगाना आसान होता है।

इस तरह के सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए संकेतकों को प्रयोग में लाने से पहले, यह सिद्ध करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जानकारी वास्तव में व्यवसाय चक्रों का पता लगाती है। रिग्रेशन तकनीकों के लिए मार्कोव-स्विचिंग (एमएस) रिग्रेशन या हिड्डन मार्कोव मॉडल (एचएमएम)¹ अन्य तकनीकों जैसे कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वयर (ओएलएस) की तुलना में अधिक कारगर है, क्योंकि उनमें व्यवसाय चक्र के विस्तार और मंदी में असमानता का पता लगाने की क्षमता है (बर्न्स और मिशेल, 1946)।

हैमिल्टन (1989) द्वारा वृद्धि दर और व्यवसाय चक्र के मोड़ को निर्धारित करने के लिए एचएमएम के विस्तार का अध्ययन किया गया। बाद में, डाईबोल्ड एंड रुडेबश (1996), किम और नेल्सन (1998), फिलार्डो और गॉर्डन (1999),

¹ स्टेट स्पेस एस के संबंध में मौजूदा न देखी गई या हिड्डन मार्कोव श्रृंखला के मामले में पाई गई समय श्रृंखला, भिन्न-भिन्न रिग्रेशन प्लेन्स से होते हुए ऐसे चरों के सेट से संबंधित है जो साथ-साथ बदलते हैं। रिग्रेशन प्लेन, न देखी गई मार्कोव श्रृंखला की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत अलग-अलग रिग्रेशन मापदंडों वाले आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच के संबंध का चित्रण करता है (अनुबंध - 1)।

चौवेट (1998) और कैमाचो एवं अन्य (2012) ने कारक के निर्धारण में एमएस के लक्षणों को शामिल करते हुए कारक मॉडल और एमएस मॉडल की विशेषताओं को जोड़ दिया। इस तरह के भिन्न-कालिक एमएस रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग फ्रांस की अर्थव्यवस्था (बर्दाजी, 2009) के लिए प्रमुख संकेतकों के माध्यम से व्यवसाय चक्र में उतार-चढ़ाव का पता लगाने, पोलैंड में आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने (बर्नार्डेली, 2015) एवं अमेरिकी व्यवसाय चक्र में मोड़ का पता लगाने (बेलोन और सेंट-मार्टिन, 2003) के लिए किया जाता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, पिछले शोध ने पहले ही दर्शाया है कि आईओएस संबंधी प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न कारक सूचकांक भारत में विनिर्माण गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए अग्रणी संकेतक प्रदान करते हैं (अंसारी और मजूमदार, 2019)। वर्तमान काम का उद्देश्य भारतीय व्यवसाय चक्र में मोड़ का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके एमएस रिग्रेशन मॉडल के प्रयोग को परखने के माध्यम से इस क्षेत्र में मौजूदा शोध में मदद करना है।

3. वर्ष 2018-19 में आईओएस : कुछ शोधपरक तथ्य

रिज़र्व बैंक के आईओएस में ₹50 लाख से ऊपर की प्रदत्त पूंजी वाली 2,500 विनिर्माण कंपनियों का एक पैनेल शामिल है, जिसमें नवगठित कंपनियों को शामिल करने और बंद या विलय की गई कंपनियों को हटाने को लेकर आवधिक संशोधन होते रहता है। उत्तरदाताओं में उद्यमों के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मी या वित्त प्रमुख शामिल हैं और प्रतिक्रिया की दर लगभग 45-50 प्रतिशत के बीच रहती है। सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 23 मानदंडों² के संबंध में गुणात्मक प्रश्नों के जवाब मांगे गए हैं जिससे अगली तिमाही के लिए वर्तमान स्थिति के साथ-साथ दृष्टिकोण / अपेक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। स्टॉक चरों (जैसे, उत्पादन क्षमता, लंबित आदेश, क्षमता उपयोग का स्तर, इन्वेन्ट्री) पर पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से सामान्य स्थिति के साथ तुलना करने की अपेक्षा की गई है, जबकि, प्रवाह चरों (जैसे, उत्पादन में बदलाव, ऑर्डर बुक, निर्यात, आयात, वित्त की उपलब्धता) के मामले में क्रमिक प्रतिक्रियाएं, अर्थात्, पिछली तिमाही की तुलना में परिवर्तन, अपेक्षित है।

² मापदंडों में संपूर्ण व्यावसायिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, कार्यशील पूंजी वित्त आवश्यकता, वित्त की उपलब्धता, उत्पादन, ऑर्डर बुक, कच्चे माल की लागत, वित्त की लागत, इन्वेन्ट्री स्तर (कच्चे माल और तैयार माल दोनों), रोजगार, निर्यात, आयात, क्षमता उपयोग संकेतक, बिक्री मूल्य और लाभ मार्जिन आते हैं।

3.1 कार्यप्रणाली

सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए उसका एक सार तैयार किया जाता है जो शुद्ध प्रतिक्रिया (एनआर) कहलाता है और इसे आमतौर पर आशावादी और निराशावादी प्रतिक्रियाओं के अनुपात के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एनआर का मान -100 से +100 तक जा सकता है। एनआर के धनात्मक मान वृद्धि / आशावाद का संकेत देते हैं जबकि शून्य से नीचे का मान संकुचन / निराशावाद³ को दर्शाता है। शून्य मान की व्याख्या 'यथापूर्व स्थिति' के रूप में की जाती है। हालांकि, इस आलेख में समष्टिआर्थिक संकेतक लक्ष्य के साथ तुलना के लिहाज से, हमने सभी मापदंडों के एनआर को 'कमी' दर्शाने वालों की तुलना में 'वृद्धि' दर्शाने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात अधिक होने के रूप में परिभाषित करने की रीति को बनाए रखा है, इस प्रकार धनात्मक एनआर मान 'वृद्धि' को दर्शाता है और ऋणात्मक एनआर मान 'गिरावट' को दर्शाता है। इस आलेख के बाकी हिस्सों में, व्यापक प्रस्तुति के लिए एनआर के साथ "कोई परिवर्तन नहीं (एनसी)" दर्शाने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात को भी शामिल किया गया है।⁴

3.2 मांग की परिस्थितियां

उत्पादन (पीआर), ऑर्डर बुक्स (ओबी), क्षमता उपयोग (सीयू), कच्चे इन्वेन्ट्री के स्टॉक (आईएनवी) और रोजगार (ईएमपी) जैसे चुनिंदा मापदंडों पर भारतीय विनिर्माताओं के मनोभाव, अर्थव्यवस्था में कुल मांग परिस्थितियों का संकेत देते हैं।

³ आमतौर पर एनआर में वृद्धि को उत्पादन, ऑर्डर बुक, क्षमता उपयोग आदि जैसे मांग के मापदंडों, एवं बिक्री मूल्यों जैसे मूल्य संकेतकों के मामले में आशावादी माना जाता है। यद्यपि, सभी लागत संबंधित मापदंडों जैसे कच्चे माल की लागत, वित्त की लागत आदि के मामले में, एनआर में कमी आशावाद का प्रतीक है। तथापि, आलेख में इस युक्ति का उपयोग नहीं किया गया है।

⁴ यदि आई, एन और डी किसी अमुक मापदंड में वृद्धि का औसत, कोई परिवर्तन नहीं और कमी दर्शाते हैं तो एनआर = $100 \times (\text{आई} - \text{डी})$ और एनसी = $100 \times \text{एन}$ होता है। उदाहरण के लिए, यदि पिछली तिमाही की तुलना में अध्ययन चर में "वृद्धि", "कोई परिवर्तन नहीं" और "कमी" दर्शाने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात क्रमशः 15 प्रतिशत, 85 प्रतिशत और 0 प्रतिशत होते हैं, तो 15 प्रतिशत की शुद्ध प्रतिक्रिया से मालूम होता है कि उत्तरदाताओं ने, इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि अधिकांश अनुपात में "कोई परिवर्तन नहीं" को लेकर आम सहमति बनी है, अध्ययन चर में "वृद्धि" का आकलन किया है। दूसरी ओर, यदि संबंधित अनुपात 48 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 48 प्रतिशत हैं, तो इस मामले में 0 प्रतिशत की शुद्ध प्रतिक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति उत्तरदाताओं के बीच पूर्ण असहमति दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्य चर के संचलन की दिशा को लेकर अस्पष्टता रहती है। आम तौर पर, एनसी कम से कम 50 प्रतिशत होने से उत्तरदाताओं में यथा पूर्व स्थिति को लेकर अधिक स्पष्ट आम सहमति बनती है। इसलिए, अत्यधिक या निम्न मान वाले एनसी को चार्ट में दर्शाया जाता है।

2018-19 के दौरान उत्पादन के आकलन के संबंध में प्राप्त शुद्ध प्रतिक्रियाएं (एनआर-पीआर) हाल के वर्षों के चरम स्तर अर्थात् 2017-18 की चौथी तिमाही के करीब रहीं, जो इस अवधि के दौरान स्थिर मांग परिस्थितियों की ओर इशारा करती हैं। वर्ष के दौरान, एक तिमाही पहले, उत्पादन की अपेक्षाओं के संबंध में प्राप्त शुद्ध प्रतिक्रियाएं (एनआरई-पीआर) तत्पश्चात्⁵ किए गए आकलन के नतीजों के अनुरूप पाई गईं। वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही की अपेक्षाओं में थोड़ी कमी का पता चलता है। उत्पादन के संबंध में विनिर्माताओं की प्रतिक्रियाएं, जैसा एनआर-पीआर और एनआरई-पीआर से मालूम होता है, आईआईपी की त्रैमासिक वृद्धि द्वारा बताए गए रुझान की पुष्टि करती हैं (चार्ट 1ए)। उत्पादन (एनसी-पीआर और एनसीई-पीआर) के संबंध में "कोई परिवर्तन नहीं" का संकेत देने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात पूरी अवधि के दौरान 48 प्रतिशत के करीब रहा।

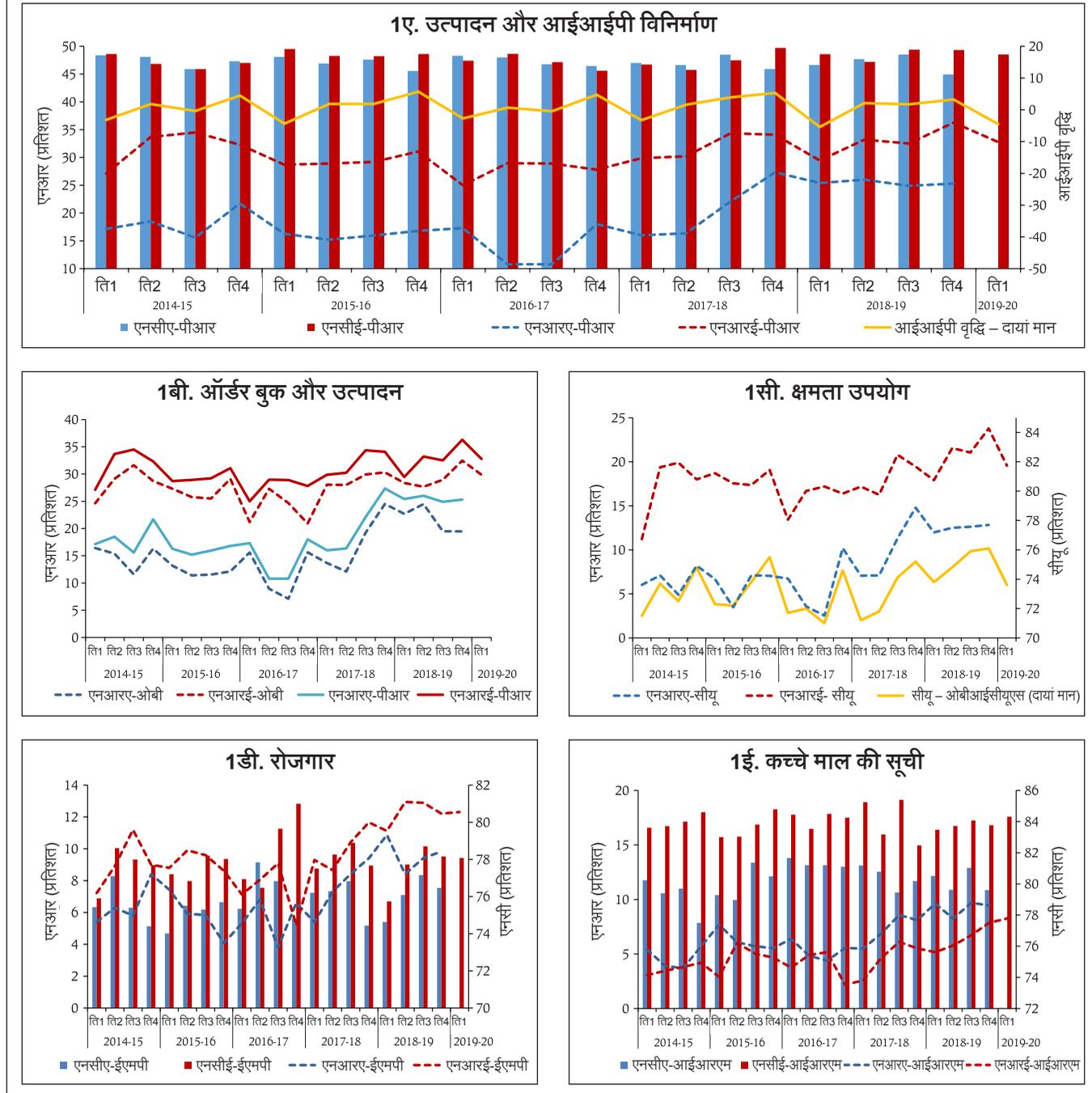
ऑर्डर बुक (ओबी) जैसी मांग के एक अन्य संकेतक के संबंध में विनिर्माताओं की धारणाओं से, प्रमुख रूप से मूल्यांकन और अपेक्षा अवधि दोनों में, उत्पादन को लेकर उनके विचारों का पता चलता है। जहां ऑर्डर बुक में 2018-19 की तीसरी तिमाही में मामूली गिरावट आई और तत्पश्चात् वह 2018-19 की चौथी तिमाही में स्थिर रहा, वहीं 2019-20 की पहली तिमाही हेतु किए गए दृष्टिकोण में चौथी तिमाही से थोड़ी कमी आई (चार्ट 1 बी)। क्षमता उपयोग, किसी उद्यम द्वारा उसकी उत्पादन प्रक्रिया में स्थापित क्षमता का वास्तविक रूप से किए गए उपयोग को रेखांकित करता है और उसे रिजर्व बैंक के मात्रात्मक सर्वेक्षण, जैसे, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए ऑर्डर बुक, इन्वेन्ट्री एवं क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के जरिए दर्ज किया जाता है। ओबीआईसीयूएस द्वारा वास्तविक सीयू को लेकर किए गए आकलन की तर्ज पर ही सीयू का आकलन किया गया, जैसा आईओएस से मालूम होता है और 2019-20 की पहली तिमाही हेतु दृष्टिकोण वास्तविक सीयू के संचलन के समरूप कम होता दिखाई देता है (चार्ट 1सी)।

⁵ एनआर-पीआर और एनआरई-पीआर उत्पादन के संबंध में मूल्यांकन और अपेक्षा की शुद्ध प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। एनसी-पीआर और एनसीई-पीआर उत्पादन के संबंध में मूल्यांकन और अपेक्षाओं की कोई परिवर्तन नहीं प्रतिक्रियाओं के अनुपात हैं। इन प्रतीकात्मक निरूपण का उपयोग इस आलेख में चर्चा किए गए अन्य सभी मापदंडों के लिए समान रूप से किए जाते हैं। इसी तरह, ऑर्डर बुक (ओबी), रोजगार (ईएमपी), कच्चे माल की सूची (आईआरएम), क्षमता उपयोग (सीयू), संपूर्ण वित्तीय स्थिति (ओएफएस), बाह्य वित्त की लागत (सीओएफ), कच्चे माल की लागत (सीआरएम), बिक्री मूल्य (एसपी), लाभ मार्जिन (पीएम) और संपूर्ण व्यावसायिक स्थिति (ओबीएस) जैसे अन्य मापदंडों के लिए समान उपाय का इस्तेमाल किया गया।

रोजगार, जो व्यवसाय की जलवायु का पता लगाने का एक और मापदंड है, को सर्वेक्षण में मापा गया है और मानदंड में कर्मचारियों के सभी संवर्ग (जैसे अंशकालिक, पूर्णकालिक और आकस्मिक मजदूर) शामिल हैं। वर्ष 2018-19 तक लगातार चार

तिमाहियों के लिए रोजगार संबंधी मनोभावों में सुधार हुआ है, जिसमें 2018-19 की दूसरी तिमाही में गिरावट आई और वह वर्ष के शेष भाग में स्थिर रहा। “कोई परिवर्तन नहीं” इंगित करने वाली प्रतिक्रियाओं का अनुपात, आम तौर पर 75 प्रतिशत के करीब,

चार्ट 1: मांग परिस्थितियों के संबंध में मनोभाव



इस मानदंड के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर हावी रहता है (चार्ट 1 डी)।

2017-18 की पहली तिमाही की शुरुआत से कच्चे माल की सूची (आईआरएम) में धीरे-धीरे वृद्धि पाई गई जो 2019-20 की पहली तिमाही के दृष्टिकोण में बनी रही। इस मानदंड को लेकर प्राप्त प्रतिक्रियाओं को मुख्य रूप से एनसी (लगभग 80 प्रतिशत पर) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है चूंकि कंपनियां सामान्यतः मांग एवं या कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव की अवधियों को छोड़कर कच्चे मालों का नियत स्तर निर्धारित करती हैं (चार्ट 1ई)।

3.3 वित्तीय स्थिति

किसी कंपनी कि वित्तीय स्थिति का मजबूत होना उसकी ताकत के साथ-साथ संपूर्ण आशावादी व्यवसाय वातावरण को दर्शाता है, जिससे निवेश को बल मिलता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, उत्तरदाताओं ने संपूर्ण वित्तीय स्थिति (ओएफएस) के संबंध में पहली तीन तिमाहियों के लिए घटते आशावाद को व्यक्त करने के साथ चौथी तिमाही में थोड़ा सुधार दर्शाया, जो 2019-20 की पहली तिमाही के दृष्टिकोण में बना रहा (चार्ट 2ए)। विनिर्माताओं ने बाह्य वित्त की लागत (सीओएफ) में वृद्धि का

संकेत दिया, जैसा 2018-19 की शुरुआत से एनआर के क्रमिक संचयन से पता चलता है, फिर भी, 2019-20 की पहली तिमाही में थोड़ी राहत का संकेत मिला (चार्ट 2बी)।

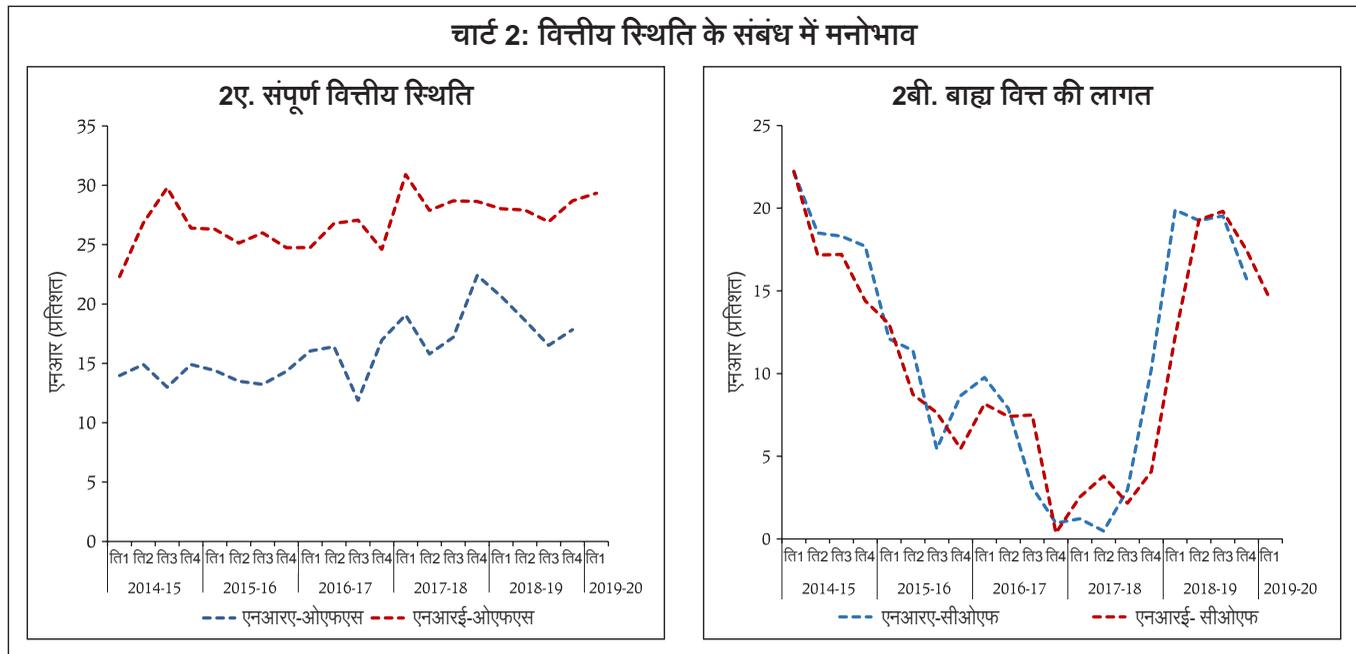
3.4 मूल्य परिदृश्य और लाभप्रदता

चुनिंदा मानदंडों, जैसे, कच्चे माल की लागत, विक्रय कीमतों एवं वेतन व्यय के संबंध में प्राप्त शुद्ध प्रतिक्रियाएं विनिर्माण क्षेत्र में कीमत परिदृश्य संबंधी मनोभाव जमा करती हैं। वर्ष 2018-19 के पूर्वार्ध में कच्चे माल की लागत (सीआरएम) अत्यधिक बढ़ी और उसके बाद कम हुई। सीआरएम के संबंध में सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाएं कच्चे माल हेतु डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में उचार-चढ़ाव पर बारीकी से नज़र रखती हैं (चार्ट 3ए)।

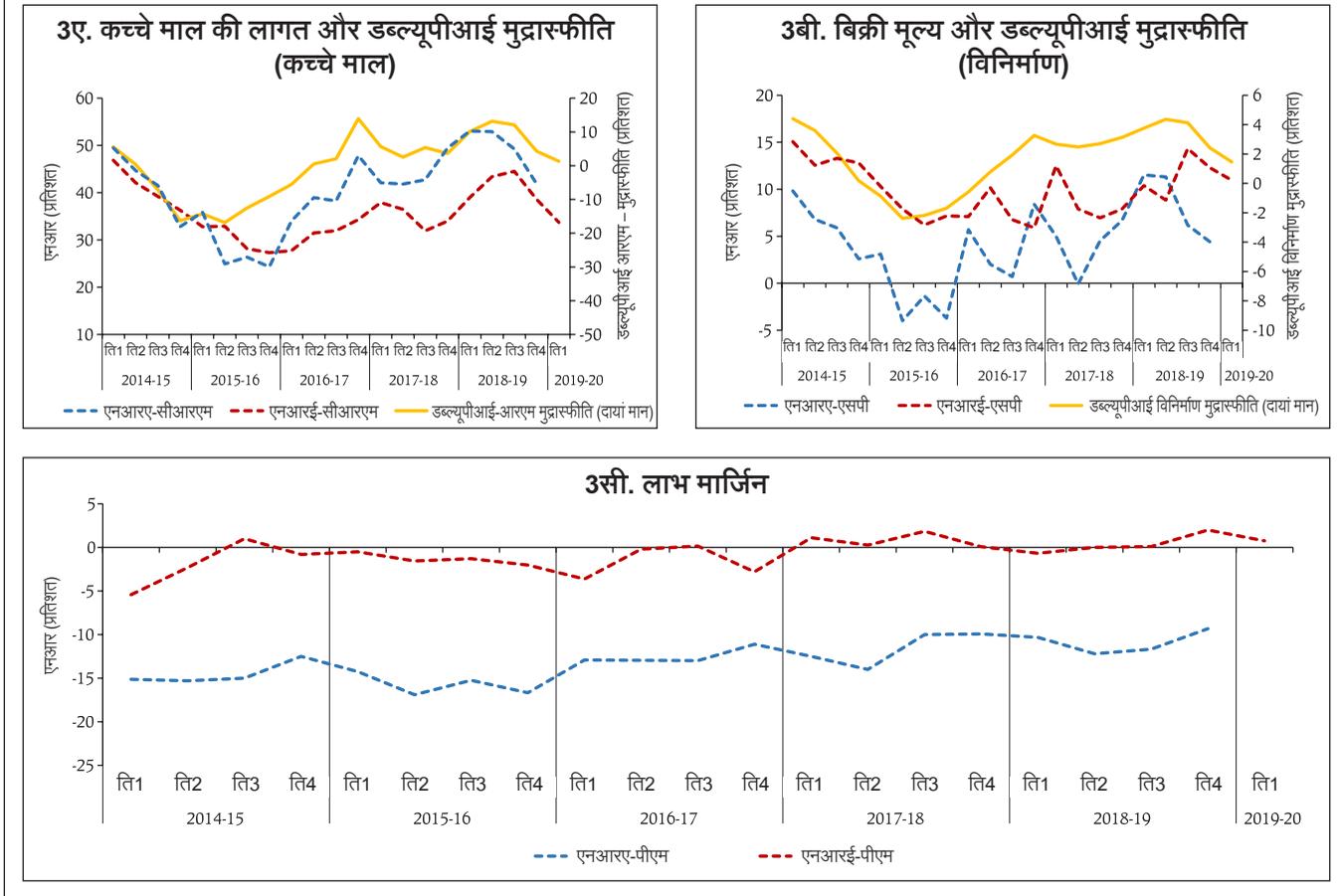
इनपुट लागत, विशेष रूप से कच्चे माल की, नर्म पड़ने से उसका लाभ ग्राहकों को पहुंचाया गया, जिस वजह से विक्रय कीमतों में कुछ हद तक कमी आई, जैसा 2018-19 की दूसरी तिमाही से विक्रय कीमतों (एसपी) के संबंध में घटते एनआर से पता चलता है (चार्ट 3बी)।

विनिर्माताओं का लाभ मार्जिन निर्धारित करने में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगी इनपुट लागतों और बिक्री मूल्यों (पूर्व-कारखाना यूनिट कीमत) के बीच का पारस्परिक प्रभाव महत्व

चार्ट 2: वित्तीय स्थिति के संबंध में मनोभाव



चार्ट 3: मूल्य परिवृश्य और लाभ मार्जिन के संबंध में मनोभाव



रखता है। वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही से लाभ मार्जिन (पीएम) (निवल बिक्री के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ) में सुधार बहुत कुछ लागत दबाव घटने की बदौलत था। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए लाभ मार्जिन को लेकर की गई अपेक्षाएं सकारात्मक बनी रहीं (चार्ट 3सी)।

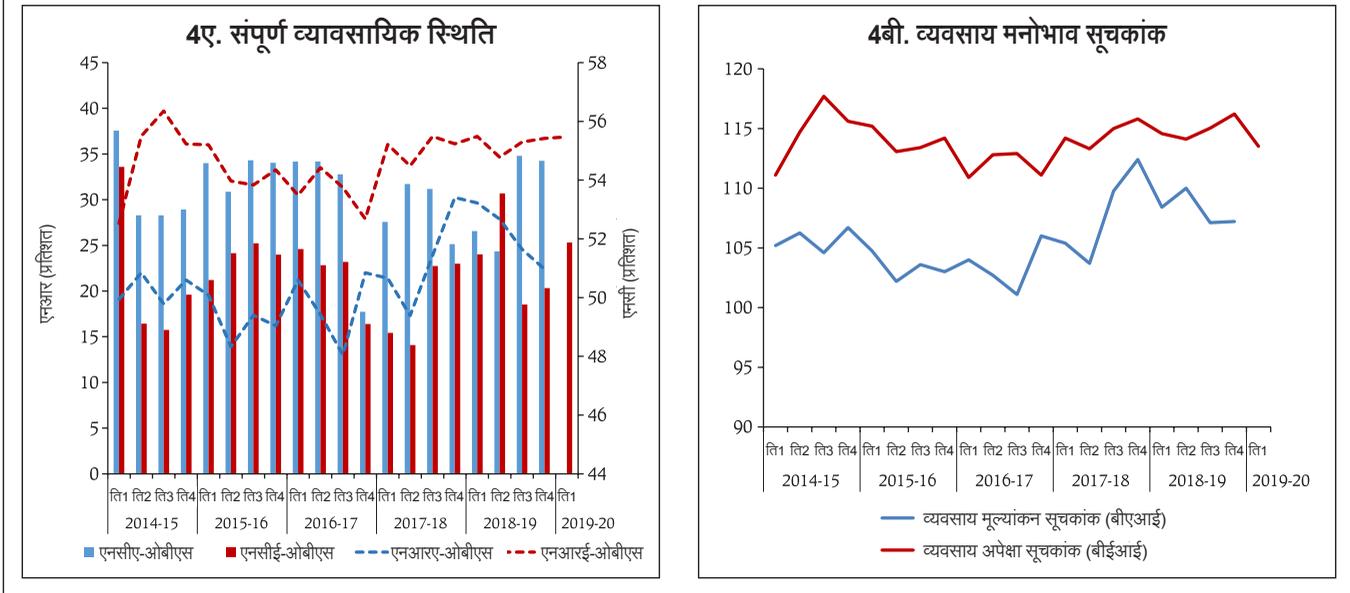
3.5 संपूर्ण व्यवसाय परिस्थितियां

सामान्य तौर पर, विनिर्माताओं ने व्यापार माहौल के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। उत्तरदाताओं में से लगभग आधे ने कहा कि 2018-19 के दौरान संपूर्ण व्यवसाय परिस्थितियां “यथा पूर्व स्थिति” बने रहने की उम्मीद की जाती है। बाकी उत्तरदाताओं की राय के आधार पर, एनआर संदर्भ अवधि के दौरान सकारात्मक बने रहे, हालांकि 2017-18 की चौथी तिमाही में वह अपने स्तर से एहतियाती तौर पर गिरा। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही का दृष्टिकोण 2017-18 की तीसरी तिमाही से अपने स्तर पर स्थिर रहा (चार्ट 4ए)।

चुनिंदा व्यावसायिक मापदंडों के संबंध में एनआर को मिश्रित सूचकांक⁶, नामतः, व्यवसाय मूल्यांकन सूचकांक (बीएआई) और व्यावसायिक अपेक्षा सूचकांक (बीईआई) में समेकित किया जाता है ताकि कम समय में व्यावसायिक वातावरण के पूर्वानुमान का चित्रण किया जा सके। रचना के अनुसार, सूचकांक 0 से 200 के बीच होता है, जिसमें 100 का आंकड़ा विस्तार को संकुचन से अलग करता है। वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में सूचकांक अपने स्तर से थोड़ा गिरा, फिर भी, पूरे 2018-19 में विस्तार के क्षेत्र में बना रहा। बीईआई 2018-19 की चौथी तिमाही में 116.2 से गिरते हुए वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 113.5 रह गया (चार्ट 4बी)।

⁶ व्यवसाय मूल्यांकन और अपेक्षा सूचकांक मिश्रित संकेतक हैं जिसे (1) संपूर्ण व्यावसायिक स्थिति; (2) उत्पादन; (3) ऑर्डर बुक; (4) कचचे माल की सूची; (5) तैयार माल की सूची; (6) लाभ मार्जिन; (7) रोजगार; (8) निर्यात; और (9) क्षमता उपयोग के संबंध में शुद्ध प्रतिक्रिया के भारित औसत (विभिन्न उद्योग समूह के जीवीए का हिस्सा) के रूप में प्राप्त किया जाता है।

चार्ट 4: संपूर्ण व्यावसायिक परिस्थितियों के संबंध में मनोभाव



4. अनुभवजन्य विश्लेषण : विनिर्माण गतिविधि की गतिशीलता का अध्ययन करने का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण

यह आकलन करने के उद्देश्य से कि शुद्ध प्रतिक्रिया (एनआर) संकेतक कितनी अच्छी तरह से व्यवसाय चक्र पर नज़र रखती है, हिड्डन मार्कोव मॉडल रिग्रेशन (एचएमएमआर) तकनीक को मौजूदा साहित्य (बर्दाजी, 2009; बर्नार्डेली, 2015; बेलोन और सेंट-मार्टिन, 2003) की तर्ज पर प्रयोग में लाया गया। सर्वेक्षण के मापदंडों और संबंधित समष्टिआर्थिक संकेतकों के बीच एक मजबूत संबंध विकसित करने के उद्देश्य से, विश्लेषण के प्रयोजनार्थ 2000-01 की पहली तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही तक के डेटा पर विचार किया गया था। अवलोकन का पूरे सैम्पल को मौसमी समायोजन के बाद प्रशिक्षण और परीक्षण सेटों में विभाजित किया गया था। अन्वेषण के प्रयोजनार्थ, एक सरल दो-व्यवस्था वाले मार्कोव मॉडल पर विचार किया गया था। विनिर्माण संबंधी मांग और कीमतों के समष्टिआर्थिक संकेतक, जैसे, विनिर्माण आईआईपी वृद्धि और विनिर्माण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति का क्रमशः उत्पादन एवं विक्रय कीमतों के एनआर के आधार पर सांख्यिकीय आकलन किया गया, ताकि अंतर्निहित मार्कोव प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था के लिए सांख्यिकीय आकलन संबंधी मापदंडों का अनुमान लगाया जा सके (अनुबंध - I)। अंतर्निहित अध्ययन न की गई मार्कोव श्रृंखला के आश्रित चरों और अवस्थाओं के लिए 2017-18 की पहली तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही तक से संबंधित आउट-ऑफ-सैम्पल

अनुमान आवर्ती आधार पर लगाए गए और प्रत्येक क्रमिक पुनरावृत्ति⁷ पर एक अतिरिक्त डेटा बिंदु शामिल किया गया।

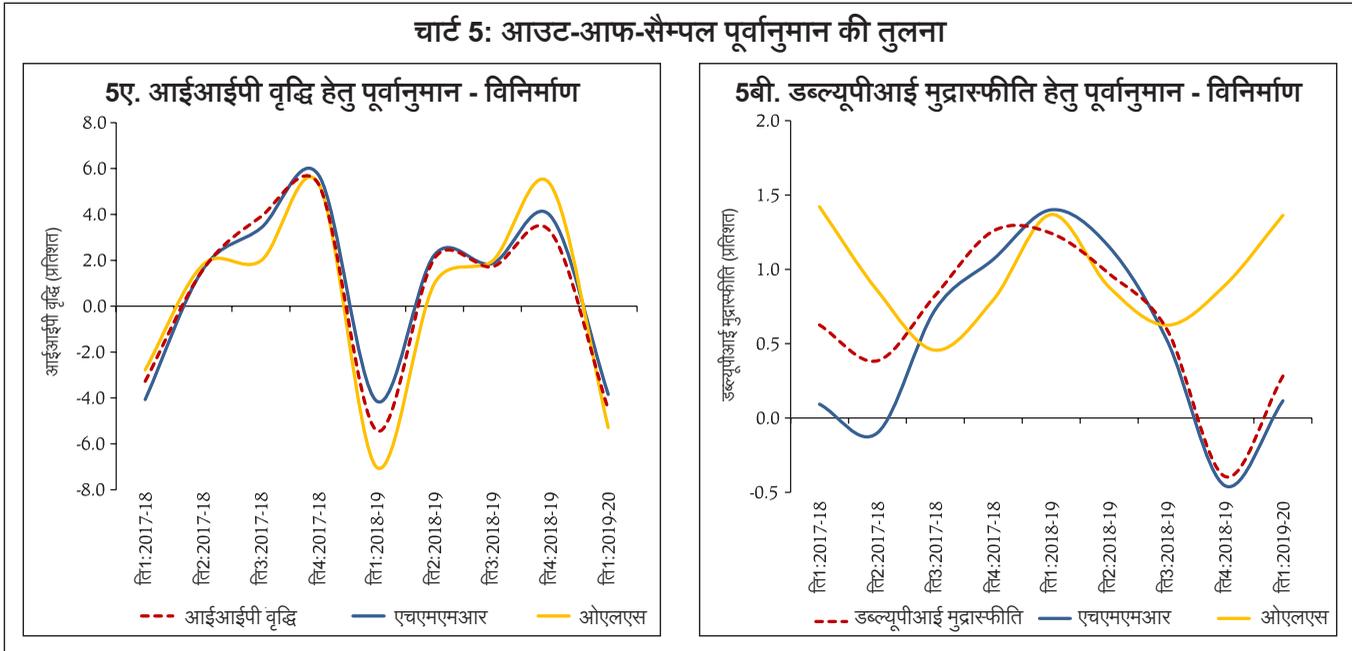
तुलना के प्रयोजन से, समान समय श्रृंखला अध्ययन पर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वयर (ओएलएस) रिग्रेशन किया गया और इसी भांति आवर्ती आधार पर आउट-ऑफ-सैम्पल पूर्वानुमान की गणना की गई थी। निष्कर्ष बताते हैं कि एचएमएमआर मॉडल ओएलएस रिग्रेशन मॉडल की तुलना में मांग और कीमतों के दोनों समष्टि संकेतकों का बेहतर पूर्वानुमान करता है (सारणी 2)। जहां एचएमएमआर और ओएलएस दोनों पर आधारित पूर्वानुमान वास्तविक विनिर्माण आईआईपी वृद्धि के अनुरूप संचलन करते पाए गए, वहीं एचएमएमआर तुलनात्मक रूप से आईआईपी पर बारीकी से नज़र रखता है (चार्ट 5ए)। दूसरी ओर, विनिर्माण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की ट्रेजेक्ट्री को एचएमएमआर पर आधारित पूर्वानुमान द्वारा अधिक सटीकता के साथ चित्रित किया गया था (चार्ट 5बी)।

सारणी 2: आउट-आफ-सैम्पल पूर्वानुमान में त्रुटि

मापदंड	रूट मीन स्क्वयर्ड ऐरर		मीन एब्जोल्यूट ऐरर	
	एचएमएमआर मॉडल	ओएलएस मॉडल	एचएमएमआर मॉडल	ओएलएस मॉडल
उत्पादन	0.63	1.19	0.51	0.94
बिक्री मूल्य	0.27	0.67	0.22	0.52

⁷ पूर्वानुमान को समष्टिआर्थिक संकेतक लक्ष्य के साथ आसानी से तुलना करने के लिए तदनु रूप मौसमी कारकों के साथ पुनर्समायोजित किया गया।

चार्ट 5: आउट-आफ-सैम्पल पूर्वानुमान की तुलना



5. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए आईओएस के चार दौरों ने आशावादी मांग परिस्थितियों का संकेत दिया, जैसा उत्पादन, ऑर्डर बुक, क्षमता उपयोग और रोजगार संबंधी मनोभावों से स्पष्ट होता है, यद्यपि, 2019-20 की पहली तिमाही का दृष्टिकोण कमतर रहा। संपूर्ण वित्तीय स्थिति, यद्यपि जिसको लेकर अधिकांश उत्तरदाताओं में आशावाद देखने को मिला, 2019-20 की पहली तिमाही में थोड़ा बेहतर होने के बाद उसमें वर्ष के दौरान धीरे-धीरे कमी आई। विनिर्माताओं ने बाह्य वित्त की लागत को लेकर हो रही चिंताओं को दूर किया। कीमतों की दृष्टि से, इनपुट लागत संबंधी मनोभावों ने उद्यमों पर घटते दबाव को दर्शाया, विशेष रूप से 2018-19 के उत्तरार्ध के दौरान, नतीजतन निम्न विक्रय कीमतों के संदर्भ में उपभोक्ताओं का बोझ हल्का हुआ। यह पाया गया है कि सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हुए एचएमएमआर मॉडल पर आधारित पूर्वानुमान विनिर्माण क्षेत्र के लिए आईआईपी वृद्धि और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव का पता लगाता है।

संदर्भ

Amstad, M. and Richard, E. (2000). "A New Approach to indicate Changes in Business Cycles in the Manufacturing Industries Using Markov Switching Models on Business Survey Indicators in Economic

Surveys and Data Analysis", *CIRET Conference Proceedings*, pp. 283-305.

Ansari, J. and Majumdar, S. (2019). "Business Sentiments and Expectations in 2017-18", *RBI Bulletin*, January.

Artis, M. J., Marcellino, M. and Proietti, T. (2004). "Dating Business Cycles: A Methodological Contribution with an Application to the Euro Area", *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 66, 537-565.

Bardaji, J., Clavel, L. and Tallet, F. (2009). "Constructing a Markov-switching Turning Point Index Using Mixed Frequencies with an Application to French Business Survey Data", *Journal of Business Cycle Measurement and Analysis*, vol. 2009/2, 111-132.

Bardaji, J. and Tallet, F. (2009). "Detecting Economic Regimes in France: A Turning Point Index using Mixed Frequency Data", *INSEE (France)*.

Baum, L.E., Petrie, T., Soules, G. and Weiss, N. (1970). "A Maximization Technique occurring in the Statistical Analysis of Probabilistic Functions of Markov Chains", *Annals of Mathematical Statistics*, 41, 164-171.

- Bellone, B. and Saint-Martin, D. (2003). "Detecting Turning Points with Many Predictors through Hidden Markov Models", *French Forecasting and Economic Analysis Directorate*.
- Dua, P. and Roy, B. (1997). "Consumer Confidence and the Probability of Recession: A Markov Switching Model", *Working Papers 47*, Centre for Development Economics.
- Duprey, T. and Klaus, B. (2017). "How to predict financial stress? An assessment of Markov switching models", *Working Papers 2057*, European Central Bank.
- Eurostat in collaboration with the Conference Board, (2017). 'Handbook of Cyclical Composite Indicators'.
- Gregoir, S. and Lenglart, F. (2000). "Measuring the Probability of a Business Cycle Turning Point by Using a Multivariate Qualitative Hidden Markov Model", *Journal of Forecasting*, 19, 81-102.
- Hamilton, J.D. (1989). 'A new approach to the economic analysis of non-stationary time series and the business cycle', *Econometrica*, 57, 357-384.
- Hansson, J., Jansson, P. and Lof, M. (2003), "Business Survey Data: Do They Help in Forecasting the Macro Economy?", *Working Papers 84*, National Institute of Economic Research.
- Kabundi, A. (2006). "Estimation of Economic Growth in France Using Business Survey Data", *Working Papers 04/69*, IMF.
- Kim, C.J. And Murray, C.J. (2002). "Permanent and Transitory Components of Recession", *Empir Econ*, 27,163-183.
- Morier, B. and Teles, V. (2016). "A Time-Varying Markov-Switching Model for Economic Growth", *Macroeconomic Dynamics*, 20, 1550-1580.
- OECD, (2003). "Business Tendency Surveys: A Handbook".
- United Nations, (2015). "Handbook on Economic Tendency Surveys".
- Zucchini, W. (2005). "Hidden Markov Models for Time Series: An Introduction Using R", 2nd ed., 370 pp., *Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group*.

अनुबंध - I

छिपा मार्कोव मॉडल रिग्रेशन (एचएमएमआर): ट्रान्सिशन प्रोबेबिलिटीस ए और स्टेट स्पेस $\{S_1, S_2, \dots, S_N\}$ के वर्तमान समरूपी अर्गाडिक मार्कोव श्रृंखला $\{Q_t\}_{t=1}^T$ के लिए एचएमएमआर मॉडल को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है :

$$Y_t = X_t^T \beta_{Q_t} + \sigma_{Q_t} \varepsilon_t \quad 1 \leq t \leq T$$

जहां, त्रुटि अवधि ε_t स्वतंत्र हैं और $N(0,1)$ के रूप में समान रूप से वितरित है।

Y_t = आईआईपी वृद्धि / डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति, X_t = उत्पादन/ बिक्री मूल्य पर एनआर, β_{Q_t} = अवस्था t से जुड़े रिग्रेशन मापदंड

आईआईपी वृद्धि और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति संबंधी सांख्यिकीय आकलनों के मामले में प्रशिक्षण सैम्पल में दिए गए मापदंड संबंधी अनुमानों को क्रमशः सारणी ए1 और ए2 में दर्शाया गया है।

मॉडल की मौलिक धारणा यह है कि किसी भी समय बिंदु पर, अवलोकन के बीच समय की निर्भरता फस्ट-आर्डर मार्कोव प्रक्रिया का पालन करने के लिए कल्पित अवस्थाओं के बीच समय-निर्भरताओं के कारण होती है। छिपा मार्कोव मॉडल के लिए, अवलोकन की सीमांत लॉग-संभावना की गणना फॉर्बर्ड-बैकवर्ड एल्गोरिथम (बॉम और अन्य 1970) के जरिए की जाती है और अपेक्षित लॉग-संभावना को बार-बार अधिकतम करके मापदंडों का अनुमान लगाया जाता है।

अवस्था का अनुमान: विटर्बी-एल्गोरिथम (जुचिनी 2005) अंतर्निहित छिपी मार्कोव अवस्था की विश्व स्तर पर व्याख्या करता है और अवलोकन किए गए डेटासेट को देखते हुए मार्कोव अवस्थाओं के सबसे संभावित अनुक्रम का अनुमान करता है। यह अवस्थाओं का अनुक्रम (s_1, s_2, \dots, s_N) निर्धारित करके किया जाता है, जो पूरे अवलोकन प्रक्रिया को देखते हुए छिपी अवस्थाओं के संयुक्त वितरण को अधिकतम करता है, अर्थात्, $\text{argmax } Pr(S_1 = s_1, S_2 = s_2, \dots, S_N = s_N / y_1, \dots, y_T, x_1, \dots, x_T)$.

व्याख्या करने के प्रयोजन से, हमने दो अवस्थाओं को लेकर प्रयास किया है, हालांकि कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य है, जो बताते हैं कि मंदी, उच्च वृद्धि और सामान्य वृद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाली इन तीन अवस्थाओं में सुधार हो सकता है (अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए किम और मुरे 2002, यूरो क्षेत्र के लिए आर्टिस और अन्य 2004)।

सारणी ए1: आईआईपी वृद्धि हेतु इन-सैम्पल मापदंड अनुमान

चर	एचएमएमआर (अवस्था 1)	एचएमएमआर (अवस्था 2)	ओएलएस ⁸
एनआरई-उत्पादन	0.010 (0.991)	0.062 (2.425)	0.061 (1.138)
कॉन्सटन्ट	0.707	-0.210	-0.637
एन	68		
आरएमएसई	1.87		1.92

टिप्पणी: कोष्ठकों में मानक त्रुटियां; अवस्था 1 निम्न वृद्धि की अवधि से संबंधित है और अवस्था 2 उच्च वृद्धि की अवधि को दर्शाता है।

प्रारंभिक अवस्था संभाव्यताओं ने अवस्था 1 को निश्चित माना, अर्थात्, संभाव्यता=1. ट्रान्सिशन मैट्रिक्स इस प्रकार है :

	अवस्था 1	अवस्था 2
अवस्था 1	0.965	0.035
अवस्था 2	0.034	0.966

सारणी ए2: डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति हेतु इन-सैम्पल मापदंड अनुमान

चर	एचएमएमआर (अवस्था 1)	एचएमएमआर (अवस्था 2)	ओएलएस
एनआरई-बिक्री मूल्य	-0.015 (0.034)	0.026 (0.007)	0.022 (0.015)
कॉन्सटन्ट	1.306	-1.674	-1.448
एन	68		
आरएमएसई	0.62		0.87

टिप्पणी: कोष्ठकों में मानक त्रुटियां; अवस्था 1 निम्न मुद्रास्फीति की अवधि से संबंधित है और अवस्था 2 उच्च मुद्रास्फीति की अवधि को दर्शाता है।

प्रारंभिक अवस्था संभाव्यताओं ने अवस्था 1 को निश्चित माना, अर्थात्, संभाव्यता=1. ट्रान्सिशन मैट्रिक्स इस प्रकार है :

	अवस्था 1	अवस्था 2
अवस्था 1	0.632	0.368
अवस्था 2	0.063	0.937

⁸ ओएलएस रिग्रेशन मॉडल का मूल्यांकन संबंधित समष्टिआर्थिक चरों के एक-चौथाई, दो-चौथाई, तीन-चौथाई और चार-चौथाई वृद्धि पर किया गया था। इन-सैम्पल अनुमान के निम्नतम त्रुटि उपायों के आधार पर, अध्ययन के उद्देश्य से मांग और मूल्य के समष्टि संकेतकों की एक-चौथाई वृद्धि का सांख्यिकीय आकलन सर्वेक्षण से प्राप्त संबंधित एनआर के साथ किया गया।

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और केंद्रीय बैंक*

डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) और ब्लॉकचेन ने वित्तीय क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों के समाधान की पेशकश करने के लिए सुविधाओं और जटिलता में काफी प्रगति किया है। कुछ केंद्रीय बैंकों ने डीएलटी का अध्ययन करने और समझने एवं उनके संचालन और वित्तीय प्रणालियों के लिए संभावित फ़ायदों का पता लगाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं। मौजूदा प्रणाली की कार्यप्रणाली के साथ डीएलटी प्लेटफार्मों में अंतर-बैंक निपटान के संचालन, डिजिटल आस्तियों और टोकन के निपटान तथा सीमा पार से भुगतान की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अब तक इन परियोजनाओं में से अधिकांश प्रयोगात्मक रूप से ही रहे हैं। भारतीय संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के विनियामक सैंडबॉक्स और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए बढ़ता समर्थन नई अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, जो प्रौद्योगिकी-केंद्रित संवृद्धि की गति के साथ समृद्ध होगा।

परिचय

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की चिंगारी से एक श्वेत पत्र निकला, जिसका शीर्षक था, 'बिटकॉइन: ए पीयर-टू-पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम' (नाकामोटो, 2008), जिसने वित्तीय प्रणाली में क्रांति लाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। तब से, दुनिया तेजी से बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के शुरुआती डिजाइनों से विभिन्न उद्योगों की मांगों के अनुरूप अनुकूलित ब्लॉकचेन के लिए विकसित हुई है। वर्तमान में, प्रमुख क्रिप्टोकॉरेंसी एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 2,000 से अधिक क्रिप्टोकॉरेंसी¹ हैं, और दुनिया भर में ब्लॉकचेन से संबंधित कई स्टार्ट-अप हैं। ब्लॉकचेन एक कैचवर्ड बन गया है और फिनटेक पर कोई भी चर्चा उसके संदर्भ के बिना अधूरी है। एक दशक के अंतराल में लोकप्रियता में इस तरह की वृद्धि ब्लॉकचेन द्वारा प्रदान की जाने वाली सहज क्रांतिकारी विशेषताओं और तकनीकी रूप से कुशल उद्यमियों में इसके प्रति

* यह लेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) के नलिन प्रियरंजन, डॉ. महुआ रॉय और डॉ. शरत ढल द्वारा तैयार किया गया है। इस पेपर में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को प्रतिबिंबित करें।

¹ जनवरी 2020 तक <https://www.investopedia.com/tech/most-important-cryptocurrencies-other-than-bitcoin/> पर उपलब्ध है:

आकर्षण को दर्शाती है। क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर बुलबुला फटने के कई उदाहरणों के बावजूद, वर्तमान में उनका मूल्यांकन 255 बिलियन² अमेरिकी डॉलर के आसपास है। 2017 के अंत में क्रिप्टोकॉरेंसी के मूल्यांकन में तेजी के बाद, जून 2019 में वसूली और कोरोनावायरस प्रकोप के मद्देनजर हालिया लाभ से ब्लॉकचेन और डीएलटी ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। क्रिप्टोकॉरेंसी में बढ़ी दिलचस्पी के कारण, यहां तक कि बिगटेक फर्म भी फिनटेक में जगह बना रही हैं, जो मुख्य रूप से स्टार्ट-अप्स का डोमेन था।

फिनटेक फर्म विप्रेषण और अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित समाधान पेश कर रही हैं जो तेजी से बाजार के खिलाड़ियों को बाधित और चुनौती दे रही हैं। केंद्रीय बैंक और अन्य प्राधिकरण तेजी से यह महसूस कर रहे हैं कि वे जोखिम को कम करने, धोखाधड़ी को रोकने और मौद्रिक नीति को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के मामले में इस तकनीक से लाभ उठा सकते हैं (डी मीजर, 2018)। तदनुसार, कुछ केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय स्थिरता के संरक्षण और डीएलटी का उपयोग करके वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए गैर-विघटनकारी तरीके से उद्योग को सुविधाजनक बनाने और मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है। ब्लॉकचेन और डीएलटी में लोगों के बीच भारी रुचि के बावजूद, इन उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी में एक अंतर दिखाई देता है। कई केंद्रीय बैंकों और अन्य नियामक अधिकारियों ने मुख्य रूप से इस तकनीक की जटिलता से जुड़ी विभिन्न नियामक चुनौतियों के कारण इस तकनीक को अपनाने में सावधानी दिखाई है, "मुख्य रूप से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आसपास तेजी से बढ़ रही शब्दावली और नियामकों के लिए इस अस्थिर मौखिक इलाके की चुनौतियों से" (वाल्व, 2016)। यहाँ, चार्ल्स केटरिंग के लौकिक कथन पर विचार करना उपयोगी है, 'अच्छी तरह से बताई गई समस्या आधी हल है'। यह इस दृष्टिकोण से है कि यह अध्ययन केंद्रीय बैंकों द्वारा डीएलटी और ब्लॉकचेन और उनके अनुप्रयोगों की एक सरल समझ प्रदान करने के लिए प्रेरित है और भारतीय संदर्भ में अध्ययन से सीख भी उपयोगी हो सकती है।

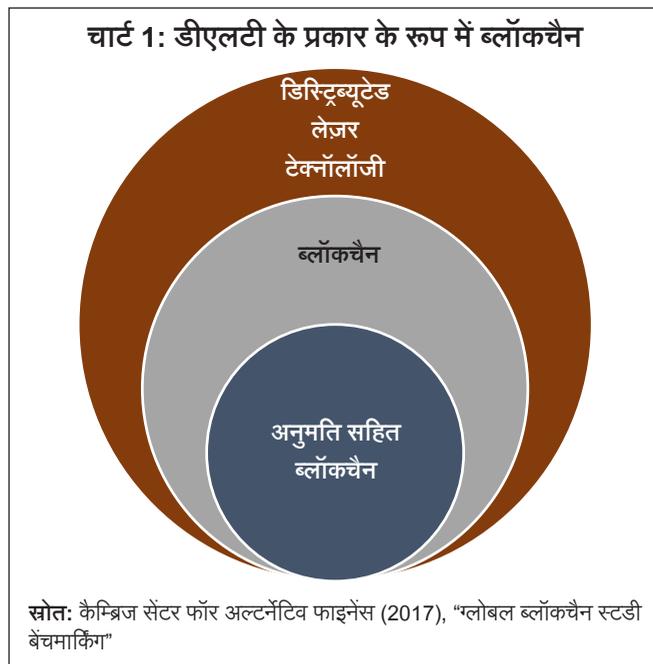
आलेख के शेष भाग को छह खंडों में बांटा गया है, जिसमें डीएलटी और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे, डीएलटी में हाल के घटनाक्रम और मुद्दे, विभिन्न केंद्रीय बैंकों, केंद्रीय बैंक डिजिटल

² 31 जनवरी, 2020 तक www.coinmarketcap.com पर उपलब्ध है:

मुद्राओं (सीबीडीसी) द्वारा कार्यान्वित डीएलटी परियोजनाएं, भारतीय वित्तीय स्थान में डीएलटी के संभावित अनुप्रयोग और निष्कर्ष शामिल हैं।

II. डीएलटी और ब्लॉकचेन की बुनियादी बातें - प्रमुख अवधारणाएं

डीएलटी और ब्लॉकचेन शब्द का इस्तेमाल अक्सर एक-दूसरे के लिए किया जाता है। हालांकि, इसके अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। ब्लॉकचेन, ब्लॉक की एक रैखिक रूप से जुड़ी श्रृंखला, डीएलटी का एक विशिष्ट प्रकार है, जबकि डीएलटी एक विकेन्द्रीकृत खाता बही है, जो उन विभिन्न प्रतिभागियों के बीच एक रैखिक श्रृंखला नहीं हो सकती है, जो कि बहीखाता की एक सामान्य स्थिति पर सहमत होते हैं और नई जानकारी/लेनदेन को मान्य करते हैं और यह खाता बही को अद्यतन करता है। इस प्रकार, सभी ब्लॉकचेन डीएलटी हैं; हालांकि, सभी डीएलटी प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन नहीं हैं (चार्ट 1)। कोई डीएलटी एक ब्लॉकचेन नहीं हो सकता है यदि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रैखिक रूप से जुड़े ब्लॉकों के रूप में नहीं है। उदाहरण के लिए, 2016 में लेमन बेयर्ड द्वारा विकसित हेडेरा हैशग्राफ³ एक ब्लॉकचेन नहीं है, लेकिन डीएलटी छतरी के नीचे आता है।



³ हेडेरा हैशग्राफ एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य हैशग्राफ कन्सेन्सस एल्गोरिथम के माध्यम से संवर्धित सुरक्षा विशेषताओं के साथ उच्च लेन-देन प्रवाह क्षमता को प्राप्त करना है। ब्लॉकचेन के विपरीत हैशग्राफ डेटा संरचना, पेड़ की शाखाओं को छांटता नहीं है, लेकिन लेजर के ढांचे में सन्निहित होता है।

डीएलटी, जैसा कि नाम से पता चलता है, नेटवर्क के सभी प्रतिभागियों के लिए एक सामान्य खाता बही का वितरण है, और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक के पास विशिष्ट शर्तों के साथ एक ही खाता है और टोकन के स्वामित्व से संबंधित जानकारी के साथ खाता को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, यह स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक रूप से साझा बही है कि कौन क्या करता है। केंद्रीकृत प्रणालियों के विपरीत जहां एक एकल इकाई डेटाबेस को बनाए रखती है, वहीं डीएलटी कई संस्थाओं को लेजर की एक प्रति संग्रहीत करने और सिस्टम के नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से लेजर को अपडेट करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। नोड द्वारा लेजर के लिए एक मान्य अद्यतन सिस्टम के अन्य सभी नोड्स के लिए नया बहीखाता बन जाता है। नेटवर्क के प्रतिभागी खाता बही को बदलने के लिए विशिष्ट नियमों से सहमत होते हैं और यह प्रक्रिया कन्सेन्सस एल्गोरिथम कहलाता है जिसके माध्यम से सभी प्रतिभागी लेन-देन को मान्य या संशोधित करते हैं। ब्लॉकचेन को डीएलटी का एक रूप माना जा सकता है जहां क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित रैखिक रूप से जुड़े सूचना-युक्त ब्लॉक प्रतिभागियों के बीच साझा किए जाते हैं। यह मूलभूत अंतर है जो प्रतिभागियों को केंद्रीकृत विश्वसनीय पक्ष की आवश्यकता के बिना डिजिटल लेनदेन में संलग्न होने की अनुमति देता है जो डीएलटी को एक उल्लेखनीय नवाचार बनाता है। डीएलटी पूरी तरह से नई तकनीक नहीं है, बल्कि क्रिप्टोग्राफी, पीयर-टू-पीयर (पी2पी) नेटवर्क और कन्सेन्सस मेकेनिज्म/एल्गोरिदम जैसी ज्ञात तकनीकों का एक संयोजन है।

II.1 क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन

ब्लॉकचेन के सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में, एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एक विशेष प्रकार का फंक्शन है जो किसी भी आकार का इनपुट लेता है और इसे एक छोटे और निश्चित आकार के आउटपुट में परिवर्तित करता है, जिसे हैश कहा जाता है। एक ही इनपुट हमेशा एक ही हैश देगा, इस प्रकार यह नियतात्मक बनाता है। यह व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि कोई किसी दिए गए हैश मान से इनपुट डेटा का अनुमान नहीं लगा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह टकराव मुक्त है, यानी, कोई भी दो इनपुट समान हैश नहीं देगा। इसके अलावा, इनपुट में एक छोटा सा परिवर्तन भी एक बहुत अलग आउटपुट उत्पन्न करता है, जो आउटपुट को क्रैक करना बहुत कठिन बना देता है (सारणी 1)।

सारणी 1: समान इनपुट्स का विभिन्न हैश आउटपुट्स

हैश फंक्शन	हैश वैल्यू
SHA256('India')	abd149214539d9f222d25de6358735b9fa0efd3956f66102b2c119ae2d9f6348
SHA256('india')	fb54e9062429a93785559529beda15c55f62c29be22267811c0e8346c14846d3

स्रोत: पाईथोन में हैशलिब लाइब्रेरी के sha256 का उपयोग करके गणना की गयी।

11.2 सार्वजनिक-निजी कुंजी क्रिप्टोग्राफी

सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में, प्रत्येक व्यक्ति के पास सार्वजनिक-निजी कुंजी जोड़ी का अपना अनूठा सेट होता है। सामग्री पर ईगल किए बिना संदेशों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्ति इच्छित प्राप्तकर्ता की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके संदेश को एन्क्रिप्ट कर सकता है, जो एन्क्रिप्टेड संदेश/दस्तावेज प्राप्त करने पर इसे स्वयं की निजी कुंजी का उपयोग करके डिक्रिप्ट कर सकता है (सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन और निजी कुंजी डिक्रिप्शन के लिए उपयोग की जाती है, हालांकि यह उल्टा में भी काम कर सकता है)। सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग सुरक्षित तरीके से संदेश को सही प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए किया जाता है, जबकि निजी कुंजी क्रिप्टोग्राफी संदेश/लेनदेन के स्रोत को सुरक्षित रूप से निर्धारित कर सकती है।

11.3 नोड्स

नोड एक नेटवर्क में बिंदु हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक इकाई नेटवर्क के साथ बातचीत करता है। किसी डीएलटी प्लेटफॉर्म में, नोड्स एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ताकि वे सूचनाओं को आगे भेज सकें या लेनदेन कर सकें। डीएलटी प्लेटफॉर्म में विभिन्न कार्यों के साथ विभिन्न प्रकार के नोड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डेलीगेटेड प्रूफ-ऑफ-स्टेक कन्सेन्सस प्रोटोकॉल पर आधारित ब्लॉकचेन में, दो प्रकार के नोड होते हैं, नियमित उपयोगकर्ता और गवाहा एक अनुमति-रहित प्रणाली में, कोई भी नेटवर्क से जुड़ सकता है और नोड बन सकता है। हालांकि, एक अनुमत प्रणाली में, कोई पूर्वनिर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही नोड बन सकता है।

11.4 टोकन

टोकन भौतिक या आभासी वस्तुओं की इकाइयाँ हैं, जो किसी वस्तु के स्वामित्व को भी व्यक्त कर सकती हैं। सैद्धांतिक रूप में, किसी भी चीज को टोकन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के टोकन जैसे कि भुगतान और उपयोगिता टोकन, इच्छित कार्य के आधार पर होते हैं। टोकनाइजेशन से तात्पर्य टोकन उत्पन्न करने से है जो डीएलटी

में किसी वस्तु का डिजिटल प्रतिनिधित्व है। ब्लॉकचेन के लिए मूल टोकन का उपयोग भुगतान टोकन के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में मूल भुगतान टोकन के रूप में बिटकॉइन टोकन है, जहां ब्लॉकचेन उनके बिटकॉइन टोकन के लेनदेन को रिकॉर्ड करता है। उपयोगिता टोकन का एक उदाहरण फाइलकॉइन है जो टोकन मालिकों को नेटवर्क पर डेटा स्टोर करने की अनुमति देता है (प्रोटोकॉल लैब्स, 2017)।

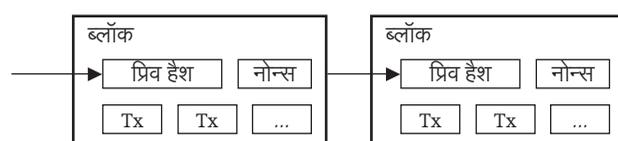
11.5 ब्लॉकचेन में ब्लॉक

ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य लेनदेन रिकॉर्ड करना है। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ब्लॉक वैध हैं और इसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। एक ब्लॉक की वैधता एक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल या कन्सेन्सस प्रोटोकॉल/मेकेनिज्म द्वारा परिभाषित की जाती है। एक ब्लॉकचेन में, ब्लॉक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का उपयोग करते हुए एक श्रृंखला की तरह रैखिक रूप से जुड़े होते हैं, जहां श्रृंखला में प्रत्येक ब्लॉक की सामग्री इसके पिछले ब्लॉक के हैश मान से शुरू होती है (चार्ट 2), इस प्रकार हैश मान के माध्यम से जुड़े ब्लॉकों की एक श्रृंखला बनती है (नाकामोटो 2008)।

11.6 प्रूफ-ऑफ-वर्क (पीओडबल्यू)

यह ब्लॉकचेन में लेनदेन की वैधता पर सहमति देने के लिए नोड्स के लिए आम सहमति तंत्र का एक प्रकार है। कन्सेन्सस एल्गोरिथ्म की अन्य श्रेणियों पर बाद में चर्चा की गयी है। पीओडबल्यू प्रोटोकॉल के तहत, नए ब्लॉकों के निर्माण की प्रक्रिया को माइनिंग और नोड्स के रूप में जाना जाता है जो माइनिंग में

चार्ट 2: ब्लॉकों की श्रृंखला



स्रोत: बिटकॉइन: पीअर-टू-पीअर इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रणाली, www.bitcoin.org पर उपलब्ध

माइनिंग के रूप में जुड़े होते हैं। यह कई कन्सेन्सस मेकेनिज्म में से एक है और इसका इस्तेमाल बिटकॉइन और इथेरियम⁴ जैसे कई ब्लॉकचेन में किया जा रहा है। इसके लिए एक गणितीय पहली को हल करने के लिए नोड्स की आवश्यकता होती है (नान्स चेंज करके ब्लॉक में ब्लॉक का हैश मान खोजें, जो एक थ्रेशोल्ड मान से कम है), जिसे केवल प्रयत्न और त्रुटि के आधार पर हल किया जा सकता है और इसलिए ब्लॉकचेन में मान्य ब्लॉक बनाने के लिए महत्वपूर्ण गणना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक निश्चित समय में जोड़े जाने वाले ब्लॉकों की संख्या को सीमित करता है जो कठिनाई सीमा को समायोजित करके प्रति 10 मिनट में एक ब्लॉक है। पीओडब्ल्यू के साथ एक बड़ी खामी यह है कि बिटकॉइन की बढ़ती कीमतों के साथ, बिटकॉइन माइनिंग के लिए बड़ी गणना ऊर्जा लगा दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली की पर्याप्त खपत होती है।

II.7 डीएलटी का उपयोग क्यों करें?

वास्तविक जीवन में, किसी वस्तु जैसे मकान, कार आदि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए, एक अधिकृत संस्था द्वारा जारी किया गया एक भौतिक दस्तावेज होता है जिसे जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है। स्वामित्व के प्रमाण के इस रूप के साथ कुछ प्रमुख मुद्दे नकली प्रमाण पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया और प्रसार हैं। डीएलटी में, प्रत्येक खाते में एक डिजिटल सार्वजनिक कुंजी और निजी कुंजी जोड़ी होती है, जिसका उपयोग हैश फंक्शन का उपयोग करके ब्लॉक पर हस्ताक्षर और एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। यह मेकेनिज्म डीएलटी संरचना की रीढ़ तैयार करता है। यहां, स्वामित्व का उल्लेख सार्वजनिक रूप से साझा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेजर में किया गया है जिसे क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकने वाला बनाया गया है। लेन-देन की प्रामाणिकता निजी कुंजी के उपयोग के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, जिसका उपयोग लेन-देन पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार यह सबूत प्रदान करता है कि यह स्वामी की ओर से आया है जिसे इसकी सार्वजनिक कुंजी जोड़ी का उपयोग करके आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।

III डीएलटी में हाल घटनाक्रम और मुद्दे

ब्लॉकचेन ने 2008 के सातोशी नाकामोतो के पेपर के साथ अपनी अवधारणा से एक लंबा सफर तय किया है। क्रिप्टोकॉरेंसी अपने अनुप्रयोगों में से पहली थी, वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों ने गति प्राप्त कर ली है। ब्लॉकचेन की पहली पीढ़ी की प्रारंभिक

कमियों में सीमित एप्लिकेशन, धीमा लेन-देन की पुष्टि, सीमित थ्रूपुट, कोई गोपनीयता नहीं और बड़ी ऊर्जा खपत शामिल हैं। इन कमियों का समाधान नई तकनीकों का उपयोग करके किया जा रहा है जैसे कि शार्डिंग, वैकल्पिक कन्सेन्सस मेकेनिज्म जैसे प्रूफ-ऑफ-स्टेक, और विशेष अनुप्रयोगों के लिए ब्लॉकचेन की अनुमति, मसलन थोक अंतर-बैंक निपटान (बैंक ऑफ कनाडा और मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट परियोजनाएं)। क्रॉस-प्लेटफॉर्म कार्यक्षमता के लिए ब्लॉकचेन के बीच अंतरसंक्रियता विकसित की जा रही है। अलग-अलग समाधानों की बढ़ती मांग ने अन्य डीएलटी प्लेटफार्मों, जैसे कि कोरम, कॉर्ड, हाइपरलेजर, आदि के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।

III.1 प्रूफ-ऑफ-स्टेक (पीओएस)

‘प्रूफ-ऑफ-वर्क’ अर्थात्, ऊर्जा की बर्बादी और लेनदेन की धीमी पुष्टि, की रुकावटों से निपटने के लिए, शोधकर्ताओं ने पीओएस आधारित कन्सेन्सस एल्गोरिदम विकसित किया है जहां टोकन रखने वाला कोई भी व्यक्ति नए ब्लॉकों के निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। पीओएस में, ब्लॉक माइनिंग नहीं किए जाते हैं बल्कि ढाले जाते हैं। ब्लॉकचेन पर नोड्स का प्रभाव सिस्टम में उनकी राशि के अनुपात में होता है। यह पीओडब्ल्यू में माइनिंग प्रक्रिया से काफी कुशल है (ब्यूटिरिन और ग्रिफिथ, 2017)।

III.2 अनुमति सहित बनाम अनुमति रहित डीएलटी

लेनदेन को प्रमाणित करने की क्षमता के आधार पर, किसी डीएलटी को अनुमति (जरूरी भाग लेने के लिए पूर्व मंजूरी) या अनुमति रहित (कोई भी भाग ले सकता है) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्यादातर पहली पीढ़ी के ब्लॉकचेन जैसे बिटकॉइन और एथेरियम अनुमति रहित हैं। अनुमति रहित डीएलटी सिस्टम अत्यधिक पारदर्शी हैं, क्योंकि हर कोई खाता वहीं पर सभी लेनदेन देख सकता है। हालांकि, वे भी काम करने में समय लेते हैं, और उन समाधानों के लिए फिट नहीं होते हैं जिनमें लेनदेन की गोपनीयता की आवश्यकता होती है। अनुमति-रहित प्रणालियों की बाधाओं से निपटने के लिए और बैंकों और कंपनियों जैसे कुछ समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, डीएलटी प्लेटफार्मों की अनुमति शुरू की गई थी। इसकी प्रकृति के अनुसार, लेन-देन को मान्य करने की पहुंच चुनिंदा एजेंटों को दी जाती है। गोपनीयता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, डीएलटी को डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि एक एजेंट केवल अपने लेनदेन को देख सके और दूसरों की नहीं। यह व्यापार और वित्तीय एजेंटों द्वारा एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है।

⁴ प्रूफ-ऑफ-स्टेक प्रोटोकॉल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव

III.3 स्मार्ट अनुबंध

ये अनुबंध मूल रूप से डीएलटी पर कोड या तर्क की लाइनें हैं जो पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद स्वयं निष्पादित करते हैं। इन्हें डिजिटल समझौतों के रूप में समझा जा सकता है जहां एक बार समझौते की शर्तें पूरी हो जाती हैं, फिर स्मार्ट अनुबंध इसे सत्यापित करता है और शर्तों के अनुसार टोकन स्थानांतरित करता है (ब्यूटिरिन, 2013)। एक स्मार्ट अनुबंध का एक सरल उदाहरण यह है कि एक बार भुगतान प्राप्त होने के बाद यह स्वचालित रूप से विभाजित हो जाता है और पूर्वनिर्धारित व्यक्तियों को भेजा जाता है। एक स्मार्ट अनुबंध अन्य स्मार्ट अनुबंधों के साथ अन्तः क्रिया कर सकता है और इस प्रकार, जटिलता के संदर्भ में विकसित होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को केंद्रीय बैंकों और अन्य संस्थानों की विभिन्न प्रयोगिक परियोजनाओं जैसे कि व्यापार वित्त, प्रतिभूतियों के निपटान, आदि में लागू किया गया है।

III.4 ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी

दुनिया में कई ब्लॉकचेन और डीएलटी प्लेटफॉर्म प्रचालनगत हैं। ये डीएलटी प्लेटफॉर्म विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए बनाए गए हैं और वांछित सेवाओं को देने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। डीएलटी की इस सुविधा की तुलना अक्सर इंटरनेट के साथ की जाती है, जो कई नेटवर्क का एक नेटवर्क है। इंटरऑपरेबिलिटी का तात्पर्य है कि एक एकल डीएलटी प्लेटफॉर्म में होने वाले लेनदेन के आधार पर, एक अन्य लेनदेन एक अलग डीएलटी प्लेटफॉर्म में होगा। बैंक ऑफ कनाडा की परियोजना जैस्पर और मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोजेक्ट यूबिन के द्वारा प्रदर्शित सीमा पार से भुगतान लेनदेन में इस तरह की

इंटरऑपरेबिलिटी उपयोगी है (बैंक ऑफ कनाडा एवं अन्य, 2018)।

III.5 डीएलटी और ब्लॉकचेन प्लेटफार्म

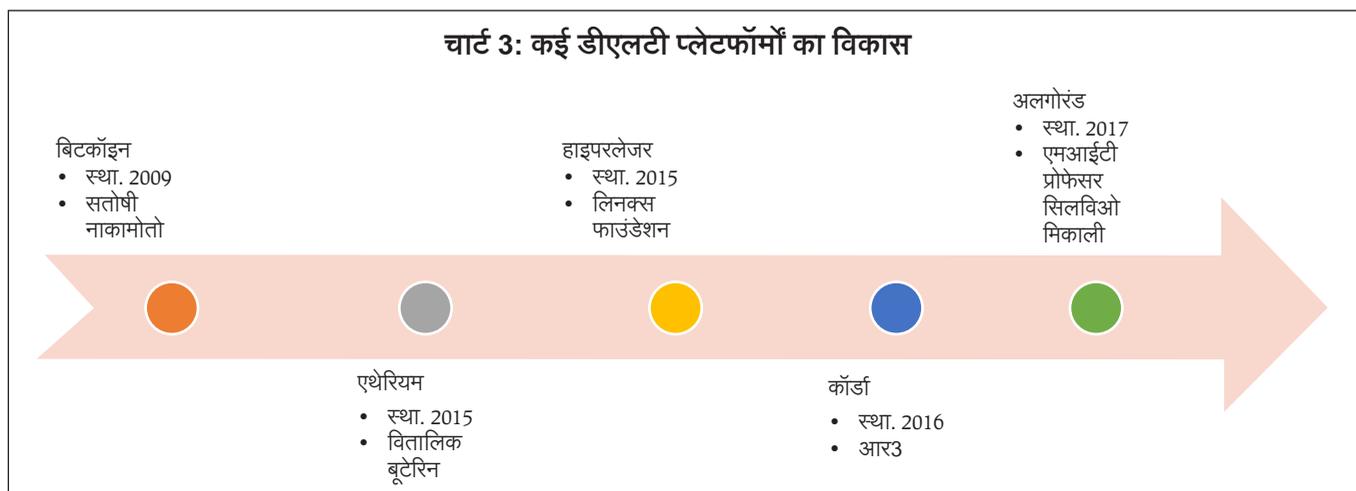
डीएलटी और ब्लॉकचेन को केवल क्रिप्टोकॉरेसी भेजने के साधन के रूप में नहीं बल्कि बड़े एप्लीकेशन्स के निर्माण के लिए प्लेटफार्मों के रूप में भी माना जाना चाहिए। प्रत्येक डीएलटी प्लेटफॉर्म, निर्माण के साथ, सुविधाओं और संबंधित फायदे और नुकसान के अपने स्वयं के सेट के साथ अद्वितीय है। इस प्रकार, शुरू किए जाने वाले एप्लीकेशन के लिए सही प्लेटफॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण है। ऐसे प्लेटफार्मों का विकास बिटकॉइन से शुरू होने वाले समयरेखा में दर्शाया गया है (चार्ट 3)।

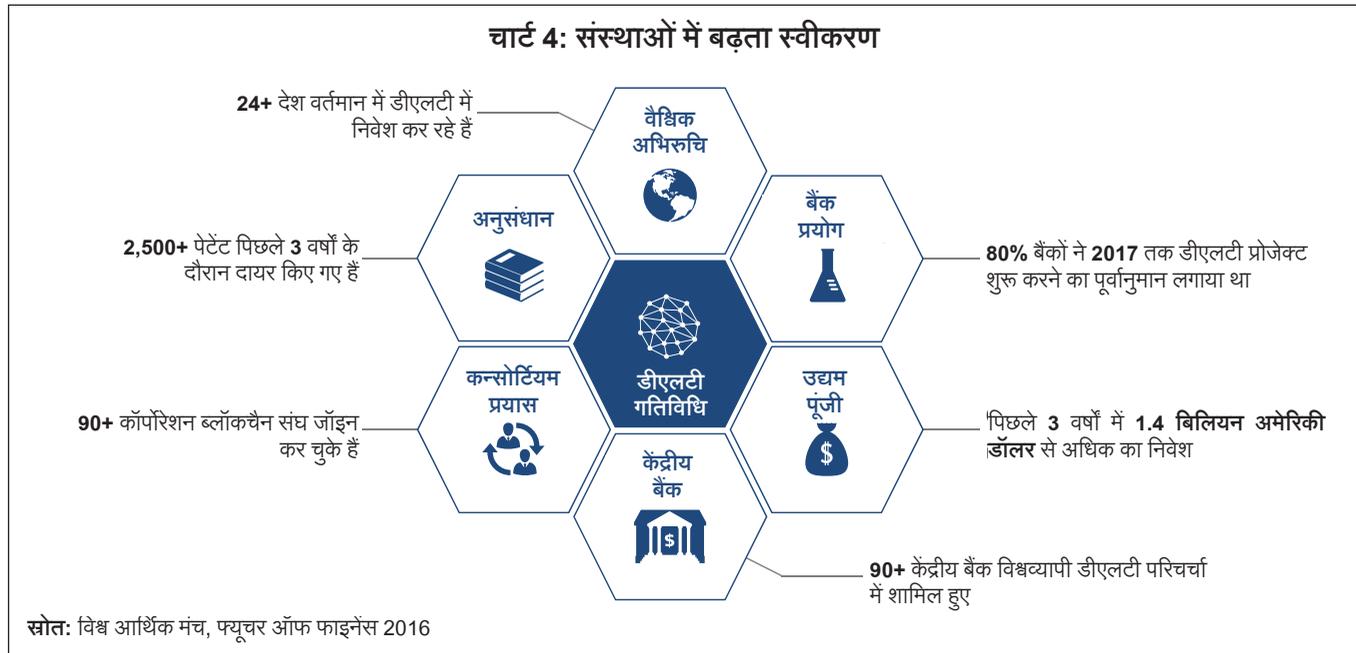
IV. केंद्रीय बैंकों में डी.एल.टी.

ब्लॉकचेन ने अपनी लोकप्रियता एक क्रिप्टोकॉरेसी बिटकॉइन से प्राप्त की। चूंकि यह निजी मुद्रा के वैकल्पिक रूप की पेशकश द्वारा केंद्रीय बैंक के डोमेन का उल्लंघन कर रहा था, जो कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का एकमात्र निर्गमकर्ता है, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने क्रिप्टोकॉरेसी द्वारा उत्पन्न जोखिमों की निगरानी करना शुरू किया। हालांकि, इन गतिविधियों की निगरानी करते हुए, केंद्रीय बैंकों ने क्रिप्टोकॉरेसी के अलावा ब्लॉकचेन-आधारित एप्लीकेशन्स में एक आशावाद और रुचि प्रदर्शित की।

अगस्त 2016 में, विश्व आर्थिक मंच (डबल्यूईएफ) ने एक रिपोर्ट 'द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर' प्रकाशित की, जिसमें संभावित तरीकों का विवरण प्रदान किया गया जिसमें ब्लॉकचेन भुगतान से लेकर इक्विटी निपटान तक के एप्लीकेशन्स के साथ वित्तीय सेवाओं को नया आकार दे सकता है (चार्ट 4)।

चार्ट 3: कई डीएलटी प्लेटफॉर्मों का विकास





केंद्रीय बैंकों ने, जिन्हें वित्तीय अवसंरचना विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, महसूस किया कि वे तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में नवाचारों को सुविधाजनक बना सकते हैं। इसके अलावा, यह भी स्वीकार किया गया कि केंद्रीय बैंकों की भागीदारी वित्तीय क्षेत्रों के लिए परिणामी क्षमताओं को बढ़ाते हुए, इन प्लेटफार्मों की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ा सकती है।

हाल ही में, अपनी परियोजनाओं में बैंक ऑफ कनाडा और मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपने संबंधित ब्लॉकचेन नेटवर्क में सीमा पार से भुगतान की कोशिश की। डिएलटी में केंद्रीय बैंकों के हित को 2019 की दूसरी छमाही में और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि फेसबुक द्वारा लिब्रा के प्रस्तावित लॉन्च की घोषणा जून 2019 में एक श्वेत पत्र में की गई थी।

पिछले पांच वर्षों में, कई केंद्रीय बैंकों ने डिएलटी प्रौद्योगिकी का अध्ययन और उपयोग करने के लिए परियोजनाएं (परिशिष्ट) शुरू की हैं ताकि वित्तीय अवसंरचना में डिएलटी के संभावित अनुप्रयोगों का आकलन किया जा सके। अधिकांश परियोजनाओं का उद्देश्य मौजूदा वित्तीय अवसंरचना को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि अन्वेषणात्मक है जिसे एक नए विकेंद्रीकृत मंच पर मौजूदा प्रणालियों की व्यवहार्यता का अध्ययन करना है। ऐसी परियोजनाएं मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों के बीच डिएलटी की समझ में सुधार लाने के उद्देश्य से हैं और चरणबद्ध तरीके से वित्तीय अवसंरचना में सीबीडीसी को लागू करने की व्यवहार्यता का पता लगाती हैं।

IV.1 बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी): प्रोजेक्ट जैस्पर

बैंक ऑफ कनाडा ने मार्च 2016 में पेमेंट्स कनाडा, आर3 और कनाडियन वाणिज्यिक बैंकों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट जैस्पर शुरू किया, ताकि डिएलटी और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जा सके और इसे समझा जा सके। इसने एथेरियम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रथम चरण में डिएलटी आधारित थोक अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली के प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी)⁵ विकसित किए। नेटवर्क के सदस्य बैंक ऑफ कनाडा द्वारा जारी अंतरबैंक भुगतानों का लेन-देन और निपटान करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा द्वारा जारी डिजिटल डिपॉजिटरी रसीदें (डीडीआर) का उपयोग करते हैं, जो कि अंततः बैंक ऑफ कनाडा के साथ बैंकों की जमाराशि के विरुद्ध निपटाया जाएगा। दूसरे चरण में, कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी सेविंग मेकेनिज्म (एलएसएम) जैसे अधिक कार्य जोड़े गए, जहां वित्तीय संस्थानों द्वारा लेनदेन की गोपनीयता सुनिश्चित की गई। तीसरे चरण में, परियोजना ने वितरित लोन पर डीडीआर के विरुद्ध प्रतिभूतियों के निपटान के लिए डिएलटी के अनुप्रयोग को बढ़ाया। चौथे चरण में, परियोजना ने अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ सीमा पार और क्रॉस-मुद्रा निपटान प्रणाली के लिए डिएलटी का उपयोग करने के लिए सहयोग किया। कुल मिलाकर, परियोजना का निष्कर्ष है कि डिएलटी-आधारित अनुप्रयोगों से दक्षता लाभ

⁵ प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) किसी विचार की व्यवहार्यता को निर्धारित करने या यह सत्यापित करने के लिए है कि यह आइडिया परिकल्पना के अनुसार कार्य करेगा।

और लागत में बचत हो सकती है। हालांकि, इस तरह के फ़ायदों को महसूस करने के लिए, नेटवर्क में प्रतिभागियों के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर आस्तियों के कवरेज का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।

IV.2 मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएसएस): प्रोजेक्ट यूबीन

मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएसएस) ने अन्य वित्तीय संस्थानों और आर3 के साथ नवंबर 2016 में प्रोजेक्ट यूबिन शुरू किया, ताकि डीएलटी-आधारित डिजिटल कैश-ऑन-लेजर का उपयोग करके अंतर-बैंक भुगतान का विकास और उत्पादन करने के लिए पीओसी का उत्पादन किया जा सके। इस परियोजना ने प्रोजेक्ट जैस्पर में आर3 द्वारा प्राप्त अनुभव का लाभ उठाया और इसे सिंगापुर के संदर्भ में प्रोजेक्ट यूबिन में लागू कर दिया। परियोजना के प्रथम चरण में, एथेरियम ब्लॉकचेन पर थोक अंतरबैंक भुगतान के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया था। दूसरे चरण में, प्राप्त अनुभव के आधार पर, एलियन की उन्नत सुविधा को मूल पीओसी में जोड़ा गया था, जिसका विश्लेषण और विकास अन्य डीएलटी प्लेटफॉर्म जैसे कि हाइपरलेजर फैब्रिक, कॉर्ड और कोरम में किया गया था और इसे नवंबर 2017 को पूरा और प्रकाशित किया गया था। तीसरे चरण में, एमएसएस और सिंगापुर एक्सचेंज ने डीएलटी प्लेटफॉर्म पर, प्रतिभूतियों जैसे टोकन आस्तियों के निपटान के लिए डिलिवरी बनाम भुगतान (डीवीपी) कार्यात्मकताओं को विकसित करने के लिए सहयोग किया। चौथे चरण में, एमएसएस और बीओसी ने विभिन्न डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सीमा पार से अंतरबैंक भुगतान को सक्षम करने के लिए मिलकर काम किया और मई 2019 में जैस्पर-यूबिन डिजाइन पेपर प्रकाशित किया। वर्तमान में, परियोजना का पांचवा चरण प्रगति पर है, जो समान नेटवर्क पीआर विभिन्न मुद्राओं में भुगतान को सक्षम बनाएगा।

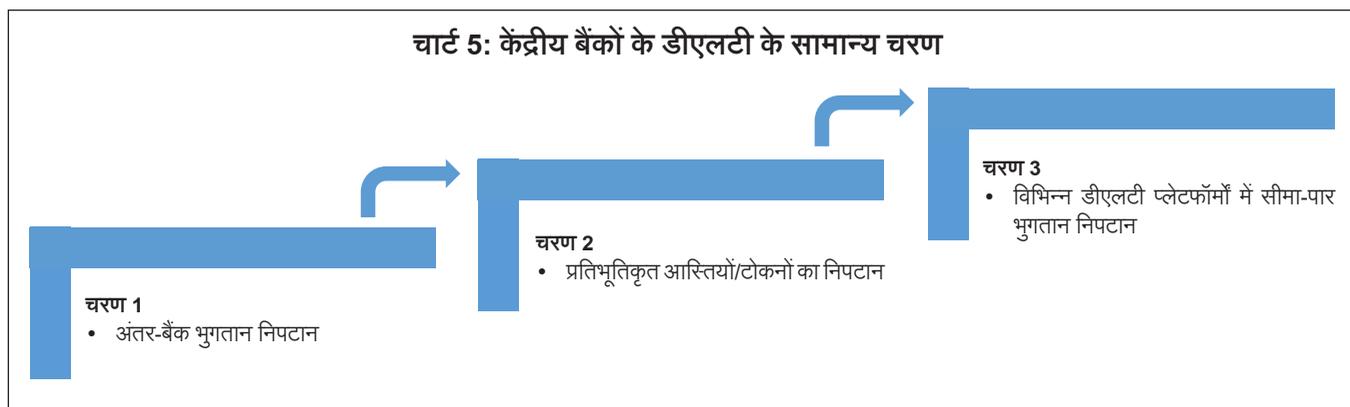
IV.3 अन्य पहल

डीएलटी में केंद्रीय बैंकों की दिलचस्पी हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में विकास की निगरानी के लिए विशेष इकाइयां स्थापित की हैं और नई प्रौद्योगिकियों की समझ में बेहतरी के लिए परियोजनाओं में लगे हुए हैं, जो वित्तीय बुनियादी ढांचे पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अब तक, डीएलटी परियोजनाओं के साथ केंद्रीय बैंकों के प्रायोगिक अध्ययन ने एक समान पैटर्न (चार्ट 5) का पालन किया है, जो थोक अंतर-बैंक भुगतान में अनुप्रयोग के साथ शुरू होता है, फिर डिलिवरी-बनाम-भुगतान निपटान में टोकन आस्तियों के लेनदेन के साथ परीक्षण सीमा पार से भुगतान की ओर रुख करती है।

कुछ केंद्रीय बैंक, जिन्होंने इसी तरह की परियोजनाएं ली हैं, वे हैं बैंक ऑफ जापान के साथ यूरोपीय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, बैंक ऑफ थाईलैंड आदि। नेशनल बैंक ऑफ कंबोडिया ने अपने प्रोजेक्ट बकॉग के तहत एक ब्लॉकचेन-आधारित खुदरा भुगतान प्रणाली विकसित की है, जो सार्वजनिक उपयोग के लिए ब्लॉकचेन-आधारित पी2पी सिस्टम लॉन्च करने वाले पहले केंद्रीय बैंकों में से एक है।

केंद्रीय बैंकों के अलावा, कई निजी बैंक भी ब्लॉकचेन और डीएलटी के लाभ लेने के प्रयासों में शामिल हुए हैं। उदाहरण के लिए, जे पी मॉर्गन ने 2017 में कोरम को विकसित किया है, जो उद्यम समाधान के लिए एथेरियम ब्लॉकचेन का एक अनुमति सहित संस्करण है, जिसका उपयोग वह कंपनी के इंटरबैंक सूचना नेटवर्क (आईआईएन) का समर्थन करने के लिए करता है। आईआईएन का लक्ष्य न्यूनतम समय में सीमा पार से भुगतान की सुविधा के लिए सूचनाओं का सुरक्षित और तेज आदान-प्रदान करना है। आईआईएन के नेटवर्क पर वैश्विक रूप से 365 बैंक हैं, जिसमें भारत के सात बैंक भी शामिल हैं।

चार्ट 5: केंद्रीय बैंकों के डीएलटी के सामान्य चरण



V. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा

केंद्रीय बैंक न केवल वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपने अनुप्रयोग के लिए डीएलटी की संभावना तलाश रहे हैं, बल्कि इसे केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को लागू करने में एक संभावित तकनीकी समाधान के रूप में भी विचार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा किए गए केंद्रीय बैंकों के हालिया सर्वेक्षण के परिणाम से यह निष्कर्ष निकलता है कि 66 प्रतिशत देने वाले केंद्रीय बैंकों में से 80 प्रतिशत ने किसी न किसी रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के उपयोग का पता लगाने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं (बोर एवं अन्य, 2020)। ये केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में सीबीडीसी के संभावित फायदों और निहितार्थों पर विचार और अध्ययन कर रहे हैं। हम इस संबंध में चीन और स्वीडन के केंद्रीय बैंकों में किए जा रहे प्रयासों के बारे में नीचे चर्चा करेंगे।

V.1 पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी)

पीबीओसी ने डिजिटल करेंसी में अनुसंधान और अध्ययन करने और उन तकनीकों का पता लगाने के लिए डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है जिसके माध्यम से किसी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को लागू किया जा सकता है। डीबीटी और ब्लॉकचेन को सीबीडीसी शुरू करने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी के रूप में पीबीओसी द्वारा बड़े पैमाने पर संभावना तलाशी गयी है (पीबीओसी, 2016)। सीबीडीसी के अलावा, पीबीओसी, व्यापार वित्त के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने पर शोध का समर्थन कर रहा है, खासकर ब्लॉकचेन तकनीक के लिए चीन के राष्ट्रपति के समर्थन के बाद, नवाचारों⁶ के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में।

V.2 स्वेरिएस रिक्सबैंक: ई-क्रोना प्रोजेक्ट

स्वीडन में नकदी के घटते उपयोग के साथ, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, रिक्सबैंक, सीबीडीसी पर शोध कर रहा है और मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से डिजिटल मुद्रा, ई-क्रोना को लॉन्च करने के निहितार्थों का विश्लेषण कर रहा है। ई-क्रोना को लागू करने के लिए, रिक्सबैंक ने डीएलटी सहित विभिन्न तकनीकी समाधानों का पता लगाया है। हालांकि, बैंक ने कहा है कि वर्तमान में, डीएलटी को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किया गया है ताकि वह ई-क्रोना के वांछित अनुप्रयोग प्रदान कर सके। इसलिए, ई-क्रोना अल्पावधि में डीएलटी पर आधारित

नहीं होगा। हालांकि, डीएलटी में तकनीकी विकास की गति को देखते हुए, यह दीर्घकालिक रूप से सीबीडीसी के लिए एक प्रासंगिक समाधान बन सकता है। इसलिए, ई-क्रोना के लिए डीएलटी अनुप्रयोगों के साथ सक्रियता वांछनीय है (स्वेरिएस रिक्सबैंक, 2018)।

VI. भारत में डीएलटी एप्लीकेशन

बिटकॉइन के बाद, भारत में क्रिप्टोकॉरेसी में व्यापार करने वाले विभिन्न स्टार्ट-अप्स हैं जैसे कि 2013 में यूनोकवायन और 2014 में जेबपे (ट्राक्शन, 2019)। हालांकि, बिटकॉइन की कीमतों में अस्थिरता और क्रिप्टोकॉरेसी के जोखिमों पर धोखाधड़ी के उदाहरणों ने नियामक चिंताओं को सामने लाया है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने संकेत दिया है कि उन्होंने क्रिप्टोकॉरेसी में कारोबार करने के लिए किसी भी इकाई को अधिकृत नहीं किया है या कोई विनियम जारी नहीं किया है और इसलिए, व्यक्तियों को क्रिप्टोकॉरेसी से निपटने के लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है और इसके साथ जुड़े सभी जोखिमों को वहन उसे ही करना पड़ेगा। वास्तव में, रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकॉरेसी में काम करने के खिलाफ कई प्रेस प्रकाशनी (24 दिसंबर, 2013, 01 फरवरी, 2017, 05 दिसंबर, 2017) के माध्यम से चेतावनी जारी की है।

क्रिप्टोकॉरेसी में सट्टा कारोबार से बढ़ते जोखिम को ध्यान में रखते हुए और घरेलू जमाकर्ताओं एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा के लिए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2018 में अपनी विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टोकॉरेसी या वर्चुअल मुद्राओं (वीसी) में कारोबार करने वाली कंपनियों को अपनी सेवाएं देने से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि, अधिकारियों ने ब्लॉकचेन और डीएलटी की उपयोगिता को मान्यता दी है (सारणी 2)। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, भारत में संस्थानों के लिए डिजिटल इनोवेशन के लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए डीएलटी से जुड़े संभावित फायदों और जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है।

हाल के वर्षों में, भारत में डीएलटी और ब्लॉकचेन को अपनाने को लेकर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रगति हुई है, हालांकि अधिकांश परियोजनाएं अवधारणा के चरण में हैं। वास्तव में, सार्वजनिक क्षेत्र ब्लॉकचेन-आधारित समाधानों के एक बड़े उपयोगकर्ता के रूप में उभर रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसी कुछ राज्य सरकारों ने भूमि रजिस्ट्री, डिजिटल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि के क्षेत्रों में ब्लॉकचेन-संबंधित समाधान शुरू किया है (आंध्र प्रदेश सरकार, सितंबर 2018)। निजी क्षेत्र में, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र ब्लॉकचेन-आधारित

⁶ <https://www.coindesk.com/president-xi-says-china-should-seize-opportunity-to-adopt-blockchain> पर उपलब्ध।

सारणी 2: भारत में डीएलटी से संबंधित प्रमुख गतिविधियां

रिपोर्ट	जारी किया गया	डीएलटी और ब्लॉकचेन से संबंधित चुनिंदा बातें
श्वेत पत्र: भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, आईडीबीआरटी।	जनवरी 2017	बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, दो उपयोग के मामलों का पीओसी विकसित किया गया था: जिसमें साख पत्र और संवर्धित सूचना भुगतान दृष्टि के साथ घरेलू व्यापार वित्त शामिल हैं।
फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर आरबीआई अंतर-विनियमकीय कार्य समूह (अध्यक्ष: सुदर्शन सेन)।	फरवरी 2018	"इस क्षेत्र को सक्रिय रूप से विनियमन करने से पहले विभिन्न फिनटेक उत्पादों और वित्तीय क्षेत्र के साथ उनकी बातचीत और वित्तीय प्रणाली पर उनके निहितार्थ के बारे में गहन समझ विकसित करने की आवश्यकता है।"
बजट 2018-19 में वित्त मंत्री का अभिभाषण	फरवरी 2018	"सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था की शुरुआत के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोगिता के बारे में पता लगाएगी।"
बैंकिंग सेक्टर और उससे इतर के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का ब्लूप्रिंट, आईडीआरबीटी।	जनवरी 2019	रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि एक उपयोगी ब्लॉकचेन कैसे बनाया जाए जो विभिन्न एप्लीकेशन्स को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सके।
आभासी मुद्राओं के संबंध में किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के संबंध में प्रस्ताव देने के लिए समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: सुभाष चंद्र गर्ग)।	जुलाई 2019	"समिति ने सिफारिश की है कि आरबीआई तेजी से और अधिक सुरक्षित भुगतान बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए डीएलटी आधारित प्रणालियों का उपयोग करने की, विशेष रूप से सीमा-पार भुगतान के लिए, उपयोगिता की जांच करे।"
फिनटेक से संबंधित मुद्दों पर संचालन समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: सुभाष चंद्र गर्ग)।	सितंबर 2019	सार्वजनिक क्षेत्र के ब्लॉकचेन-आधारित व्यापार वित्त के संदर्भ में, "समिति तदनुसार अनुशंसा करती है कि एमएसएमई मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त में ब्लॉकचेन समाधानों के परीक्षण और कार्यान्वयन के लिए डीएफएस और आरबीआई के साथ काम करना चाहिए।"
विनियामक सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क को सक्षम करना, आरबीआई।	अगस्त 2019	ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के तहत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्लिकेशन जैसे नवीन उत्पादों/प्रौद्योगिकियों को नियामक सैंडबॉक्स कॉहोर्ट्स के तहत परीक्षण के लिए माना जा सकता है। आरबीआई ने 04 नवंबर, 2019 को नियामक सैंडबॉक्स के अपने पहले कॉहोर्ट में 'खुदरा भुगतान' के विषय के साथ आवेदन आमंत्रित किया था।

समाधानों को अपनाने में अग्रणी है। उदाहरण के लिए, इन पहलों में शामिल हैं: यस बैंक ब्लॉकचेन पर वाणिज्यिक पत्र जारी करना (यस बैंक, जुलाई 2019); एक्सिस बैंक द्वारा रिपल के एंटरप्राइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवा शुरू की (एक्सिस बैंक, नवंबर 2017); और एचएसबीसी इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा ब्लॉकचेन-आधारित व्यापार वित्त लेनदेन को निष्पादित करना (एचएसबीसी इंडिया, नवंबर 2018)।

हेल्थकेयर, रिटेल, सरकारी सेवाओं और मानव संसाधन जैसे विभिन्न उद्योगों में समाधान प्रदान करने के लिए स्टार्ट-अप भी ब्लॉकचेन का लाभ उठा रहे हैं। उद्यमी पूंजीपतियों के माध्यम से भारत में ब्लॉकचेन-आधारित स्टार्टअप में निवेश लगभग 8.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है (नास्कॉम, 2019)। हालांकि, इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ब्लॉकचेन स्टार्ट-अप में उद्यम पूंजी निवेश में वृद्धि की तुलना में, भारतीय स्टार्ट-अप उन निवेशों में से केवल 0.2 प्रतिशत पर कब्जा करने में सक्षम थे। भारतीय रिजर्व बैंक अपने नए नियामक सैंडबॉक्स पर्यावरण के माध्यम से ब्लॉकचेन-आधारित अनुप्रयोग के विकास

के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में अति-सक्रिय रहा है। ब्लॉकचेन-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करने वाले स्टार्ट-अप और वित्तीय संस्थानों को एक निर्धारित अवधि के लिए अपने उत्पादों के परीक्षण के लिए विनियामक सैंडबॉक्स के साथ में शामिल किया जा सकता है।

हाल ही में केंद्रीय बजट 2020-21 में भारत सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि पर आधारित नई अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया है। इसने देश भर में डेटा सेंटर पार्कों का निर्माण करने हेतु निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए एक नीति लाने का प्रस्ताव दिया और भारतनेट कार्यक्रम के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़कर जमीनी स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ₹6,000 करोड़ और नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन के लिए पाँच वर्ष की अवधि हेतु ₹8,000 करोड़ आवंटित किए। इसके अलावा, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं (ईएसओपी) के तहत अपने कर्मचारियों को स्टार्ट-अप द्वारा आवंटित शेयरों पर कर भुगतान को स्थगित करने का प्रस्ताव किया गया था। इस

प्रकार, इन उपायों से न केवल स्टार्ट-अप्स को बढ़ने और फलने-फूलने के लिए नए रास्ते मिलेंगे, बल्कि नए निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आगे चलकर, नियामक सैंडबॉक्स के कार्यान्वयन के साथ डीएलटी और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आसपास नियामक वातावरण जैसे-जैसे परिपक्व होगा वैसे-वैसे अधिक स्टार्ट-अप और निवेश की उम्मीद है।

VII. निष्कर्ष

एक दशक के अंतराल में, डीएलटी और ब्लॉकचेन ने वित्तीय क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों के समाधान की पेशकश करने के लिए सुविधाओं और जटिलता में काफी विकास किया है। प्रारंभ में, डीएलटी की समझ उसकी जटिलता के कारण कंप्यूटर वैज्ञानिकों और कुछ अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों तक ही सीमित थी। हालांकि, वित्त और अन्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग के साथ, डीएलटी में व्यापक रुचि देखने को मिल रही है। अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कुछ केंद्रीय बैंक डीएलटी का अध्ययन करने और उसे समझने तथा उनके संचालन और वित्तीय प्रणालियों के संभावित लाभों का पता लगाने के लिए पायलट परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अब तक, इनमें से अधिकांश परियोजनाएं मौजूदा प्रणाली की कार्यक्षमता के साथ डीएलटी प्लेटफार्मों में अंतर-बैंक निपटान, डिजिटल आस्तियों और टोकन के निपटान और सीमा पार से भुगतान की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रकृति में प्रयोगात्मक हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने अभी तक डीएलटी-आधारित एप्लीकेशन्स को उत्पादन में विनियोजन करने का इरादा व्यक्त नहीं किया है। यहां तक कि सीबीडीसी के मामले में, रिक्सबैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि डीएलटी अपने वर्तमान स्वरूपों में ई-क्रोना के कार्यान्वयन के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए अपरिपक्व है। फिर भी, उनके परिणामी लाभों के साथ ऐसी परियोजनाएँ डीएलटी-आधारित वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय बैंकों और नियामकों की क्षमता को बढ़ा देती हैं। यह केंद्रीय बैंकों को स्टार्ट-अप्स और संस्थानों को उत्पादक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम बनाता है क्योंकि वे व्यावसायिक समस्याओं के प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करने के लिए नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार की ओर से बढ़ते समर्थन से विनियामक सैंडबॉक्स और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से नवाचारों और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को नई अर्थव्यवस्था के

लिए प्रौद्योगिकी-केंद्रित वृद्धि गति के साथ समृद्ध करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ

Axis Bank (2017), "Axis Bank launches Ripple-powered instant payment service for retail and corporate customers". *Press Release*, November 22.

Banco Central Do Brazil (2017), "Distributed ledger technical research in Central Bank of Brazil".

Bank of Canada (2017-19), "Fintech Experiments and Project", Available at: <https://www.bankofcanada.ca/research/digital-currencies-and-fintech/fintech-experiments-and-projects/>

Bank of Canada, the Monetary Authority of Singapore, Accenture and J.P. Morgan (2019), "Jasper-Ubin Design Paper: Enabling Cross-Border High Value Transfer Using Distributed Ledger Technologies".

Bank of England (2018), "FinTech Accelerator Proof of Concept", Available at: <https://www.bankofengland.co.uk/research/fintech/proof-of-concept>

Bank of Thailand (2018-19), "Project Inthanon Phase 2: Enhancing Bond Lifecycle Functionalities & Programmable Compliance Using Distributed Ledger Technology", Available at: <https://www.bot.or.th/English/PressandSpeeches/Press/2019/Pages/n3962.aspx>

Boar, C., Holden, H., and Wadsworth, A. (2020), "Impending arrival – a sequel to the survey on central bank digital currency", *BIS Papers No.107*, January.

Buterin, V. (2013), "A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform." Ethereum White Paper, Available at <https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper>.

Buterin, V., & Griffith, V. (2017), "Casper the Friendly Finality Gadget", *ArXiv, abs/1710.09437*.

De Meijer, C.R.W. (2018), "Central Banks apathy for blockchain is waning", Finextra, August 21, Available at: https://www.finextra.com/blogposting/15678/central-banks-apaty-for-blockchain-is-waning?utm_medium=rss&utm_source=finextrafeed

European Central Bank and Bank of Japan (2017-19), "STELLA - a joint research project of the European Central Bank and the Bank of Japan".

Government of Andhra Pradesh, APCRDA (2018), "Securing Land Records through Blockchain". Available at: <https://www.esri.in/~media/esri-india/files/pdfs/events/2018/UC/experience-the-uc-presentations/apcrda-land-records-on-blockchain-urban-transformation-summit.pdf>

HSBC (2018), "HSBC and Reliance Industries execute first of its kind blockchain trade finance transaction", *News Release*, November 04.

Monetary Authority of Singapore (2017-19), "Project Ubin: Central Bank Digital Money using Distributed Ledger Technology", Available at: <https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/Project-Ubin>

Nakamoto, S. (2008), "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", Available at <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.

NASSCOM (2019), NASSCOM Avasant India Blockchain Report.

People's Bank of China (2016), Transcript of Governor Zhou Xiaochuan's Exclusive Interview with Caixin Weekly, Press Release.

Protocol Labs (2017), "Filecoin: A Decentralized Storage Network." *Filecoin White Paper*, Available at: <https://filecoin.io/filecoin.pdf>

Reserve Bank of India (2013), "RBI cautions users of Virtual Currencies against Risks", *Press Releases*, December 24.

Reserve Bank of India (2017), "RBI cautions users of Virtual Currencies", *Press Releases*, February 01.

Reserve Bank of India (2017), "Reserve Bank cautions regarding risk of virtual currencies including Bitcoins", *Press Releases*, December 05.

Reserve Bank of India (2018), "Prohibition on dealing in Virtual Currencies (VCs)", Notifications, April 06.

South African Reserve Bank (2018), "Project Khokha: Exploring the use of distributed ledger technology for interbank payments settlement in South Africa".

Sveriges Riksbank (2018), "The Riksbank's e-krona project : Report 2", Available at : <https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/e-krona-reports/e-krona-project-report-2>

Tracxn (2019), "Blockchain Startups in India". Available at: <https://tracxn.com/explore/Blockchain-Startups-in-India>

Walch, A. (2016), "The Path of the Blockchain Lexicon (and the Law)", *Review of Banking & Financial Law*, Vol.36.

World Economic Forum (2016), "The Future of Financial Infrastructure: An Ambitious Look at How Blockchain Can Reshape Financial Services", *Future of Financial Services Series*, August. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_future_of_financial_infrastructure.pdf.

Yes Bank (2019), "Yes Bank Implements Asia's First Commercial Paper Issuance On Blockchain", *Press Release*, July 11.

परिशिष्ट: केंद्रीय बैंक की डीएलटी परियोजनाएं

चरण	परियोजना उद्देश्य	डीएलटी प्लेटफॉर्म	प्रकाशित/पूर्ण
1. बैंक ऑफ कनाडा – प्रोजेक्ट जैस्पार			
चरण 1	डीएलटी पर एक थोक अंतरबैंक भुगतान प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) बनाएं	एथेरियम	फरवरी 2017
चरण 2	लिक्विडिटी सेविंग मेकेनिज्म (एलएसएम) जैसे अतिरिक्त कार्यक्षमताओं का निर्माण करें	कॉर्ड	सितंबर 2017
चरण 3	प्रतिभूति निपटान के लिए डिलिवरी बनाम भुगतान (डीवीपी) समाधानों की जांच करें	कॉर्ड	अक्टूबर 2018
चरण 4	क्रॉस-बॉर्डर और क्रॉस-करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के लिए डीएलटी का उपयोग करने हेतु अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर काम करें	क्वोरम और कॉर्ड	मई 2019
2. मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर – प्रोजेक्ट यूबिन			
चरण 1	ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अंतर-बैंक भुगतान का संचालन करने के लिए प्रूफ-ऑफ- कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट	एथेरियम	मार्च 2017
चरण 2	लिक्विडिटी सेविंग मेकेनिज्म के साथ विकेंद्रीकृत अंतर-बैंक भुगतान और निपटान के लिए तीन अलग-अलग मॉडल	कोरम, हाइपरलेजर फैब्रिक, कॉर्ड	नवंबर 2017
चरण 3	डीएलटी प्लेटफॉर्मों पर टोकन आस्तियों के निपटान के लिए डिलिवरी बनाम भुगतान (डीवीपी) क्षमताएं।	एथेरियम, कोरम, हाइपरलेजर फैब्रिक, चैन, अनकन	नवंबर 2018
चरण 4	सीमा पार से भुगतान बनाम विभिन्न डीएलटी प्लेटफॉर्मों पर भुगतान	क्वोरम और कॉर्ड	मई 2019
चरण 5	एक ही नेटवर्क में विभिन्न मुद्राओं के लिए व्यापक प्रणाली सहयोग को सक्षम करना	-	प्रगति में
3. यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान - प्रोजेक्ट स्टेला			
चरण 1	भुगतान प्रणाली: डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वातावरण में लिक्विडिटी सेविंग मेकेनिज्म,	हाइपरलेजर फैब्रिक	सितंबर 2017
चरण 2	प्रतिभूति निपटान प्रणाली: डिलिवरी-बनाम- डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वातावरण में भुगतान	हाइपरलेजर फैब्रिक, कॉर्ड, एलिमेंट्स	मार्च 2018
चरण 3	सिंक्रनाइज्ड सीमा पार से भुगतान	हाइपरलेजर फैब्रिक,	जून 2019
4. बैंक ऑफ थाइलैंड - प्रोजेक्ट इथानोन			
चरण 1	आधारभूत निर्माण: अंतर बैंक निपटान के लिए विकेंद्रीकृत आरटीजीएस	कॉर्ड	जनवरी 2019
चरण 2	बॉन्ड टोकन, बॉन्ड डीवीपी, अंतर-बैंक पुनर्खरीद करार का जीवनचक्र	कॉर्ड	जुलाई 2019
चरण 3	डीएलटी इंटरऑपरेबिलिटी के साथ सीमा पार भुगतान, एचकेएमए के प्रोजेक्ट लायनरोक के साथ सहयोग	कॉर्ड	दिसंबर 2019

(क्रमशः)

परिशिष्ट: केंद्रीय बैंक की डीएलटी परियोजनाएं (समाप्त)

चरण	परियोजना उद्देश्य	डीएलटी प्लेटफॉर्म	प्रकाशित/पूर्ण
5. सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील			
चरण 1	चार उपयोग के मामलों की पहचान की और उनमें से, इसका उपयोग करके प्रूफ ऑफ प्रोटोटाइप करने के लिए अल्टर्नेट सिस्टम फॉर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट का चयन किया गया;	एथेरियम	नवंबर 2016
चरण 2	अंतर-बैंक निपटान प्रोटोटाइप की सुविधाओं में सुधार और प्रतिस्पर्धी ब्लॉकचेन प्लेटफार्मों के साथ इसका विश्लेषण किया गया	कोरम, हाइपरलेजर फैब्रिक, कॉर्ड	मार्च 2017
6. साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक - प्रोजेक्ट खोखा			
एक चरण	'यथार्थवादी' वातावरण में गोपनीयता और मापनीयता पर विस्तार करके डीएलटी पर आरटीजीएस पीओसी का निर्माण किया	कोरम	जून 2018
7. के सहयोग से बैंक ऑफ इंग्लैंड			
पीडबल्यूसी	कई प्रतिभागियों के बीच एक काल्पनिक आस्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के मामले में डीएलटी की क्षमता, इन-हाउस क्षमताओं का लाभ और पीओसी में ज्ञान का आकलन करना।	एथेरियम	2016
रिप्पल	दो अलग-अलग सिम्युलेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम में दो अलग-अलग मुद्राओं के सिंक्रनाइज़ की गयी गति का पता लगाने के लिए पीओसी	इंटरलेजर प्रोटोकॉल	जुलाई 2017
बैटन सिस्टम्स, क्लियरमैटिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आर3 और टोकन	पीओसी यह समझने के लिए कि कैसे नवीकृत आरटीजीएस सेवा डीएलटी जैसे नवन्मेषी भुगतान प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाली प्रणालियों में निपटान का समर्थन करने में सक्षम हो	कॉर्ड	जुलाई 2018

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक भारतीय रिज़र्व बैंक	57
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	58
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	59
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय	60
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	61
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं मुद्रा और बैंकिंग	61
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	62
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	63
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	64
9	कुल चलनिधि राशियां	64
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	65
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	65
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	66
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	66
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	67
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	68
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	69
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक मूल्य और उत्पादन	70
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	71
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	71
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	71
21	थोक मूल्य सूचकांक	72
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100) सरकारी खाते और खज़ाना बिल	76
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	76
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	77
25	खज़ाना बिलों की नीलामी वित्तीय बाजार	77
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	78
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	79
28	वाणिज्यिक पत्र	79
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	79
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	80

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	81
32	विदेशी मुद्रा भंडार	81
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	81
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	82
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	82
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	83
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	83
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरिकी डॉलर)	84
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	85
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	86
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	87
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	88
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	89
	प्रासंगिक शृंखला	
44	लघु बचत	91
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	92
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	93
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	94
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	95
49	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	96

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2018-19		2019-20	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.7	6.9	4.9	4.3
1.1.1 कृषि	2.9	5.1	4.9	2.0	2.1
1.1.2 उद्योग	6.2	9.9	6.1	1.7	-0.5
1.1.3 सेवाएं	7.7	7.5	7.5	6.7	6.4
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	7.2	10.0	4.1	6.9
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	13.3	11.8	4.0	1.0
	2018-19	2018		2019	
	1	नवंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.8	0.2	2.5	1.8	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	10.8	8.9	9.5	9.7
2.1.2 ऋण	13.3	16.2	13.9	7.2	7.0
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	16.3	13.8	7.2	6.9
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	2.0	-0.5	8.6	12.9
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	18.9	17.0	12.4	10.2
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	10.4	10.2	9.8	10.4
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	18.50	18.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.8	5.1	4.8	4.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	77.1	78.2	75.5	76.2
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	111.6	139.2	22.5	39.3
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	28.5	27.9	28.3	28.7
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	17.8	1.1	62.4	74.1
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.50	5.15	5.15
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.25	6.25	4.90	4.90
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.75	6.75	5.40	5.40
4.4 बैंक दर	6.50	6.75	6.75	5.40	5.40
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.95/9.45	8.95/9.45	8.95/9.40	8.45/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	8.15/8.45	8.15/8.55	7.65/8.10	7.65/8.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.50	6.25/7.50	6.25/6.60	6.20/6.40
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.25/3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.39	6.57	5.03	5.11
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.77	6.65	4.99	5.03
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	7.06	6.84	5.12	5.22
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	7.22	6.94	5.14	5.30
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.64	7.36	6.65	6.78
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	69.66	69.98	71.73	71.22
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	79.36	80.18	78.98	79.19
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.31	4.37	3.35	3.96
3-माह (%)	4.80	4.02	3.97	3.35	3.90
6-माह (%)	4.16	4.13	4.09	3.76	4.38
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	2.3	2.1	5.5	7.4
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	4.9	5.2	8.6	9.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	4.5	3.5	0.6	2.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	0.6	1.4	7.7	11.5
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	15.5	7.6	-7.3	-1.5
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	4.2	3.6	-0.8	-0.3
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.4	5.5	0.8	-12.7	-8.8
7.2 निर्यात	8.7	-1.1	0.1	-0.3	-1.8

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से सदर्थ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2019	2020				
			जनवरी	जनवरी 3	जनवरी 10	जनवरी 17	जनवरी 24
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2113764	2035957	2242671	2271523	2278414	2280962	2284695
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	12	12	13	12	12	11
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2113775	2035969	2242683	2271536	2278426	2280974	2284706
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	79481	73693	92739	93061	93475	94284	95254
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2033559	1961475	2149191	2177731	2184217	2185962	2188733
1.2.3 रुपया सिक्का	735	801	753	744	735	728	719
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	806012	618526	1051975	955428	959038	921029	994030
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	101	101	100	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	565707	493114	542465	539538	547082	540629	550704
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4197	3445	6925	6681	7110	6647	6841
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3494	2254	3092	3014	3011	2958	3002
2.1.1.7 अन्य बैंक	32036	28325	31364	31264	31141	31725	31707
2.1.1.8 अन्य	199734	91246	467985	374788	369122	338210	400909
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	700				1430	718	724
2.1.2 अन्य देयताएं	1087686	1143107	1170393	1129506	1140304	1152701	1161436
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	1893698	1761633	2222368	2084934	2099342	2073730	2155466
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	12	13	13	12	12	11
2.2.2 विदेश में रखे शेष	646640	710752	947990	880176	885950	926095	955641
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	130171	60605	87735	24184	73545
2.2.3.2 राज्य सरकारें	10	919	5304	7589	7499	3234	1210
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	180688	99949	18165	15176	21159	15315	16915
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	13463	4798	4309	4247	4272	4050	4416
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	700						724
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	923080	854194	1001087	1001327	976156	983230	983670
2.2.6 अन्य आस्तियां	129106	91009	115329	115800	116559	117609	119334
2.2.6.1 सोना	87169	79312	108717	109094	109579	110528	111665

* डाटा अन्तिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
दिसं. 2, 2019	3577	18466	-	237836	5352	217	-	5	220	-246941
दिसं. 3, 2019	3577	21277	-	239517	6310	-1	-	-	-	-250908
दिसं. 4, 2019	3482	18088	-	238407	3950	-204	-	-	-	-249267
दिसं. 5, 2019	3577	25045	-	259407	4780	-	-	-	-	-276095
दिसं. 6, 2019	3739	42550	10400	219609	3838	-	-	-	-	-244182
दिसं. 7, 2019	1500	6200	-	-	238	-	-	-	-	-4462
दिसं. 9, 2019	3527	12678	-	244448	3251	-	-	-	-	-250348
दिसं. 10, 2019	3272	18905	5000	245236	4505	-	-	-	-	-251364
दिसं. 11, 2019	3362	17292	-	246477	3100	-	-	-	-	-257307
दिसं. 12, 2019	3129	17205	-	269837	5800	-	-	-	-	-278113
दिसं. 13, 2019	3322	34654	2200	244008	3600	-	-	210	280	-269470
दिसं. 16, 2019	4119	42669	-	194387	7652	-	-	1065	645	-225705
दिसं. 17, 2019	3144	23150	4000	240017	3300	-	-	200	-	-252923
दिसं. 18, 2019	3644	28107	-	240292	4405	-	-	545	-	-260895
दिसं. 19, 2019	5034	25972	-	251168	4495	-	-	-	-	-267611
दिसं. 20, 2019	3644	49421	10175	179128	3856	212	-	-	-	-210662
दिसं. 21, 2019	9953	7816	-	-	5436	-	-	-	-	7573
दिसं. 22, 2019	-	414	-	-	-	-	-	-	-	-414
दिसं. 23, 2019	5029	27641	-	210353	3753	-	-	-	-	-229212
दिसं. 24, 2019	6319	34368	12050	207089	2765	-	-	6825	10000	-217148
दिसं. 25, 2019	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-23
दिसं. 26, 2019	5135	39163	-	233586	3128	-	-	-	-	-264486
दिसं. 27, 2019	2894	36582	1350	239769	2822	-	-	-	-	-269285
दिसं. 28, 2019	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-24
दिसं. 29, 2019	-	318	-	-	-	-	-	-	-	-318
दिसं. 30, 2019	4279	52933	-	230914	7217	-82	-	-	-	-272433
दिसं. 31, 2019	4654	114551	80	224538	4279	82	-	8501	10000	-328495

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15377	607	6928	4360
1.1 क्रय (+)	40804	837	7458	5374
1.2 विक्रय (-)	56181	230	530	1014
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	4009	49142	30894
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डालर)	-15377	-25903	25381	29741
(करोड़ ₹)	-111945	-184076	174408	205303
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	-13774	-2426	-6143	-1875

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	13935	0	0	1690
1.2 विक्रय (-)	13935	0	0	1690
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	0	0	0	400

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)**

मद	31 दिसंबर 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1220	1120	100
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	3634	1460	2174
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	7576	1705	5871
4. 1 वर्ष से अधिक	0	10020	-10020
कुल (1+2+3+4)	12430	14305	-1875

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2019					2020	
		जनवरी 18	अगस्त 30	सितंबर 27	सितंबर 25	नवंबर 22		दिसंबर 20
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	12882	504	55	48	4373	3231	3856	2340
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3.2 बकाया	2678	1704	1879	2372	1884	1604	1615	1872
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	15560	2208	1934	2420	6257	4835	5471	4212

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		दिसंबर 21	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052209	1950995	2172488	2184545	2180612
1.1 संचलन में नोट	2110883	2004183	2241262	2248925	2245888
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	25043	25380	25435	25435
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84561	78974	94897	90558	91454
2 जनता की जमाराशियां	1658254	1327673	1480272	1533018	1507735
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1626512	1302600	1447960	1500659	1473756
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25073	32312	32359	33979
3 एम₁ (1 + 2)	3710464	3278668	3652760	3717563	3688348
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	140599	130185	139385	139385	139385
5 एम₂ (3 + 4)	3851063	3408853	3792145	3856948	3827733
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	11721603	11271027	12292989	12447209	12370541
7 एम₃ (3 + 6)	15432067	14549695	15945749	16164772	16058889
8 कुल डाकघर जमाराशियां	367287	348696	395361	395361	395361
9 एम₄ (7 + 8)	15799354	14898391	16341110	16560133	16454250

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		दिसंबर 21	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4234658	4890841	5038571	4918791
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	683006	965438	1064368	979921
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	789902	1001006	1064511	1002864
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	789335	1000408	1055439	1001608
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	567	598	9072	1256
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	127735	106896	35568	143	22943
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	106854	35526	100	22901
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	43	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3586539	3551652	3925403	3974203	3938870
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	10382719	9877043	10468270	10582274	10597315
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	9281	7144	6894	6702
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10367356	9867762	10461126	10575380	10590613
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9771722	9287636	9860303	9934684	9945118
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	571234	588692	622085	625750
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9703	8892	12132	18612	19746
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3070841	2879672	3425222	3440660	3440836
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848587	2750402	3207225	3222663	3222839
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2750631	3207434	3222884	3223060
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	229	209	221	221
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222254	129271	217997	217997	217997
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25786	26123	26178	26178
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2435870	2467464	2864707	2922911	2924232
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1050344	1137091	1132917	1123096
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1377075	1417120	1727616	1789994	1801136
एम₃ (1+2+3+4-5)	15432067	14549695	15945749	16164772	16058889

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		दिसंबर 21	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710464	3278668	3652760	3717563	3688348
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	8911512	8283659	9103488	9238836	9176532
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	15646602	14758368	16087659	16316115	16203315
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052209	1950995	2172488	2184545	2180612
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13184397	12424803	13560689	13770154	13669723
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626512	1302600	1447960	1500659	1473756
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11557885	11122203	12112729	12269495	12195966
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5201048	5004991	5450728	5521273	5488185
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	183544	158123	159779	156633
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356837	6117212	6662001	6748223	6707782
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25073	32312	32359	33979
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	378254	357497	322170	329057	319001
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	15659336	14945228	16251859	16514854	16396664
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4234658	4890841	5038571	4918791
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	683006	965438	1064368	979921
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3586539	3551652	3925403	3974203	3938870
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11270846	10710570	11361017	11476283	11477872
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	9281	7144	6894	6702
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11255483	10701289	11353873	11469389	11471170
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879849	824236	883989	884605	871958
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25786	26123	26178	26178
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801726	2649028	3141351	3155743	3207853
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2750402	3207225	3222663	3222839
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-101374	-65874	-66920	-14986
2.4 पूंजी खाता	2346743	2295356	2482957	2487889	2465133
2.5 अन्य मदें (निवल)	493605	566318	848715	892770	962246

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2018		2019	
		दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	15646602	14758370	16111023	16087659	16203315
2 डाकघर जमाराशियां	367287	348696	395359	401111	401111
3 एल₁ (1 + 2)	16013889	15107066	16506382	16488770	16604426
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	2932	56839	54287
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	2656	3262	3078
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	31	49162	46887
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	245	4415	4322
5 एल₂ (3 + 4)	16016821	15109998	16509314	16545609	16658713
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	31905
7 एल₃ (5 + 6)	16048726	15141903	16690618

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		दिसंबर 21	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2029969	2267385	2275103	2272066
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	601969	515563	555408	578361	603702
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	558496	482114	517462	540118	562488
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25073	32312	32359	33979
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2570605	2855104	2885823	2909747
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	844761	758848	769899	783826
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	801951	683006	965438	1064368	979921
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	682481	964882	1055339	978707
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	52575	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	788507	999581	1002053	1000832
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	788507	999581	1002053	1000832
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	828	827	811	776
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	127693	106854	35526	100	22901
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	525	556	9029	1214
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	152474	-213734	-301363	-202797
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	152474	-213734	-301363	-202797
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	9281	7144	6894	6702
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	2082	1604	1403	1615
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25786	26123	26178	26178
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2750402	3207225	3222663	3222839
2.3.1 सोना	159585	147854	192307	193186	192925
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2602565	3014935	3029494	3029931
2.4 पूंजी खाता	970265	987131	1012649	1003505	992085
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	63213	124442	129412	131011

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2018		2019			
		दिसंबर 28	नवंबर 29	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20	दिसंबर 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2618017	2874296	2885823	2885589	2909747	2884942
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2025039	2256875	2275103	2284891	2272066	2270344
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	601969	567369	581895	578361	568922	603702	581929
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25609	35526	32359	31776	33979	32669
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	801951	738285	1001249	1064368	1044279	979921	989412
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	137488	147998	-247355	-301363	-282176	-202797	-245924
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	15363	9321	6877	6894	6397	6702	6443
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2749018	3222285	3222663	3207160	3222839	3252164
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25798	26178	26178	26178	26178	26238
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1052403	1134938	1132917	1116249	1123096	1143391

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		दिसंबर 21	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	12410053	11667449	12778214	12928338	12830205
1.1.1 मांग जमाराशियां	1511287	1189913	1331740	1379987	1354601
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	10898766	10477536	11446474	11548352	11475605
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	4904445	4714891	5150913	5196758	5164022
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	183544	158123	159779	156633
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	5994321	5762645	6295561	6351593	6311583
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	378254	357497	322170	329057	319001
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14032206	13460375	14463919	14579790	14540311
2.1.1 सरकार को ऋण	3379001	3346558	3715868	3749880	3712006
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10653205	10113816	10748051	10829911	10828305
2.1.2.1 बैंक ऋण	9771722	9287636	9860303	9934684	9945118
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9730112	9210294	9768999	9810020	9859975
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8542	9554	9021	9667	8862
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2055	1353	3700	9918	11330
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	815274	875027	875642	862996
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-101374	-65874	-66920	-14986
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	178362	236374	232728	278216
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	163719	148824	180260	177713	174575
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145526	130912	121989	121935	118628
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538104	398859	816180	921646	846390
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	482114	517462	540118	562488
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74877	69219	84984	80165	81105
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	152474	-213734	-301363	-202797
2.4 पूंजी खाता	1352307	1284054	1446137	1460214	1448878
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	382835	448860	667703	716907	773631
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	398120	406180	385783	439556	441282
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-47846	-47158	-45368	49375	47417

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 29, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		दिसंबर 21	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3381056	3347911	3719568	3759797	3723336
2 वाणिज्यिक पत्र	90362	94824	99328	98735	94810
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11535	11704	11286	11385	11409
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69592	72363	66368	66331	66237
3.3 अन्य	6379	6424	5515	5568	5515
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134819	126795	123067	120976	124372
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268783	228418	239223	238348	232706
4.3 अन्य	170047	126643	199063	187027	184531
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20988	56463	48279	48568	46020
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98382	91913	82173	81153	79867

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	224	219	219	147	150	142	142
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	276350	263040	249308	272074	271426	258328	244433	267197
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	181651	163281	187449	196859	176828	159009	182731	192163
1.2 बैंकों से उधार राशि	79487	91213	49892	62874	79459	90926	49866	62839
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15212	8546	11967	12341	15139	8393	11836	12196
2 अन्य के प्रति देयताएं	13835976	13127730	14314792	14366281	13495672	12809813	13953219	13950581
2.1 कुल जमाराशियां	12901579	12229298	13447567	13474861	12573772	11924904	13098829	13076544
2.1.1 मांग	1542554	1290130	1448683	1424617	1511287	1261728	1416506	1390559
2.1.2 मीयादी	11359025	10939168	11998884	12050244	11062484	10663176	11682323	11685985
2.2 उधार	381864	370274	335569	331812	378254	366094	331841	327452
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552533	528159	531656	559608	543646	518815	522549	546584
3 रिजर्व बैंक से उधार	180688	188109	23012	30427	180688	188109	23012	30427
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	180688	188109	23012	30427	180688	188109	23012	30427
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	657555	621750	642086	646512	640584	607287	626159	628412
4.1 उपलब्ध नकदी	76554	76274	85089	89276	74877	74114	83184	86995
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	581001	545476	556997	557235	565707	533173	542975	541417
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	372670	368802	262359	289777	327814	329671	207281	230031
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245880	258171	168690	177938	223048	236956	142276	151727
5.1.1 चालू खाते में	17216	17858	14405	18374	13329	15339	12215	16207
5.1.2 अन्य खातों में	228663	240313	154285	159563	209719	221618	130062	135521
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47047	45101	24263	37565	32252	31974	7015	16753
5.3 बैंकों को अग्रिम	32950	31823	28990	33214	29635	31190	24968	27449
5.4 अन्य आस्तियां	46793	33708	40416	41060	42879	29551	33022	34102
6 निवेश	3475607	3416210	3814598	3880315	3381056	3323755	3716854	3765269
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3467845	3409882	3797839	3859977	3379001	3322998	3706537	3751590
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7762	6329	16759	20338	2055	757	10317	13678
7 बैंक ऋण	10047125	9594587	10176213	10288941	9771722	9319765	9890071	9969432
7क खाद्यान्न ऋण	64636	98712	117556	112463	41610	75685	90526	85433
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9792287	9367741	9969053	10074707	9521994	9097647	9686695	9758702
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27641	21791	24641	25081	26223	20433	23902	24405
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160984	142277	126309	132527	158296	139808	124288	130702
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24914	22738	23182	24270	24588	22415	22762	23872
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41299	40039	33028	32357	40622	39463	32424	31750

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			दिसंबर 21	नवंबर 22		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	8674892	8241267	8764913	8822209	1.7	7.0
1.1 खाद्यान्न ऋण	41474	77092	91005	84863	104.6	10.1
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	8633418	8164175	8673908	8737346	1.2	7.0
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1111300	1082111	1134004	1139092	2.5	5.3
1.2.2 उद्योग	2885778	2749375	2772248	2794372	-3.2	1.6
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375505	365002	362758	365398	-2.7	0.1
1.2.2.2 मझौले	106395	104570	102601	107166	0.7	2.5
1.2.2.3 बड़े	2403878	2279803	2306889	2321808	-3.4	1.8
1.2.3 सेवाएं	2415609	2232987	2362956	2370600	-1.9	6.2
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138524	130312	139754	140438	1.4	7.8
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18535	19124	19052	18597	0.3	-2.8
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39005	38792	43468	44745	14.7	15.3
1.2.3.4 नौवहन	7748	6236	6704	6548	-15.5	5.0
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171517	171662	170660	172553	0.6	0.5
1.2.3.6 व्यापार	528158	485990	501677	513987	-2.7	5.8
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250528	214041	217567	228558	-8.8	6.8
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277630	271949	284109	285429	2.8	5.0
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202291	189929	220685	219585	8.5	15.6
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	641208	570946	730907	728561	13.6	27.6
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668623	619996	530048	525586	-21.4	-15.2
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2220732	2099699	2404701	2433282	9.6	15.9
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6299	3280	5499	5450	-13.5	66.2
1.2.4.2 आवास	1160111	1096614	1274747	1289637	11.2	17.6
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	82873	69324	62892	64441	-22.2	-7.0
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6265	6170	4982	5072	-19.0	-17.8
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88262	84519	105860	105905	20.0	25.3
1.2.4.6 शिक्षा	67988	69115	66902	66895	-1.6	-3.2
1.2.4.7 वाहन ऋण	202154	199235	207996	213601	5.7	7.2
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606780	571442	675823	682281	12.4	19.4
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2739021	2627870	2694733	2787852	1.8	6.1
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1104988	1074992	1125474	1133239	2.6	5.4
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1067175	1004744	1057378	1061953	-0.5	5.7
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375505	365002	362758	365398	-2.7	0.1
1.2अ.2.2 सेवाएं	691670	639742	694620	696555	0.7	8.9
1.2अ.3 आवास	432703	408457	454000	456989	5.6	11.9
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24101	23877	33526	35104	45.7	47.0
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53950	56694	53410	53215	-1.4	-6.1
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	338	387	395	-0.5	16.9
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662628	601915	698449	711799	7.4	18.3
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15566	18495	13219	15152	-2.7	-18.1

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2019
			दिसंबर 21	नवंबर 22		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2885778	2749375	2772248	2794372	-3.2	1.6
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	41752	41664	41372	42741	2.4	2.6
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	157058	147840	136930	145578	-7.3	-1.5
1.2.1 चीनी	29705	24875	24624	24541	-17.4	-1.3
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21343	21395	17430	20071	-6.0	-6.2
1.2.3 चाय	4966	5294	5832	5458	9.9	3.1
1.2.4 अन्य	101044	96276	89044	95508	-5.5	-0.8
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	14662	14214	14030	15034	2.5	5.8
1.4 वस्त्र	203549	199888	186323	189152	-7.1	-5.4
1.4.1 सूती वस्त्र	97726	99982	83448	85688	-12.3	-14.3
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2119	2095	2181	2215	4.5	5.7
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26748	24141	25820	26170	-2.2	8.4
1.4.4 अन्य वस्त्र	76956	73670	74874	75079	-2.4	1.9
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11071	10749	10813	10949	-1.1	1.9
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	11968	11478	11968	12067	0.8	5.1
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30319	29968	30230	30697	1.2	2.4
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	63136	56812	52466	53536	-15.2	-5.8
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	191484	177377	173231	177427	-7.3	0.0
1.9.1 उर्वरक	40043	27249	34112	34375	-14.2	26.2
1.9.2 औषधि और दवाइयां	50500	50954	48501	49839	-1.3	-2.2
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46717	46271	37445	39154	-16.2	-15.4
1.9.4 अन्य	54224	52903	53173	54059	-0.3	2.2
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	45803	44658	47029	49164	7.3	10.1
1.11 कांच और कांच के सामान	9887	10119	8686	8784	-11.2	-13.2
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55683	55013	59309	58502	5.1	6.3
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	371564	379892	347906	337587	-9.1	-11.1
1.13.1 लोहा और स्टील	282878	292174	265599	254848	-9.9	-12.8
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88686	87718	82307	82739	-6.7	-5.7
1.14 सभी अभियांत्रिकी	168621	161480	162680	158648	-5.9	-1.8
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	37856	37398	32895	33145	-12.4	-11.4
1.14.2 अन्य	130765	124082	129785	125503	-4.0	1.1
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	79859	80816	81472	82840	3.7	2.5
1.16 रत्न और आभूषण	72014	67978	61310	60452	-16.1	-11.1
1.17 निर्माण	99473	92838	100091	102579	3.1	10.5
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1055921	971924	1025154	1029417	-2.5	5.9
1.18.1 पावर	568966	547618	562711	562025	-1.2	2.6
1.18.2 दूरसंचार	115585	90603	130960	134310	16.2	48.2
1.18.3 सड़क	186852	186983	186529	186870	0.0	-0.1
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184518	146720	144954	146212	-20.8	-0.3
1.19 अन्य उद्योग	201954	194667	221247	229218	13.5	17.7

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018	2019						
		नवंबर, 30	सितंबर, 13	सितंबर, 27	अक्तूबर, 11	अक्तूबर, 25	नवंबर, 08	नवंबर, 22	नवंबर, 29
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	31	30	30	30	30	29	30	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	62003.4	54000.2	63423.7	62908.4	62777.3	63217.0	62705.3	64039.0	65921.6
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	18241.3	16400.1	18611.6	18621.8	18129.1	18067.8	17776.6	18086.2	18502.7
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	4908.8	5229.1	5430.0	5159.1	5177.4	4984.9	5157.7	5353.2
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	8473.5	9467.8	9639.3	9385.4	9439.3	9232.9	9891.0	9997.5
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	3017.8	3914.6	3532.4	3564.6	3431.1	3558.8	3017.5	3152.0
2.2 मीयादी देयताएं	98531.4	85664.6	106990.8	107416.5	108105.1	109131.6	109411.3	110399.6	113574.2
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	39373.0	52259.6	53251.8	53846.0	54502.9	55098.0	55354.5	56770.2
2.2.1.2 अन्य	52194.8	45526.7	53955.9	53269.0	53391.9	53777.6	53472.4	54148.0	55924.1
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	0.6	0.0	0.0	34.9	0.0	5.0	0.0	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	764.3	775.3	895.6	832.2	851.0	835.9	897.1	879.8
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	52266.2	44323.7	44794.9	41809.7	45180.3	43499.4	42985.4	46581.3
4.1 मांग	16826.7	16834.2	13879.2	13568.4	12371.6	12636.9	12842.2	12591.5	13300.6
4.2 मीयादी	33548.7	35432.0	30444.5	31226.5	29438.0	32543.4	30657.2	30393.9	33280.7
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5721.0	4258.8	5927.0	5487.0	5619.6	6010.5	5213.4	5418.8	6014.5
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	315.2	296.8	286.7	297.4	289.4	300.1	311.1	307.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	3943.6	5630.3	5200.3	5322.2	5721.0	4913.3	5107.7	5706.7
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1543.2	1127.3	1005.7	796.9	685.0	695.9	740.1	974.0	716.0
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	30885.3	31000.1	30656.8	31724.0	31460.3	32366.1	33174.3	33051.2	32995.3
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	16190.2	16683.6	18098.5	20083.3	17754.6	18708.5	17643.3	17282.6	20094.5
9 बैंक ऋण (10.1+11)	60089.8	55325.3	61037.6	62865.8	61797.8	62515.4	61915.1	74721.2	63337.3
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	60086.2	55322.3	61037.1	62865.3	61797.3	62514.9	61914.6	74720.6	63336.8
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	81237.1	75750.4	74965.4	75841.0	78322.8	77988.3	78925.3	80806.6
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	3.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	दिसंबर 18	नवंबर 19	दिसंबर 19	दिसंबर 18	नवंबर 19	दिसंबर 19	दिसंबर 18	नवंबर 19	दिसंबर 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	138.5	150.9	154.3	137.6	153.6	156.3	138.2	151.9	155.0
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	137.1	141.8	142.8	138.5	144.1	144.9	137.5	142.5	143.5
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	151.9	163.7	165.2	147.8	162.4	164.4	150.5	163.2	164.9
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	137.4	143.8	149.3	141.1	148.4	153.6	138.8	145.6	151.0
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	142.4	147.1	148.5	141.6	145.9	147.3	142.1	146.7	148.1
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	124.2	126.0	127.5	118.1	121.5	122.8	122.0	124.3	125.8
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	140.2	146.2	144.3	138.5	148.8	147.1	139.4	147.4	145.6
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	136.6	191.4	209.5	132.4	215.7	231.7	135.2	199.6	217.0
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	120.9	136.2	138.8	117.5	134.6	137.2	119.8	135.7	138.3
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	109.9	113.8	113.6	111.0	115.0	114.7	110.3	114.2	114.0
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	140.2	147.3	149.1	141.5	146.3	148.0	140.6	147.0	148.7
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	137.8	138.7	139.3	128.1	130.5	130.7	133.8	135.3	135.7
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	156.0	157.7	158.3	152.9	157.2	157.7	154.6	157.5	158.0
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	162.4	167.2	167.8	164.6	169.9	170.4	163.0	167.9	168.5
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	150.8	151.5	151.9	140.8	144.2	144.6	146.8	148.6	149.0
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	151.6	152.3	152.6	142.7	146.3	146.8	148.1	149.9	150.3
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	145.9	147.0	147.3	130.3	132.6	132.8	139.4	141.0	141.3
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	146.5	153.5	152.8	146.5	153.5	152.8
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	149.0	148.4	149.8	132.4	132.2	133.6	142.7	142.3	143.7
6 विविध	138.6	131.1	134.9	141.6	146.1	147.0	131.7	136.3	137.6	136.8	141.3	142.4
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	149.5	150.9	151.1	136.2	139.1	139.7	143.2	145.3	145.7
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	149.6	154.3	154.8	137.3	142.8	143.2	144.9	149.9	150.4
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	128.9	132.1	134.6	118.8	121.7	125.0	123.6	126.6	129.5
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	143.3	149.1	149.5	131.7	136.7	136.8	136.8	142.1	142.3
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	155.1	160.8	161.1	146.5	151.8	151.9	150.1	155.5	155.7
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	133.2	140.6	140.7	130.8	139.8	140.2	132.2	140.3	140.5
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	141.9	149.9	152.2	138.0	147.0	148.3	140.1	148.6	150.4

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2018		2019	
				दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	नवंबर
	1	2	3	4	5	6	
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	301	328	330	
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	913	1000	1014	
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	921	1006	1019	

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018		2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	नवंबर
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31193	31251	38122	38092	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38404	37095	44938	44576	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
				दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	119.8	119.7	122.0	122.3	122.8
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	133.5	145.5	147.3	148.8
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	143.5	160.2	162.4	162.5
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	146.7	150.4	160.8	162.5	163.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	140.4	194.2	199.4	196.6
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	143.7	146.2	146.4	147.5
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	140.1	145.6	148.6	148.8
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	129.1	148.8	153.0	154.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	145.9	142.9	142.5	143.5
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	124.4	126.1	127.0	134.0
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	128.6	126.4	123.5	123.7
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	140.9	151.4	149.6	152.9
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	107.8	103.1	104.1	105.4
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	176.4	207.4	238.5	348.3
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	139.3	153.6	154.8	153.6
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	126.2	147.3	149.8	147.3
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	185.0	176.0	172.3	176.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	83.3	82.8	83.1	86.0
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	102.8	102.3	101.3	101.3
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.4	126.5	124.8	126.5
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	133.3	141.9	136.5	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	94.2	92.8	91.6	91.2
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	110.7	110.0	110.0	110.0
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	118.3	117.8	117.8	118.0
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	127.8	134.6	135.3	136.6
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	136.4	139.6	137.5	135.0
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस,मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	134.8	139.3	138.9	136.6
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	113.4	113.5	114.6	115.0
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	113.9	116.6	119.0	124.9
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	133.3	145.8	147.0	149.1
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	144.0	148.3	148.3	147.6
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	120.1	136.8	135.2	136.3
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	129.7	133.3	133.9	134.4
1.3.1.9 चीनी,गुड़ और शहद	1.163	111.2	110.2	119.9	119.8	119.1
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	126.6	128.5	126.8	128.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स,और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	137.0	135.8	132.6	123.4
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	136.5	142.8	142.7	138.4
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	123.4	134.4	135.5	134.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	127.3	126.7	126.7	127.8
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	145.9	167.5	167.5	165.2
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	159.2	180.1	178.6	175.2
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	121.8	123.2	123.8	123.4
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	115.3	117.9	118.4	118.3
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	121.4	126.4	125.8	125.1
1.3.2.3 शीतल पेय,मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	131.9	128.6	130.0	129.5
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	149.2	154.4	153.2	152.9
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	149.2	154.4	153.2	152.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
				दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	118.9	117.3	117.1	116.9
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	110.9	107.4	106.5	106.2
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	128.4	129.3	130.1	129.8
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	113.8	115.2	114.5	114.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	134.6	135.2	135.4	135.0
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	139.4	143.0	146.0	146.5
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	120.5	117.8	118.0	116.8
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	138.7	138.4	138.9	139.1
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	139.3	138.9	139.6	140.1
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	137.2	136.8	137.2	136.6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	120.8	118.5	118.7	118.9
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	111.0	108.2	105.5	106.0	104.4
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	134.2	136.4	135.9	136.4
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	123.5	123.2	120.0	120.3	121.2
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.5	134.4	133.7	133.7	133.1
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	127.3	120.9	120.2	120.5
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.3	137.4	135.8	134.9	135.2
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	158.7	157.0	176.1	176.3	177.8
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	122.7	125.9	130.2	123.7
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	125.3	120.1	119.7	119.5
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	129.3	132.3	123.0	122.5	123.0
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	118.5	114.7	114.1	112.9
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	120.8	120.9	120.9	120.6
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	146.6	152.1	152.3	150.3
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	146.6	152.1	152.3	150.3
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	120.0	117.1	116.8	116.2
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	126.7	118.9	117.7	116.8
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	123.6	122.9	123.4	123.8
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	116.9	112.1	111.8	109.0
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	120.2	119.7	123.0	122.7	121.4
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	113.1	113.8	114.0	114.0
1.3.10.6 साबुन और डिटरजेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	117.5	118.4	117.9	118.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	117.4	113.7	113.8	113.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	103.3	97.3	96.7	96.2
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	123.4	126.8	126.6	127.9
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	123.4	126.8	126.6	127.9
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	110.2	108.4	107.7	108.3
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.8	98.0	98.3	98.4
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	91.8	94.1	94.0	93.9
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	118.3	115.5	114.4	115.2
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	115.3	115.4	115.4	115.8
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	122.6	121.0	120.8	125.3
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	110.8	109.3	108.5	106.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	96.4	102.5	100.1	105.6
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.3	112.7	112.5	113.3
1.3.13.5 सीमेन्ट, गूना और प्लास्टर	1.645	114.3	112.9	118.2	118.6	118.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
				दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	120.6	121.3	121.4	122.5
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	118.8	118.5	119.0	118.2	119.0
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	135.9	84.9	84.9	80.6
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	112.3	103.4	103.3	103.5
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	113.3	95.1	96.1	96.5
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	117.8	117.5	102.1	101.8	102.8
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	98.7	92.8	92.5	93.6
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	110.2	110.3	102.6	101.8	103.1
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	119.6	119.7	103.3	102.3	103.4
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	110.3	98.9	99.4	97.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	112.8	98.8	99.7	98.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	127.3	125.1	123.1	123.4
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	111.3	106.4	106.6	106.3
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	109.8	113.5	112.4	111.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	136.8	148.5	150.4	149.7
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	115.7	115.1	115.5	115.6
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	114.1	113.6	113.5	113.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	127.3	125.0	125.6	124.9
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	105.9	103.8	106.3	106.3	106.3
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	96.8	100.2	99.6	100.3
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	100.2	100.5	100.3	100.0
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	124.3	121.9	123.6	124.3
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	111.6	109.8	109.5	110.0
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	100.9	98.3	97.7	97.6
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	135.1	135.1	135.0	135.0
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.8	117.5	118.4	118.9
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	102.6	97.2	95.3	96.7
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	105.4	110.3	112.5	113.5
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	138.6	138.7	139.7	139.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	105.4	102.5	103.1	101.4
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	107.4	109.4	109.4	111.0
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	112.2	111.2	110.9	110.6
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	108.8	108.5	108.8	108.1
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	117.7	117.0	117.3	115.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	128.7	108.4	105.2	108.1
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	111.5	110.0	110.1	110.0
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	106.4	112.6	111.8	110.4
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	120.8	120.5	120.1	120.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	109.8	107.6	105.0	106.9
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	111.8	112.7	112.6	113.0
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन,एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	102.9	103.4	104.1	105.0
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	118.7	120.2	120.2	120.1
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.2	111.0	110.9	111.1
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	110.7	109.9	107.2	109.1
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	78.2	77.7	80.1	80.4	80.6
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	112.2	110.8	111.3	112.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
				दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	129.9	130.2	128.6	130.5
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	118.0	121.3	120.9	121.1
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	103.3	107.9	107.9	109.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.5	74.2	74.1	74.3
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	127.5	125.7	125.7	124.2
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	118.0	117.7	117.7	117.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	124.3	126.2	127.6	127.0
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	65.8	66.6	65.4
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रैलरों और अर्ध-ट्रैलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	112.9	114.7	115.7	114.9
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	114.3	115.2	115.2	115.0
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	111.4	114.2	116.3	114.8
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	112.5	118.0	118.3	118.4
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	104.3	106.6	106.6	106.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	107.5	114.4	114.7	114.7
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	129.2	128.1	128.1	130.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	124.9	125.9	126.9	127.0
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	129.7	131.6	131.2	129.9
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	129.7	131.6	131.2	129.9
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	114.5	116.7	113.6	114.1
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	111.9	114.1	110.7	111.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	172.0	166.4	175.9	172.7
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	128.9	129.8	130.9	131.4
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	132.2	132.4	135.9	137.0	138.7
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.3	162.5	162.5	162.5
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	137.6	150.6	152.3	152.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भासंक	2017-18	2018-19	अप्रैल-नवंबर		नवंबर	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	127.7	128.5	126.1	128.4
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	104.9	107.9	102.0	101.9	110.6	112.5
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	129.0	130.1	126.8	130.2
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	160.5	161.8	147.3	139.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	124.3	124.4	124.8	124.4
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	106.7	94.3	100.0	91.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	123.1	138.1	120.2	140.7
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	138.8	135.0	135.5	130.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	131.9	123.3	118.3	116.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	139.1	144.5	148.6	151.6

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नजर में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-दिसंबर			
	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	1850101	1146897	1084044	62.0	62.7
1.1 कर राजस्व (निवल)	1504587	904944	936333	60.1	63.1
1.2 करेतर राजस्व	345514	241953	147711	70.0	60.2
2 पूंजीगत प्राप्तियां	81605	31025	46532	38.0	50.0
2.1 ऋण की वसूली	16605	12925	12317	77.8	93.6
2.2 अन्य प्राप्तियां	65000	18100	34215	27.8	42.8
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1931706	1177922	1130576	61.0	62.0
4 राजस्व व्यय	2349645	1854125	1620211	78.9	75.7
4.1 ब्याज भुगतान	625105	424314	421193	67.9	71.7
5 पूंजी व्यय	348907	255522	211822	73.2	66.9
6 कुल व्यय (4+5)	2698552	2109647	1832033	78.2	74.6
7 राजस्व घाटा (4-1)	499544	707228	536167	141.6	130.5
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2)}	766846	931725	701457	121.5	110.6
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	141741	507411	280264	358.0	598.5

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018		2019				
		दिसंबर 28	नवंबर 22	नवंबर 29	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20	दिसंबर 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18521	38010	16907	15658	16420	16035	15169	15629
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	17327	16006	14558	16936	13869	15432	13566
1.3 राज्य सरकारें	26999	74831	58739	62729	51324	50324	53449	55446
1.4 अन्य	27747	48183	87989	93697	93862	100260	101107	105392
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	31953	40399	73881	72356	71077	70225	70248	69389
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	42813	26258	27263	28448	27728	25631	26616
2.3 राज्य सरकारें	28036	34448	6087	6078	7078	7068	6945	6945
2.4 अन्य	18567	18781	28958	26531	23730	22444	22582	19404
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	48811	52933	62867	61801	61997	59819	60357	58261
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	81546	59216	61512	60150	59822	57387	58889
3.3 राज्य सरकारें	18892	18092	17920	17890	21790	21790	21790	21790
3.4 अन्य	62393	62439	55177	53155	53410	54816	55663	55247
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	165605	140624	141900	129972	78618	62470	137981	140863
4.4 अन्य	252	483	333	243	253	478	377	372
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	412704	529801	510007	513228	506222	504199	505762	506574

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या				कुल अंकित मूल्य	
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
नवंबर 27	10000	79	69336	8001	11	9999	8001	18000	98.77	4.9896
दिसंबर 4	10000	74	44134	4842	25	9989	4842	14831	98.80	4.8901
दिसंबर 11	10000	95	54019	1123	28	9998	1123	11121	98.77	4.9982
दिसंबर 18	10000	79	43980	8995	31	9981	8995	18976	98.77	5.0073
जनवरी 24	10000	72	33660	6005	34	10000	6005	16005	98.76	5.0258
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
नवंबर 27	4000	49	12578	17	8	3983	17	4000	97.51	5.1197
दिसंबर 4	4000	75	20040	1011	15	3989	1011	5000	97.53	5.0695
दिसंबर 11	4000	69	10943	7	37	3993	7	4000	97.48	5.1866
दिसंबर 18	4000	54	10261	10	26	3990	10	4000	97.48	5.1938
जनवरी 24	4000	59	14126	9	23	3991	9	4000	97.46	5.2197
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
नवंबर 27	3000	57	11882	0	4	3000	0	3000	95.13	5.1389
दिसंबर 4	3000	88	13487	4001	15	2999	4001	7000	95.16	5.0990
दिसंबर 11	3000	72	11092	0	32	3000	0	3000	95.03	5.2476
दिसंबर 18	3000	56	7327	1	35	2999	1	3000	95.01	5.2665
जनवरी 24	3000	61	10704	0	21	3000	0	3000	94.98	5.3000

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	
		भारत औसत दरें	
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
दिसंबर	2, 2019	3.60-5.25	4.99
दिसंबर	3, 2019	3.60-5.25	5.05
दिसंबर	4, 2019	3.70-5.30	5.02
दिसंबर	5, 2019	3.50-5.25	5.03
दिसंबर	6, 2019	3.70-5.25	5.02
दिसंबर	7, 2019	3.50-5.20	4.69
दिसंबर	9, 2019	3.70-5.25	5.01
दिसंबर	10, 2019	3.70-5.25	4.99
दिसंबर	11, 2019	3.70-5.25	5.00
दिसंबर	12, 2019	3.50-5.25	4.95
दिसंबर	13, 2019	3.60-5.25	4.97
दिसंबर	16, 2019	3.60-5.30	5.08
दिसंबर	17, 2019	3.60-5.25	5.06
दिसंबर	18, 2019	3.60-5.25	5.06
दिसंबर	19, 2019	3.60-5.25	4.99
दिसंबर	20, 2019	3.70-5.25	5.07
दिसंबर	21, 2019	4.30-5.25	4.89
दिसंबर	23, 2019	3.70-5.30	5.11
दिसंबर	24, 2019	3.70-5.25	5.12
दिसंबर	26, 2019	3.60-5.30	5.12
दिसंबर	27, 2019	3.40-5.30	5.11
दिसंबर	30, 2019	3.40-5.25	5.09
दिसंबर	31, 2019	3.70-5.30	5.10
जनवरी	1, 2020	3.60-5.25	5.12
जनवरी	2, 2020	3.00-5.25	5.01
जनवरी	3, 2020	2.75-5.25	4.89
जनवरी	4, 2020	4.15-5.15	4.69
जनवरी	6, 2020	2.75-5.25	4.89
जनवरी	7, 2020	3.00-5.25	4.92
जनवरी	8, 2020	3.40-5.25	4.91
जनवरी	9, 2020	3.50-5.25	4.96
जनवरी	10, 2020	3.60-5.25	4.98
जनवरी	13, 2020	3.60-5.25	4.97
जनवरी	14, 2020	3.60-5.25	4.97
जनवरी	15, 2020	3.60-5.25	4.94

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2018		2019		
	दिसंबर 21	नवंबर 8	नवंबर 22	दिसंबर 6	दिसंबर 20
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	180664.01	171696.00	162443.00	163198.00	160669.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	32220.22	10862.41	15649.53	14847.44	13837.13
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.83-9.02	5.15-7.31	5.04-7.24	4.96-6.80	4.97-5.84

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018		2019		
	दिसंबर 31	नवंबर 15	नवंबर 30	दिसंबर 15	दिसंबर 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	498728.65	461813.40	458415.60	457213.55	414906.30
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	95777.10	94360.65	80022.90	97114.00	83567.75
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.78-10.29	4.78-13.23	5.01-13.30	4.88-12.65	4.99-13.18

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018		2019				
		दिसंबर 21	नवंबर 22	नवंबर 29	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20	दिसंबर 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	31280	37204	21914	18304	17179	20606	22788	27553
2 नोटिस मुद्रा	4930	6006	196	3595	5338	202	7194	238
3 मीयादी मुद्रा	740	201	743	757	642	479	510	939
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	213010	251875	308704	379116	325120	352328	413105	339731
5 बाजार रिपो	200970	173304	189037	259645	229520	234024	270854	230092
6 कापॉरेट बांड में रिपो		5924	2074	2953	1554	4158	98	1528
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	65507	59361	70279	53349	64953	62050	66546
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65800	88458	95305	70233	82536	61668	59986	70654
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4320	7933	5598	4846	6775	5274	2512	5891
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3380	6924	4035	2223	6653	3746	4766	6094
10.2 182-दिवसीय	1450	2191	1683	1505	2156	1457	1942	1577
10.3 364-दिवसीय	1620	4746	1700	1901	3381	1601	1970	1019
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1400		90	6	996	530	122	
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970	110252	108411	80714	102496	74277	71298	85234
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	3065	29	240	285	81	3393	4670

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रै.-दिसं.)*		2019-20 (अप्रै.-दिसं.)*		दिसंबर 2018		दिसंबर 2019*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	16754	106	14519	56	61035	4	765	4	1264
1ए प्रीमियम	124	16085	104	14015	55	39411	4	702	4	1033
1.1 पब्लिक	119	14605	100	12677	45	9780	2	49	4	1264
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	98	12307	44	9373	2	44	4	1033
1.2 राइट्स	10	2149	6	1843	11	51255	2	715	—	—
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	6	1708	11	30038	2	659	—	—
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	25	36680	15	28565	27	11746	1	264	3	2519
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	15	28565	27	11746	1	264	3	2519
3.1.1 पब्लिक	25	36680	15	28565	27	11746	1	264	3	2519
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3+4)	154	53433	121	43085	83	72781	5	1028	7	3783
4.1 पब्लिक	144	51284	115	41242	72	21526	3	313	7	3783
4.2 राइट्स	10	2149	6	1843	11	51255	2	715	—	—

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018		2019			
			दिसंबर	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2307726	197045	185276	186202	188126	185360	194765
	मिलियन अमरिकी डालर	330078	27858	26042	26103	26482	25942	27357
1.1 तेल	करोड ₹	325929	28777	22777	24735	26042	29177	27743
	मिलियन अमरिकी डालर	46554	4069	3202	3468	3666	4083	3897
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1981797	168268	162499	161467	162085	156183	167022
	मिलियन अमरिकी डालर	283525	23790	22840	22635	22816	21859	23461
2 आयात	करोड ₹	3594675	299553	283351	268472	265727	272273	274884
	मिलियन अमरिकी डालर	512793	42351	39827	37636	37406	38106	38611
2.1 तेल	करोड ₹	986275	76276	78049	64374	68781	79038	76137
	मिलियन अमरिकी डालर	140921	10784	10970	9024	9682	11062	10694
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2608400	223278	205302	204098	196946	193235	198747
	मिलियन अमरिकी डालर	371872	31567	28857	28612	27723	27044	27917
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1286948	-102509	-98075	-82269	-77601	-86913	-80119
	मिलियन अमरिकी डालर	-182714	-14493	-13785	-11533	-10924	-12164	-11254
3.1 तेल	करोड ₹	-660346	-47498	-55272	-39639	-42740	-49861	-48394
	मिलियन अमरिकी डालर	-94367	-6715	-7769	-5557	-6016	-6978	-6798
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-626602	-55010	-42804	-42631	-34861	-37052	-31725
	मिलियन अमरिकी डालर	-88347	-7777	-6016	-5976	-4907	-5186	-4456

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019					2020	
		जनवरी 11	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20	दिसंबर 27	जनवरी 3	जनवरी 10
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	2798800	3234873	3219350	3235017	3264729	3311099	3272431
	मिलियन अमरिकी डालर	397352	453422	454492	454948	457468	461157	461214
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	2617250	3005418	2992223	3005923	3032614	3072705	3033747
	मिलियन अमरिकी डालर	371379	421258	422422	422732	424936	427949	427582
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	152460	193185	191029	192925	195484	201456	202156
	मिलियन अमरिकी डालर	21844	27078	26968	27132	27392	28058	28492
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1052	1046	1046	1046	1046	1046	1046
	करोड ₹	10370	10282	10226	10257	10281	10392	10235
	मिलियन अमरिकी डालर	1472	1441	1444	1443	1441	1447	1442
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	18720	25989	25872	25912	26349	26545	26294
	मिलियन अमरिकी डालर	2656	3644	3658	3642	3700	3703	3697

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरिकी डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130423	125773	132699	133135	6977	5859
1.1 एफसीएनआर (बी)	23170	20840	24326	24018	-1186	848
1.2 एनआर (ई) आरए	92017	90254	92325	92889	6604	3562
1.3 एनआरओ	15236	14680	16049	16228	1558	1449

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30712	24292	27589	3112	1068	3016
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	43302	33512	36151	4237	1720	4046
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	62001	46540	51429	5950	4440	6766
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45055	33997	37274	4449	2862	4717
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2429	2033	3028	1	58	45
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	36315	27820	28460	4264	2210	3646
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5622	3640	5281	126	536	967
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	505	505	58	58	58
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13672	10022	9953	1150	1150	1150
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3274	2521	4202	351	428	899
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18699	13028	15278	1713	2720	2720
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18452	12816	15117	1700	2719	2719
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	212	161	13	1	1
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12590	9220	8562	1124	652	1030
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7201	5519	4382	766	331	324
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3032	2274	2319	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5202	3079	3709	313	341	726
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	2845	1652	1848	208	272	272
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-10054	12153	-1344	2120	-496
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1820	1820	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2225	-13693	12777	-1370	2726	109
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-1820	624	-26	606	606
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30094	14238	39743	1769	3188	2519

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		दिसंबर	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13787.58	1093.10	1523.77	1482.00	1563.72
1.1 जमाराशियां	455.94	31.62	39.57	39.42	42.38
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.53	5.38	8.65	7.14	4.85
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.90	34.29	38.80	73.99	27.57
1.4 उपहार	1370.24	110.36	148.39	153.02	150.90
1.5 दान	8.67	1.32	0.71	0.48	0.89
1.6 यात्रा	4803.81	386.18	578.97	522.28	620.32
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2800.88	223.27	256.77	262.96	276.74
1.8 चिकित्सा उपचार	28.59	1.86	3.18	3.04	2.68
1.9 विदेश में शिक्षा	3569.87	277.88	432.66	400.98	420.45
1.10 अन्य	242.15	20.97	16.08	18.69	16.93

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2019		2020
			जनवरी	दिसंबर	जनवरी
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	72.23	72.67	72.26
1.2 रीर	119.71	114.01	113.29	117.85	117.18
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	73.81	74.00	73.72
2.2 रीर	121.94	116.32	115.55	120.35	119.90
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	62.76	63.35	62.98
1.2 रीर	129.19	121.70	120.67	128.72	127.22
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	92.42	93.28	92.74
2.2 रीर	100.00	94.20	93.41	99.64	98.47

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार पंजीकरण

(राशि अमरिकी मिलियन डालर में)

मद	2018-19	2018	2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	66	122	109
1.2 राशि	28387	3332	2116	1257
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	1	-	4
2.2 राशि	13537	474	-	840
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1020	67	122	113
3.2 राशि	41924	3806	2116	2097
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	5.50	7.10	4.70
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	1.15	2.03	1.41
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.00-12.00	0.00-15.00	0.00-25.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्र.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	290140	292008	-1868	301536	296418	5118
1 चालू खाता (1.1+1.2)	160019	179073	-19054	161210	167487	-6276
1.1 पण्य	83399	133436	-50037	80014	118097	-38083
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	76620	45637	30984	81196	49390	31806
1.2.1 सेवाएं	50094	29839	20256	52380	31937	20443
1.2.1.1 यात्रा	7038	5813	1225	7643	6031	1611
1.2.1.2 परिवहन	4641	5086	-446	5183	6009	-826
1.2.1.3 बीमा	646	396	250	603	354	249
1.2.1.4 जीएनआईई	140	261	-122	169	298	-128
1.2.1.5 विविध	37629	18282	19348	38782	19245	19537
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	20757	1472	19286	23247	2182	21064
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9408	9690	-282	10878	11211	-333
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1311	1132	180	1239	594	645
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	606	278	328	635	354	281
1.2.2 अंतरण	20891	1560	19331	21986	1999	19986
1.2.2.1 आधिकारिक	35	215	-180	50	251	-202
1.2.2.2 निजी	20856	1346	19511	21936	1748	20188
1.2.3 आय	5635	14238	-8603	6831	15454	-8623
1.2.3.1 निवेश आय	4560	13646	-9086	5426	14791	-9364
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1074	592	482	1404	663	741
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	129539	112935	16604	140326	128273	12053
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	77035	69423	7612	85399	75487	9913
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	14827	7417	7410	15298	7862	7436
2.1.1.1 भारत में	14076	4055	10021	14523	4482	10041
2.1.1.1.1 इक्विटी	10081	3894	6187	9935	4446	5489
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3344		3344	3310		3310
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	652	161	490	1279	37	1242
2.1.1.2 विदेश में	751	3361	-2610	775	3380	-2605
2.1.1.2.1 इक्विटी	751	1376	-625	775	1478	-703
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	780	-780
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1228	-1228	0	1122	-1122
2.1.2 संविभाग निवेश	62208	62006	202	70101	67625	2476
2.1.2.1 भारत में	61036	61616	-580	68312	66307	2005
2.1.2.1.1 एफआईआई	59216	61616	-2400	68312	66307	2005
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	50860	52179	-1319	48252	51608	-3355
2.1.2.1.1.2 ऋण	8356	9436	-1081	20059	14699	5361
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	1820	0	1820	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1173	391	782	1789	1318	471
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	23578	16652	6926	21567	18396	3171
2.2.1 बाह्य सहायता	1216	1264	-48	1805	1362	443
2.2.1.1 भारत द्वारा	12	30	-18	5	24	-19
2.2.1.2 भारत को	1204	1234	-30	1800	1338	462
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8951	6766	2185	9030	5656	3374
2.2.2.1 भारत द्वारा	1515	1349	166	1287	1082	205
2.2.2.2 भारत को	7436	5417	2019	7743	4574	3169
2.2.3 भारत को अल्पावधि	13411	8622	4789	10731	11378	-646
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	7392	8622	-1230	10731	10940	-209
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	6019	0	6019	0	437	-437
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21194	20672	522	23881	25699	-1818
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21194	20670	524	23881	25364	-1483
2.3.1.1 आस्तियां	5370	5638	-268	9914	10148	-235
2.3.1.2 देयताएं	15823	15031	792	13967	15216	-1249
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	15402	12075	3326	13458	11178	2280
2.3.2 अन्य	0	2	-2	0	335	-335
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	1	-1	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	7732	6187	1545	9479	8689	790
3 भूल-चूक	582		582		658	-658
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	1868	0	1868	0	5118	-5118
4.1 आईएमएफ	0	0	0			
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	1868	0	1868		5118	-5118

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2035381	2048484	-13103	2123697	2087648	36049
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1122561	1256224	-133664	1135391	1179595	-44204
1.1 पण्य	585056	936075	-351019	563533	831746	-268213
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	537505	320150	217355	571858	347850	224009
1.2.1 सेवाएं	351421	209324	142097	368905	224927	143978
1.2.1.1 यात्रा	49373	40780	8593	53826	42478	11348
1.2.1.2 परिवहन	32556	35682	-3126	36504	42320	-5817
1.2.1.3 बीमा	4534	2780	1755	4245	2494	1751
1.2.1.4 जीएनआईई	981	1834	-853	1193	2096	-904
1.2.1.5 विविध	263977	128249	135728	273138	135539	137599
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	145615	10323	135292	163725	15370	148355
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	65998	67978	-1981	76611	78960	-2348
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9200	7939	1261	8729	4187	4543
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4252	1951	2302	4475	2494	1981
1.2.2 अंतरण	146556	10945	135611	154844	14081	140763
1.2.2.1 आधिकारिक	246	1506	-1260	349	1768	-1419
1.2.2.2 निजी	146310	9439	136871	154495	12313	142182
1.2.3 आय	39528	99881	-60353	48109	108842	-60733
1.2.3.1 निवेश आय	31992	95729	-63736	38218	104171	-65953
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7535	4152	3383	9891	4671	5220
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	908738	792260	116478	988305	903419	84886
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	540417	487014	53403	601461	531648	69814
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	104014	52029	51985	107745	55373	52372
2.1.1.1 भारत में	98746	28449	70297	102287	31568	70719
2.1.1.1.1 इक्विटी	70719	27316	43403	69970	31310	38661
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	23456	0	23456	23309	0	23309
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4570	1132	3438	9007	258	8749
2.1.1.2 विदेश में	5268	23581	-18313	5458	23805	-18346
2.1.1.2.1 इक्विटी	5268	9650	-4382	5458	10409	-4950
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5318	-5318	0	5496	-5496
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8613	-8613	0	7900	-7900
2.1.2 संविभाग निवेश	436403	434985	1418	493716	476275	17441
2.1.2.1 भारत में	428177	432244	-4067	481114	466993	14122
2.1.2.1.1 एफआईआई	415410	432244	-16834	481114	466993	14122
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	356793	366047	-9253	339837	363469	-23632
2.1.2.1.1.2 ऋण	58616	66197	-7581	141277	103523	37754
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	12768	0	12768	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8226	2741	5485	12602	9283	3320
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	165403	116817	48586	151892	129560	22332
2.2.1 बाह्य सहायता	8528	8864	-336	12711	9592	3120
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	36	169	-132
2.2.1.2 भारत को	8447	8655	-208	12675	9423	3252
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	62796	47467	15329	63600	39837	23764
2.2.2.1 भारत द्वारा	10627	9465	1162	9066	7623	1444
2.2.2.2 भारत को	52168	38001	14167	54534	32214	22320
2.2.3 भारत को अल्पावधि	94079	60487	33592	75580	80132	-4551
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	51855	60487	-8632	75580	77050	-1470
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	42224	0	42224	0	3081	-3081
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	148677	145018	3659	168191	180998	-12807
2.3.1 वाणिज्य बैंक	148677	145002	3675	168191	178639	-10448
2.3.1.1 आस्तियां	37674	39555	-1881	69820	71474	-1654
2.3.1.2 देयताएं	111003	105447	5556	98370	107165	-8794
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	108045	84711	23334	94785	78728	16056
2.3.2 अन्य	0	16	0	0	2359	-2359
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	9	-9	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	54241	43401	10840	66761	61198	5563
3 भूल-चूक	4083	0	4083	0	4633	-4633
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	13103	0	13103	0	36049	-36049
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/कमी +)	13103	0	13103	0	36049	-36049

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	160019	179051	-19033	161208	167462	-6254
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	133493	163275	-29781	132394	150033	-17640
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	83399	133436	-50037	80014	118097	-38083
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	83400	124239	-40839	79356	113743	-34388
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-1	0	-1	658	0	658
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		9197	-9197		4353	-4353
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	50094	29839	20256	52380	31937	20443
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	58	8	50	58	33	25
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	43	259	-216	44	253	-208
1.अ.ख.3 परिवहन	4641	5086	-446	5183	6009	-826
1.अ.ख.4 यात्रा	7038	5813	1225	7643	6031	1611
1.अ.ख.5 निर्माण	766	635	131	677	714	-37
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	646	396	250	603	354	249
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1311	1132	180	1239	594	645
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	162	1942	-1780	248	1776	-1528
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	21428	1869	19559	23947	2654	21293
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9408	9690	-282	10878	11211	-333
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	447	774	-328	551	923	-372
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	140	261	-122	169	298	-128
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	4007	1972	2035	1139	1085	54
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5635	14238	-8603	6831	15454	-8623
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1074	592	482	1404	663	741
1.आ.2 निवेश आय	3486	13340	-9854	4372	14576	-10204
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1788	6108	-4320	1756	6902	-5146
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	53	3525	-3471	54	3760	-3706
1.आ.2.3 अन्य निवेश	135	3694	-3559	602	3899	-3297
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1508	13	1495	1960	15	1945
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1075	306	769	1055	215	840
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	20891	1539	19352	21984	1975	20009
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20856	1346	19511	21936	1748	20188
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20224	991	19233	21291	1336	19955
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	633	354	278	645	412	233
1.इ.2 सामान्य सरकार	35	193	-159	48	227	-179
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	75	96	-21	90	186	-97
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	2	4	-2	9	93	-84
2.2 पूंजी अंतरण	72	92	-19	81	93	-12
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	131333	112861	18472	140238	133230	7008
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	14827	7417	7410	15298	7862	7436
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14076	4055	10021	14523	4482	10041
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13425	3894	9531	13244	4446	8799
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10081	3894	6187	9935	4446	5489
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3344		3344	3310		3310
3.1.अ.2 ऋण लिखत	652	161	490	1279	37	1242
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	652	161	490	1279	37	1242
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	751	3361	-2610	775	3380	-2605
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	751	2134	-1383	775	2258	-1483
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	751	1376	-625	775	1478	-703
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		780	-780
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1228	-1228	0	1122	-1122
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1228	-1228		1122	-1122
3.2 संविभाग निवेश	60388	62006	-1618	70101	67625	2476
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	59216	61616	-2400	68312	66307	2005
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	50860	52179	-1319	48252	51608	-3352
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	8356	9436	-1081	20059	14699	5361
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1173	391	782	1789	1318	471
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5623	4344	1278	7395	7138	257
3.4 अन्य निवेश	48627	39093	9534	47444	45487	1957
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	1820	0	1820	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	15402	12078	3324	13458	11513	1945
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	2	-2	0	335	-335
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	15402	12075	3326	13458	11178	2280
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	15959	16624	-665	21258	21204	54
3.4.3अ भारत को ऋण	14433	15245	-812	19965	20098	-132
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1527	1379	147	1292	1106	186
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	36	142	-106	54	71	-17
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	13411	8622	4789	10731	11378	-646
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	1999	1626	373	1942	1321	621
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार				0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	1868	0	1868	0	5118	-5118
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	1868	0	1868	0	5118	-5118
4. कुल आस्तियां / देयताएं	131333	112861	18472	140238	133230	7008
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	71867	63085	8782	71511	66838	4672
4.2 ऋण लिखत	53779	48150	5629	66786	59952	6833
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	5687	1626	4060	1942	6439	-4498
5. निवल भूल-चूक	582	0	582	0	658	-658

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1122558	1256075	-133518	1135379	1179423	-44044
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	936477	1145399	-208922	932438	1056673	-124234
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	585056	936075	-351019	563533	831746	-268213
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	585065	871555	-286490	558895	801084	-242189
1.अ.क.2 वाणिज्यिक अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-10	0	-10	4638	0	4638
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	64520	-64520	0	30661	-30661
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	351421	209324	142097	368905	224927	143978
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	408	56	351	408	235	173
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	305	1818	-1513	310	1779	-1468
1.अ.ख.3 परिवहन	32556	35682	-3126	36504	42320	-5817
1.अ.ख.4 यात्रा	49373	40780	8593	53826	42478	11348
1.अ.ख.5 निर्माण	5373	4456	917	4770	5031	-261
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4534	2780	1755	4245	2494	1751
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9200	7939	1261	8729	4187	4543
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1137	13626	-12489	1749	12511	-10762
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	150318	13109	137210	168656	18693	149963
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	65998	67978	-1981	76611	78960	-2348
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3133	5433	-2300	3882	6503	-2621
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	981	1834	-853	1193	2096	-904
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	28107	13834	14273	8021	7641	380
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	39528	99881	-60353	48109	108842	-60733
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7535	4152	3383	9891	4671	5220
1.आ.2 निवेश आय	24452	93582	-69130	30790	102655	-71866
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12545	42849	-30304	12365	48608	-36243
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	375	24727	-24352	380	26481	-26100
1.आ.2.3 अन्य निवेश	950	25914	-24964	4241	27463	-23223
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	10581	92	10489	13803	103	13700
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7540	2147	5394	7428	1515	5913
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	146553	10796	135757	154831	13908	140923
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	146310	9439	136871	154495	12313	142182
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	141872	6953	134920	149953	9410	140544
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4438	2486	1951	4542	2903	1639
1.इ.2 सामान्य सरकार	243	1357	-1113	336	1596	-1260
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	523	672	-150	632	1312	-680
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	14	28	-14	63	656	-593
2.2 पूँजी अंतरण	509	644	-135	569	656	-87
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	921321	791737	129585	987686	938328	49358
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	104014	52029	51985	107745	55373	52372
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	98746	28449	70297	102287	31568	70719
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	94175	27316	66859	93280	31310	61970
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	70719	27316	43403	69970	31310	38661
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23456	0	23456	23309	0	23309
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4570	1132	3438	9007	258	8749
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4570	1132	3438	9007	258	8749
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5268	23581	-18313	5458	23805	-18346
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5268	14968	-9700	5458	15904	-10446
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5268	9650	-4382	5458	10409	-4950
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5318	-5318	0	5496	-5496
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8613	-8613	0	7900	-7900
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8613	-8613	0	7900	-7900
3.2 संविभाग निवेश	423635	434985	-11350	493716	476275	17441
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	415410	432244	-16834	481114	466993	14122
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	356793	366047	-9253	339837	363469	-23632
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	58616	66197	-7581	141277	103523	37754
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8226	2741	5485	12602	9283	3320
3.3 वित्तीय डेबिटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	39443	30477	8966	52083	50270	1813
3.4 अन्य निवेश	341126	274245	66881	334142	320362	13780
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	12768	0	12768	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	108045	84728	23317	94785	81087	13697
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	16	-16	0	2359	-2359
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	108045	84711	23334	94785	78728	16056
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	111956	116621	-4665	149718	149339	379
3.4.3अ भारत को ऋण	101248	106947	-5699	140615	141548	-932
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	10709	9675	1034	9103	7791	1311
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	253	999	-746	383	501	-117
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	94079	60487	33592	75580	80132	-4551
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	14024	11410	2614	13676	9303	4373
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	13103	0	13103	0	36049	-36049
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	13103	0	13103	0	36049	-36049
4. कुल आस्तियां / देयताएं	921321	791737	129585	987686	938328	49358
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	504159	442549	61611	503643	470736	32907
4.2 ऋण लिखत	377267	337778	39489	470367	422240	48127
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	39895	11410	28485	13676	45352	-31676
5. निवल भूल-चूक	4083	0	4083	0	4633	-4633

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			सितंबर		जून		सितंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399234	163537	362031	173017	417292	175622	416476
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	107925	346220	112890	399381	114373	398164
1.2 अन्य पूंजी	58841	17129	55613	15811	60127	17911	61249	18312
2 संविभाग निवेश	4699	260313	2641	237895	5012	267073	4541	259993
2.1 इक्विटी	590	147479	1804	135249	1806	151162	2344	144039
2.2 ऋण	4109	112834	837	102645	3206	115912	2197	115953
3 अन्य निवेश	54538	419279	41541	395576	54511	429560	55904	430051
3.1 व्यापार ऋण	924	105191	904	104340	2140	107224	1707	106581
3.2 ऋण	9884	168112	7084	157613	9765	173962	7895	174988
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	16628	122137	24169	133846	27563	133105
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	16925	11486	18437	14529	18739	15378
4 रिज़र्व्स	412871		400525		429837		433707	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078827	608244	995501	662378	1113926	669775	1106520
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436755		-387257		-451548		-436745

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2018	2019		विव 2018-19	2018	2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	-	-	2.78	2.83	-	-	10655649	12196681
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	-	-	1.01	1.04	-	-	6869045	8085475
1.1.1 आउटराइट	-	-	0.63	0.61	-	-	862104	853262
1.1.2 रेपो	-	-	0.19	0.21	-	-	2359755	2950776
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	-	-	0.19	0.21	-	-	3647186	4281437
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	-	-	1.74	1.75	-	-	3525359	3831685
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	-	-	0.04	0.04	-	-	261245	279520
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	-	-	133.87	136.02	-	-	8679806	10316937
1.1 ग्राहक लेनदेन	-	-	131.61	133.82	-	-	7469569	8847761
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	-	-	2.27	2.20	-	-	1210237	1469176
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)	-	-	18750.48	20029.92	-	-	2226348	2440803
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	-	-	0.64	0.84	-	-	33	35
2.2 एपीबीएस \$	-	-	1364.56	1369.14	-	-	6908	6000
2.3 ईसीएस जमा	-	-	0.17	0.10	-	-	61	53
2.4 आईएमपीएस	-	-	2280.75	2564.67	-	-	202904	210934
2.5 एनएसीएच जमा \$	-	-	722.06	674.26	-	-	92562	79028
2.6 एनईएफटी	-	-	2194.59	2336.88	-	-	1734651	1942231
2.7 यूपीआई @	-	-	12187.71	13084.02	-	-	189229	202521
2.7.1 जिसमें से यूएसएसडी@	-	-	0.74	0.80	-	-	13	14
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)	-	-	766.41	790.71	-	-	70199	72455
3.1 भीम आधार पे @	-	-	6.46	7.37	-	-	97	112
3.2 ईसीएस नामे	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच नामे \$	-	-	758.18	769.31	-	-	70097	72306
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	-	-	1.77	14.02	-	-	5	37
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	-	-	6062.09	6615.52	-	-	137707	149688
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	-	-	1762.12	2036.64	-	-	60130	65736
4.1.1 पीओएस आधारित \$	-	-	1033.52	1181.09	-	-	31730	35157
4.1.2 अन्य \$	-	-	728.60	855.55	-	-	28401	30579
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	-	-	4299.96	4578.88	-	-	77577	83953
4.2.1 पीओएस आधारित \$	-	-	2483.18	2634.18	-	-	37007	39740
4.2.2 अन्य \$	-	-	1816.79	1944.70	-	-	40570	44213
5 प्रीपेड भुगतान साधन (5.1 से 5.2)	-	-	4672.07	5072.36	-	-	17844	18922
5.1 वालेट	-	-	3354.08	3651.56	-	-	14652	15835
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	-	-	1317.99	1420.80	-	-	3192	3088
5.2.1 पीओएस आधारित \$	-	-	123.86	121.90	-	-	738	1012
5.2.2 अन्य \$	-	-	1194.13	1298.91	-	-	2454	2076
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	-	-	866.12	865.46	-	-	644802	646583
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	-	-	864.86	864.44	-	-	643678	645573
6.2 अन्य	-	-	1.26	1.02	-	-	1124	1010
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	-	31117.17	33373.97	-	-	3096901	3328451
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	-	31251.05	33509.98	-	-	11776707	13645388
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	-	30384.93	32644.52	-	-	11131905	12998805

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)				
	विव 2018-19	2018		2019		विव 2018-19	2018		2019
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	दिसंबर		नवंबर	दिसंबर	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
ए. अन्य भुगतान चैनल									
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	-	13534.23	14322.15	-	-	471295	493342	
1.1 इंटर-बैंक \$	-	-	1234.84	1280.66	-	-	96802	101679	
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	12299.40	13041.49	-	-	374494	391663	
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	-	2687.09	2703.04	-	-	2490599	2968937	
2.1 इंटर-बैंक @	-	-	581.36	615.70	-	-	1045052	1423294	
2.2 अंतर-बैंक @	-	-	2105.73	2087.35	-	-	1445546	1545644	
बी. एटीएम									
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	-	6305.28	6518.97	-	-	285376	293087	
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	7.99	8.91	-	-	381	422	
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	6269.60	6481.81	-	-	284083	291704	
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	27.68	28.25	-	-	912	961	
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	-	66.63	79.45	-	-	130	176	
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	62.30	72.40	-	-	125	162	
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	4.32	7.05	-	-	5	14	
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	-	339.83	326.35	-	-	9648	9163	
5.1 एईपीएस @	-	-	339.83	326.35	-	-	9648	9163	

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	विव 2018-19	2018		2019	
		दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	
भुगतान प्रणाली अवसंरचना					
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	-	8851.69	8606.57	
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	544.11	553.33	
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	8307.59	8053.24	
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	-	17253.28	17625.43	
2.1 वॉलेट @	-	-	16243.87	16615.68	
2.2 कार्ड @	-	-	1009.41	1009.75	
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	-	2.32	2.32	
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	2.10	2.10	
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	0.22	0.22	
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	-	2.35	2.42	
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	-	48.83	49.88	
6 भारत क्यूआर @	-	-	15.94	18.89	

@: दिसंबर 2019 से नया समावेश

\$: दिसंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

- कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए दिसंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
- केवल धरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

प्रासंगिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2018	2019		
			अगस्त	जून	जुलाई	अगस्त
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115,714.00	8,033.00	9,710.00	13,705.00	11,199.00
	बकाया	918,459.00	844,796.00	950,909.00	964,670.00	975,153.00
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91,108.00	7,063.00	8,814.00	11,517.00	7,932.00
	बकाया	618,418.00	563,115.00	645,908.00	657,425.00	665,357.00
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31,037.00	2,021.00	1,794.00	5,044.00	1,460.00
	बकाया	140,247.00	120,658.00	146,573.00	151,617.00	153,077.00
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31.00	-36.00	-31.00	-28.00	-10.00
	बकाया	3,107.00	2,943.00	3,004.00	2,976.00	2,966.00
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53.00	-6.00	-3.00	-3.00	-2.00
	बकाया	10.00	-6.00	-2.00	-5.00	-7.00
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10,967.00	1,008.00	1,121.00	1,111.00	1,133.00
	बकाया	192,658.00	186,089.00	195,547.00	196,658.00	197,791.00
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13,990.00	1,120.00	1,480.00	1,537.00	1,459.00
	बकाया	55,708.00	47,414.00	59,763.00	61,300.00	62,759.00
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25,000.00	1,983.00	3,120.00	3,045.00	2,933.00
	बकाया	124,292.00	108,621.00	132,888.00	135,933.00	138,866.00
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71,534.00	64,025.00	76,196.00	77,868.00	79,433.00
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5,910.00	5,106.00	6,178.00	6,269.00	6,359.00
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6,901.00	6,591.00	7,000.00	7,054.00	7,104.00
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39,947.00	32,899.00	43,514.00	44,742.00	45,970.00
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10,081.00	973.00	1,333.00	811.00	959.00
	बकाया	102,401.00	97,412.00	108,139.00	108,950.00	109,909.00
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	-26.00	-37.00	-25.00	-25.00	-25.00
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16,067.00	789.00	746.00	1,944.00	2,965.00
	बकाया	221,517.00	211,175.00	226,229.00	228,229.00	230,478.00
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11,318.00	542.00	-	1,165.00	2,103.00
	बकाया	98,492.00	89,037.00	100,584.00	101,749.00	103,852.00
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334.00	1.00	-104.00	-81.00	-74.00
	बकाया	263.00	261.00	-80.00	-161.00	-235.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18,678.00	-1,565.00	-1,639.00	-1,684.00	-1,344.00
	बकाया	19,303.00	31,232.00	13,828.00	12,144.00	10,800.00
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23,018.00	1,801.00	2,492.00	2,563.00	2,280.00
	बकाया	93,630.00	79,423.00	100,780.00	103,343.00	105,623.00
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93.00	10.00	-3.00	-19.00	0.00
	बकाया	2.00	-115.00	-154.00	-173.00	-173.00
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	-80.00	-80.00	-82.00	-82.00	-82.00
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9,907.00	11,417.00	11,353.00	11,409.00	10,693.00
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8,539.00	181.00	150.00	244.00	302.00
	बकाया	78,524.00	70,506.00	78,772.00	79,016.00	79,318.00

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डेटा निवल रसीदें हैं, अर्थात् सकल रसीद माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	5602830	5758103	5921026	6072243	6314426
1. वाणिज्य बैंक	41.41	40.51	40.28	39.05	39.66
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.37	0.33	0.31	0.36	0.42
3. बीमाकृत कंपनियां	24.61	24.57	24.34	24.88	24.86
4. म्यूच्युअल फंड	1.41	0.64	0.35	0.64	0.77
5. सहकारी बैंक	2.51	2.38	2.29	2.17	2.01
6. वित्तीय संस्थाएं	0.97	1.01	1.05	1.05	1.15
7. कॉरपोरेट	1.01	1.05	0.97	0.99	0.92
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.65	3.60	3.22	3.27	3.31
9. भविष्य निधियां	5.71	5.54	5.47	5.35	4.87
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	11.76	13.81	15.27	15.67	14.99
11. अन्य	6.58	6.55	6.46	6.57	7.05
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.97	2.00	2.02	1.99

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2566833	2669393	2777229	2826935	2905169
1. वाणिज्य बैंक	34.66	34.00	33.87	32.57	32.53
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.58	0.60	0.58	0.81	0.72
3. बीमाकृत कंपनियां	33.74	33.90	33.04	33.94	33.39
4. म्यूच्युअल फंड	1.05	1.23	1.20	1.24	1.12
5. सहकारी बैंक	4.75	4.67	4.55	4.65	4.24
6. वित्तीय संस्थाएं	0.43	0.37	0.42	0.44	0.33
7. कॉरपोरेट	0.17	0.22	0.29	0.32	0.28
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.10	0.09	0.09	0.08	0.05
9. भविष्य निधियां	21.04	21.29	22.15	21.88	22.36
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.48	3.64	3.81	4.08	4.98
11.1 राज्य सरकार	0.07	0.07	0.11	0.14	0.16

श्रेणी	खजाना बिल				
	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	565750	529826	412704	524618	538041
1. वाणिज्य बैंक	47.84	53.76	57.56	53.60	50.81
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.86	2.06	2.68	1.85	1.92
3. बीमाकृत कंपनियां	4.55	4.74	6.61	5.13	5.55
4. म्यूच्युअल फंड	10.69	5.65	2.78	13.00	14.08
5. सहकारी बैंक	1.20	1.21	2.48	2.54	2.55
6. वित्तीय संस्थाएं	1.67	1.88	2.49	2.14	1.82
7. कॉरपोरेट	6.67	1.86	2.23	1.67	1.57
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.02	0.08	0.07	0.01
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	25.50	28.72	23.10	19.99	21.70
11.1 राज्य सरकार	21.36	24.04	17.91	15.59	17.91

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	1	2	3	4	(सं.अ.) 5	(ब.अ.) 6
1. कुल वितरण	3285210	3760611	4265969	4515946	5516932	6071777
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
2. कुल प्राप्तियां	3189737	3778049	4288432	4528422	5364245	6003162
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	836563	952410	1064704	997097	1174823	1247962
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	26.4	29.0	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	25.6	27.4	27.9	26.5	28.2	28.5
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.2	20.0	20.4	19.8	22.1	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.2	16.7	17.1	17.4	18.5	18.5
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.8	6.2	5.9

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1565	19	876	18	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	1096	3	-	-	-	-
6	गोवा	74	12	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	365	9	155	1
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	702	27	119	14
11	झारखंड	-	-	243	9	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	330	19	877	18	688	11
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	46	16	18	1	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	72	1	-	-	-	-
19	नगालैंड	477	31	105	10	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	243	23	584	23	126	6
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1553	19	260	7	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	628	15	28	7	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक ।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2019 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7879	775	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1230	1	--	0
3	असम	4150	49	--	3000
4	बिहार	7524	--	--	0
5	छत्तीसगढ़	4213	--	1	5500
6	गोवा	567	285	--	0
7	गुजरात	13004	458	--	0
8	हरियाणा	1981	1141	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	4020	--	--	11500
13	केरल	2045	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	876	--	0
15	महाराष्ट्र	37252	405	--	15000
16	मणिपुर	360	95	--	0
17	मेघालय	584	29	9	0
18	मिज़ोरम	524	37	--	0
19	नगालैंड	1558	31	--	0
20	उड़ीसा	12759	1378	80	23395
21	पुदुचेरी	305	--	--	898
22	पंजाब	227	--	8	0
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6312	--	45	8632
25	तेलंगाना	5398	1166	1	0
26	त्रिपुरा	314	5	--	0
27	उत्तराखंड	--	--	180	0
28	उत्तरप्रदेश	3004	75	--	0
29	पश्चिम बंगाल	10503	505	214	0
	कुल	125712	7312	668	69725

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अक्तूबर		सितंबर		दिसंबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	4170	3003	4206	4206	513	222	28967	21677
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	-	-	-	-	-	-	472	472
3	असम	7760	6797	10595	8089	1000	1000	2000	2000	1900	1900	7600	7600
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	3042	2249	-	-600	-	-607	14642	11642
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	-	-	-	-700	2000	2000	4000	3300
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	200	100	200	200	300	200	1700	1200
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	3500	2000	1000	1000	2500	1500	22900	14900
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	3500	3500	-	-	2000	1000	16501	13601
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	400	400	-	-	-	-900	2000	1100
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	334	334	800	800	309	309	4992	4453
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	-	-252	-	-	500	500	2000	156
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	8200	8200	8200	6200	7700	7700	29100	24350
13	केरल	20500	16203	19500	14784	1400	550	1000	324	-	-500	14682	10706
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	-	-	1000	1000	2000	440	9000	5880
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	8000	6250	-	-	3000	3000	25500	15500
16	मणिपुर	525	278	970	667	-	-189	-	-	-	-	803	614
17	मेघालय	1116	920	1122	863	-	-124	-	-	295	295	745	521
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	100	-1	-	-	92	92	450	349
19	नगालैंड	1135	766	822	355	-	-	150	61	250	150	650	201
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	1000	1000	1000	1000	-	-	4000	4000
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	200	200	200	200	200	-300	600	100
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	2800	1100	1900	880	2035	1570	19855	11170
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	1700	430	1750	750	1000	-	26332	17250
24	सिक्किम	995	745	1088	795	-	-	-	-	-	-	451	451
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	5500	3300	8700	6700	8000	6000	45390	36190
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	3000	2166	3000	3000	1324	1116	23124	17914
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	615	465	615	615	-	-100	1680	1430
28	उत्तराखंड	41600	37178	46000	33307	9000	6524	3000	1694	5500	3922	34500	22640
29	उत्तरप्रदेश	6660	5830	6300	5289	-	-	-	-	750	750	2350	1750
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	2500	2407	6500	4169	5000	4000	33010	17700
	कुल	419100	340281	478323	348643	60161	44614	45221	33499	47168	34258	377995	268817

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम्₂ और एनएम्₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं आरआरबी को छोड़कर हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनपुगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आँकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आँकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के जनवरी 2405 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, Division of Reports and knowledge dissemination, Department of Economic and Policy Research, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, Director, Division of Reports and knowledge dissemination, Department of Economic and Policy Research, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शि कायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।